



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 58]

नई दिल्ली, बुध्दिवार, मार्च 19, 1998/फाल्गुन 28, 1919

No. 58]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 19, 1998/PHALGUNA 28, 1919

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 1998

अन्तिम जांच-परिणाम

विषय :— थाइलैंड, कोरिया गणराज्य तथा इन्डोनेशिया से पी टी ए के आयात से संबंधित पाटन रोधी जांच—अंतिम जांच परिणाम ।

14/1/96-एडीडी.— वर्ष 1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1995 और उसके सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान इन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियम, 1995 को देखते हुए :—

क. प्रक्रिया

1. नीचे वर्णित जांच-प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है :—

- (i) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने (जिसे इसके बाद प्राधिकारी कहा जाएगा) दिनांक 4 सितम्बर, 1997 की अधिसूचना के द्वारा प्रारम्भिक जांच परिणाम अधिसूचित कर दिया था और संबद्ध पक्षों से निवेदन किया गया था कि वे प्रकाशन की तिथि से 40 दिन के भीतर लिखित रूप से अपने-अपने विचार व्यक्त करें;
- (ii) प्रारम्भिक जांच परिणाम की प्रति भेजते हुए प्राधिकारी ने ज्ञात संबद्ध पक्षों से निवेदन किया था कि वे इस पत्र की तारीख से 40 दिन के भीतर प्रारम्भिक जांच परिणाम पर अपने-अपने विचार, अगर कोई हों, प्रस्तुत कर दें;
- (iii) प्राधिकारी ने प्रारम्भिक जांच परिणामों की एक-एक प्रति थाइलैंड, कोरिया गणराज्य और इन्डोनेशिया के नई दिल्ली स्थित दूतावासों को इस निवेदन के साथ भेजी थी कि निर्यातकों और अन्य संबद्ध पक्षों को प्रारम्भिक जांच परिणाम पर अपने-अपने विचार व्यक्त करने की सलाह दी जाये ;
- (iv) प्राधिकारी ने सभी संबद्ध पक्षों को दिनांक 20 अक्टूबर, 1997 को मौखिक रूप से अपने विचार रखने का मौका दिया मौखिक रूप से विचार रखने वाले सभी पक्षों से मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों को लिखित रूप में देने का अनुरोध किया गया । उनसे विरोधी पक्षों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों की प्रतियां प्राप्त करने और यदि उनका कोई खंडन हो तो उसे प्रस्तुत करने की सलाह दी गयी ।
- (v) केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 17 दिसम्बर, 1997 को नए निर्दिष्ट प्राधिकारी की नियुक्ति के बाद सभी संबद्ध पक्षों को दिनांक 20 जनवरी, 1998 के पत्र के जरिए यह सूचित करने की सलाह दी गयी कि क्या वे नियम 6(6) के अनुसार पहले से रिकार्ड किए गए अपने निवेदन

के संबद्ध में मौखिक स्पष्टीकरण देना चाहेंगे। संबद्ध पक्षों को सूचित किया गया था कि अगर वे चाहें तो अपने मामले को मौखिक रूप से स्पष्ट करने के लिए प्राधिकारी के समक्ष 10 फरवरी, 1998 को उपस्थित हो सकते हैं। मै. जे. सागर एंड एशोसिएट्स ने संबद्ध देशों से चार निर्यातकों (सैमसंग सनकियॉग, कोहप और टनटेक्स) और भारत के सभी आयातकों की ओर से मौखिक सुनवाई के अपने अधिकार को छोड़ दिया;

- (vi) प्राधिकारी ने दिनांक 10 फरवरी, 1998 को एक मौखिक सुनवाई आयोजित की। यह स्पष्ट कर दिया गया था कि सुनवाई में कोई नए मुद्दे नहीं उठाए जा सकेंगे और यह कि दिनांक 20 अक्टूबर, 1997 की सुनवाई के दौरान पेश किए गए मामलों तक ही बहस सीमित रहनी चाहिए। कोई लिखित विवरण रिकार्ड में नहीं रखे गए।
- (vii) जांच कार्य केन्द्र सरकार द्वारा विस्तारित समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया गया है। एक वर्ष की समय सीमा 19 दिसम्बर, 1997 को समाप्त हुई थी। लेकिन सरकार ने इसे तीन महीना और बढ़ा दिया था और यह बढ़ी हुई समय सीमा 19 मार्च, 1998 को समाप्त हो रही है;
- (viii) प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी साक्ष्यों के अगोपनीय अंश वाली सार्वजनिक फाइल सभी संबद्ध पक्षों को उपलब्ध कराई। जिन पक्षों ने लिखित रूप से इस फाइल के निरीक्षण का अनुरोध किया था उन सभी पक्षों को सार्वजनिक फाइल के निरीक्षण की अनुमति दे दी गई थी;
- (ix) मै.जे. सागर एंड एशोसिएट्स ने दिनांक 9 सितम्बर, 1997 के अपने फैक्स के जरिए लिखा है कि प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रारंभिक जांच-परिणामों में उसके द्वारा प्रस्तुत निर्यातकों के नामों का गलत उल्लेख किया गया है और सही नाम निम्नानुसार हैं:—

जे सागर एंड एशोसिएट्स के अनुसार सही नाम	प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक जांच परिणाम में लिखा गया नाम (जे सागर एण्ड एशोसिएट्स के अनुसार)
---	---

सनकियॉग इंडस्ट्रीज कोहप पैट्रोकेमिकल कं. लिमि.,	सनकियॉग लिमि., कोहप केमिकल कारपोरेशन
---	--------------------------------------

प्राधिकारी ने नोट किया कि इन निर्यातकों के सही नाम उनके द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर सनकियॉग इंडस्ट्रीज लिमि. और कोहप पैट्रोकेमिकल कारपोरेशन हैं और प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणाम में इन्हीं का उल्लेख किया था।

- (x) प्रारंभिक जांच परिणाम घोषित करने से पूर्व संबद्ध द्वारा रखे गए तर्कों को जिन्हें अधिसूचित प्रारंभिक जांच परिणाम में शामिल किया गया है, यहां संक्षिप्तता के प्रयोजन से नहीं दोहराया गया है। तथापि, संबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों पर प्रारंभिक जांच परिणाम में और/या इन जांच परिणामों में समुचित रूप से विचार किया गया है।
- (xi) संबद्ध पक्षों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों की जांच को इस रिपोर्ट में तिरछे शब्दों के रूप में दिखाया गया है।

ख. याचिकाकर्ता के विचार

2. याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित मुद्दे उठाए हैं:

(क) जांच अवधि के दौरान आयातित पी टी ए की मात्रा उस न्यूनतम निर्धारित आयात स्तर से ज्यादा है, जो जांच योग्य तथा शुल्क लगाए जाने योग्य है।

(ख) आर आई एल को घरेलू उद्योग की परिभाषा से बाहर कर देने की स्थिति में और जब तुलना के लिए कोई समान उत्पाद नहीं हो तो मौजूदा मामले में समान उत्पाद की परिभाषा का दूसरा भाग लागू होगा।

(ग) किसी हितबद्ध पक्ष ने यह विवाद नहीं खड़ा किया कि पॉलिस्टर या तो पी टी ए से या डी एम टी से बनाया जा सकता है। समान उत्पाद के निर्धारण के लिए प्रतिस्थापन क्षमता एक सर्वमान्य मानदंड है। यह भी अविवादित है कि पी डी एम टी की कीमत का पी टी ए की कीमत से सीधा संबंध है। डी एम टी एवं पी टी ए के बीच वाणिज्यिक समानता है। इसलिए डी एम टी एवं पी टी ए नियमों की परिभाषा के अन्तर्गत समान उत्पाद हैं।

(घ) आर आई एल ने कहा है कि उसके पी टी ए संयंत्र ने वर्ष 1997 की प्रथम तिमाही में उत्पादन शुरू किया और उसके बाद कंपनी ने पी टी ए का आयात करना बंद कर दिया। कंपनी ने आगे तर्क दिया है कि चूंकि जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है, इसलिए इसे मौजूदा जांच के प्रयोजन से घरेलू उद्योग माना चाहिए।

(ङ.) निर्यातकों ने निर्यातों से जुड़े कई व्यय किए जैसे कि समुद्री भाड़ा, मूल्य में रियायत, पत्तन पर जांच शुल्क, अन्तर्देशीय भाड़ा आयातकों को दिए गए ऋण पर ब्याज उतराई शुल्कों के बिल, उच्च पैकिंग के निर्यात इत्यादि पर किया गया व्यय। निर्यात मूल्य में इन खर्चों के लिए समायोजन किए जाने पर पाटन सीमा 2.5% से 18% तक बैठती है। लागत पर आधारित सामान्य मूल्य का निर्धारण करने की दशा पर भी पाटन होने का पता चलता है जिससे डमियंग मार्जिन 10% से 30% बैठता है।

(च) घरेलू बिजली के लिए निर्यातकों द्वारा दावा किए गए सौदेबाजी शुल्क की जांच साधनीपूर्वक करने की आवश्यकता है।

(छ) कोहप द्वारा डम्पिंग के संबंध में किए गए दावे की भी बहुत सावधानीपूर्वक परीक्षण की जरूरत है। यह तर्क कि कोहप दूसरों की अपेक्षा पी टी ए की बिक्री अपने घरेलू बाजार में बहुत कम कीमत पर कर रहा है, इस बात का परिचायक है कि कोहप कोरिया में पी टी ए का अत्यधिक प्रतिस्पर्धी आपूर्तिकर्ता हो गया है। कोरिया में दूसरे उत्पादक ऐसी हालत में टिक नहीं सकते खासकर तब जब कोरिया पी टी ए का बेसी बाजार है।

(ज) आर आई एल का तर्क था कि हालांकि उत्पादन लागत की गोपनीयता का दावा किया जा सकता है, लेकिन किसी निर्यातक द्वारा इसकी कीमत और इसमें समायोजनों की गोपनीयता का दावा नहीं किया जा सकता है। कंपनी ने अनुरोध किया कि ऐसी सूचना उन्हें भी उपलब्ध कराई जाए।

(झ) पी टी ए की डम्पिंग के परिणामस्वरूप भारत में पी टी ए का मूल्य 57000 रु. प्रति मी. टन से घटकर 37000 रु. प्रति मी. टन हो गया। भारतीय बाजार में पी टी ए की कीमत में गिरावट का एकमात्र कारण पी टी ए का बढ़ी मात्रा में पाटन करना था।

(ञ) पाटनरोधी शुल्क केवल तत्काल प्रभाव से ही नहीं लगाया जाना चाहिए अपितु कम से कम 4-9-1997 से लगाया जाना चाहिए, जब सक्षम प्राधिकारी इस निर्णय पर पहुँचे थे कि शुल्क लगाना आवश्यक है।

(ट) कोहप द्वारा दावा किया गया सामान्य मूल्य पैराक्सीलिन (जिसे इसके बाद पी एक्स कहा जाएगा) की प्रचलित कीमतों को देखते हुए वास्तविक नहीं लगता है।

(ठ) जांच अवधि के पश्चात् कोरिया से पी टी ए का आयात 515 अमरीकी डालर प्रति मी. टन की कीमत पर किया गया है।

(ग) निर्यातकों, आयातकों और अन्य संबद्ध पार्टियों के विचार

विचाराधीन उत्पाद, समान उत्पाद, घरेलू उद्योग, पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध पर आयातकों और निर्यातकों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों पर संबद्ध पैरा में नीचे विचार किया गया है। उनके द्वारा व्यक्त किए गए अन्य विचार संक्षेप में नीचे दिए गए हैं :

(क) प्रतिपाटन शुल्क को लगाने से पर्याप्त निवेशों और रोजगार से जुड़े बहुत से पालीस्टर एकक प्रभावित होंगे।

(ख) पी टी ए पर प्रतिपाटन शुल्क लगाने से भारत में पी एस एफ, पी एफ वाई पी ई टी रेजिन और फिस्मों का पाटन शुरू हो जाएगा।

(ग) आर आई एल के प्रतिनिधि ने मौखिक अनुरोध के समय घरेलू उद्योग की ओर से अनुरोध किया। चूंकि आर आई एल ने पी टी ए का आयात किया था, इसलिए उसकी याचिका को प्राधिकारी ने स्वीकार नहीं किया। आर आई एल को समूचे मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था और फिर भी उनको अनुरोध करने की स्वीकृति दी गयी। प्राधिकारी को अंतिम जांच परिणाम बनाने में उसके किसी अनुरोध पर विचार नहीं करना चाहिए।

(घ) प्राधिकारी द्वारा जांच

याचिकाकर्ताओं, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुरोधों की जांच की गई, उन पर विचार किया गया और जहां उपर्युक्त समझा गया उन पर आगे विचार किया गया है।

(ङ.) विचाराधीन उत्पाद, समान उत्पाद और घरेलू उद्योग

5. मौजूदा जांच में विचाराधीन उत्पाद प्यूरीफाइड टैरीफ्यूलिक एसिड है (जो पी टी ए के रूप में भी जाना जाता है और जिसे इस रिपोर्ट में पी टी ए के रूप में उद्धृत किया जाएगा)। विचाराधीन उत्पाद पर कोई विवाद नहीं है और, इसलिए, प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद के संदर्भ में प्रारंभिक जांच परिणामों की पुष्टि कर सकते हैं।

समान उत्पाद के संदर्भ में यह तर्क दिया गया कि अगर घरेलू उद्योग की परिभाषा में समान उत्पाद की परिभाषा को समाहित कर लिया जाता है तो यह देखा जा सकता है कि "घरेलू उद्योग" शब्द का दायरा उन घरेलू उत्पादकों के संदर्भ में ही निर्धारित होगा जो जांच के अधीन उत्पाद के समान वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। ऐसे उत्पाद के न होने पर ही परिभाषा का दूसरा पहलू प्रभाव में आएगा। पी टी ए का उत्पादन करने वाला एक घरेलू उत्पादनकर्ता है और दोनों ही सभी दृष्टिकोण से सदृश या समान हैं। आर आई एल को अयोग्य ठहराना अव्यावहारिक है क्योंकि यह घरेलू उत्पादकों को आयात करने और पाटित उत्पादों के लाभों का फायदा उठाने से वंचित करता है और इसके साथ साथ उक्त उत्पाद के विरुद्ध कार्रवाई करता है घरेलू उद्योग शब्द की दूसरे किसी प्रकार से व्याख्या करना व्याख्या के अधीन नियमों के सभी स्थापित कानूनों के विरुद्ध होगा। आगे यह भी तर्क दिया गया है कि प्राधिकारी का इस प्रयोजन से दिया गया तर्क भ्रामक है। यह कोई ऐसा मामला नहीं है कि इसमें समान उत्पाद का उत्पादन करने वाला कोई घरेलू उत्पादनकर्ता नहीं है यहाँ समान उत्पाद का उत्पादन करने वाला घरेलू उद्योग मौजूद है किन्तु वैधानिक परिभाषा के परिप्रेक्ष्य में इसे अयोग्य माना गया है। प्राधिकारी द्वारा की गई व्याख्या से किसी वैधानिक नियम का उल्लंघन नहीं होता है।

प्राधिकारी यह नोट कर सकते हैं कि जांच कथित पाटित उत्पाद अर्थात् विचाराधीन उत्पाद के लिए की जा रही है। विचाराधीन उत्पाद का निर्धारण करने के बाद प्राधिकारी को समान उत्पाद का निर्णय करना होता है। समान उत्पाद का निर्णय घरेलू उद्योग के संदर्भ में किया जाना है। इसलिए समान शब्द का निर्णय घरेलू उद्योग के संदर्भ में किया जाना है इसलिए घरेलू शब्द का दायरा समान उत्पाद का उत्पादन कर रहे घरेलू उद्योग के संदर्भ में परिभाषित किया जाना है।

7. याचिकाकर्ता और घरेलू उद्योग :

याचिका दर्ज करने के संबंध में याचिकाकर्ताओं के आधार पर उठाए गए विवाद और घरेलू उद्योग का दायरा क्षेत्र निम्नानुसार है :—

(क) आर आई एल द्वारा किए गए आयात उसके अपने पी टी ए के उत्पादन की तुलना में नगण्य है और तकनीकी आधार पर आवेदन को अस्वीकार करना सही नहीं है। पी टी ए उत्पादकों को हुई छानि यदि कोई हो, पर शुल्क की सिफारिश करते समय विचार किया जाना चाहिए था। चूंकि पी टी ए का कोई अन्य उत्पादक नहीं था इसलिए जांच को खत्म कर देना चाहिए था।

(ख) घरेलू पी टी ए उत्पादक को बाहर रखना उचित तर्क पर आधारित नहीं है।

(ग) चूंकि पी टी ए के एकमात्र उत्पादक को घरेलू उद्योग के रूप में अयोग्य करार दिया गया है, इसलिए जांच को खत्म कर देना चाहिए था।

प्राधिकारी यह नोट कर सकते हैं कि यह कहना पूर्णतः गलत है कि आर आई एल का मौजूदा जांच में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। आर आई एल मौजूदा जांच में एक याचिकाकर्ता है और वह मौजूदा जांच में एक प्रभावित पक्ष के रूप में भागीदारी करने का हकदार है यह तथ्य कि आर आई एल को घरेलू उद्योग की परिभाषा से बाहर रखा गया है उसे एक याचिकाकर्ता होने से वंचित नहीं कर सकता है और न ही इससे समुचित निदान चाहने की उसकी अधिकारिता समाप्त होती है। इसलिए, आर आई एल द्वारा जो तर्क दिए गए हैं उन पर उसी सीमा तक विचार किया गया है जहां तक ये संगत, आवश्यक, उचित और सही हैं।

8. आर आई एल के इस तर्क के संदर्भ में उसने जांच अवधि के पश्चात् पी टी ए का आयात करना बंद कर दिया है और चूंकि जांच पूरी नहीं हुई है, इसलिए उसे अब घरेलू उद्योग के रूप में माना जाए, प्राधिकारी यह नोट कर सकते हैं कि मौजूदा जांच के प्रयोजन के लिए जो संगत कारक हैं वही कारक जांच अवधि से जुड़े कारक भी हैं। चूंकि आर आई एल ने पी टी ए का जांच अवधि के दौरान आयात किया था इसलिए इस समय घरेलू उद्योग के दायरे को बदलना उचित नहीं होगा।

9. पूर्ववृत्तान्त के आलोक में, प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद, समान उत्पाद और घरेलू उद्योग के संदर्भ में प्रारंभिक निष्कर्षों की अधिसूचना के पैरा 8 से 14 में प्रारंभिक निष्कर्षों की पुष्टि कर सकते हैं और इस बात की भी पुष्टि कर सकते हैं कि मौजूदा जांच के प्रयोजन के लिए बी डी एम सी घरेलू उद्योग बनता है और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित माल विचाराधीन उत्पाद के समान है।

(घ) पाटन:—

10. इच्छुक पार्टियों द्वारा पाटन पर उठाई गई आपत्तियां इस प्रकार हैं:—

(क) मै. पैटिमिनो, पी.टी. एमोबो मित्सुई पी.टी. ए. इंडोनेशिया, (सियम मित्सुई) पी.टी.ए. कं. लि. और सेमसंग जनरल केमिकल्स कं. लि. (यहां एस.जी.सी. के. रूप में भी उल्लेख किया गया है) ने दावा किया कि वे न तो जांच-अवधि के दौरान पी.टी.ए. का उत्पाद कर रहे थे और न ही उन्होंने भारत को पी.टी.ए. को निर्यात किया था इन कम्पनियों ने उपयुक्त नियमों के नियम 22 के अनुसार बाहर रखने का दावा किया।

प्राधिकारी के विचार:—

प्राधिकारी टिप्पणी करते हैं कि चूंकि इन कम्पनियों ने दावा किया है कि उन्होंने न तो पी.टी.ए. का उत्पादन किया है और न ही जांच-अवधि के दौरान उसका भारत को निर्यात किया है, इसलिए उन पर नियम 22 लागू होता है। पैटिमिनो के अलावा सभी कम्पनियों ने नियम 22 के अन्तर्गत पृथक् रूप से याचिका दायर की है, जिन पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जा रहा है।

11. पाटन-निर्धारण के विषय में अपनाई गई प्रणाली और प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक-निष्कर्षों में दावों पर दी गई अनुमति पर यहां नीचे विचार किया गया है। मासिक आधार पर निर्यात-कीमतों से सामान्य मूल्यों की तुलना जिसकी नीचे अलग से जांच की गई है, के अलावा किसी भी इच्छुक पार्टी द्वारा अपनाई गई प्रणाली के विषय में कोई आपत्ति नहीं उठाई गई है। पाटन-निर्धारण के लिए अपनाई गई प्रणाली के विषय में प्राधिकारी प्रारंभिक निष्कर्षों की पुष्टि करते हैं।

12. प्रारंभिक निर्धारण के समय प्राधिकारी द्वारा समायोजनों के लिए दी गई अनुमति और कीमत-समायोजन के विषय में प्रारंभिक निष्कर्षों के समक्ष इन निर्यातकों द्वारा किए दावों पर संक्षिप्तता के कारण इन निष्कर्षों में विचार नहीं किया जा रहा है। प्राधिकारी द्वारा अनुमति समायोजन अब इन अन्तिम निष्कर्षों के लिए हैं और इसके कारणों पर नीचे चर्चा की गई है।

13. प्राधिकारी द्वारा नियुक्त अधिकारियों के एक दल ने चारों सहयोगी निर्यातकों के परिसरों की विस्तृत जांच-पड़ताल की थी।

1. सैमसंग पेट्रोकेमिकल कं. लि. (सैमसंग):—

15. सैमसंग ने दावा किया कि इसने एक असंबद्ध पार्टी के माध्यम से पी.टी.ए. का निर्यात किया है तथापि, यह पाया गया है कि कम्पनी ने सैमसंग कार्पोरेशन को अपना माल बेचा, जिसने बदले में भारत को संबंधित वस्तुओं का निर्यात किया। प्राधिकारी के पास इस बात का सबूत है सैमसंग एशिया प्रा. लि. द्वारा "सैमसंग कार्पोरेशन" के परामर्श पर भारत को माल का निर्यात किया गया, जो सैमसंग पेट्रोकेमिकल, द्वारा प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। इसलिए कम्पनी का यह दावा कि सैमसंग पेट्रोकेमिकल न तो सैमसंग कार्पोरेशन और न ही सैमसंग एशिया प्रा. लि. से संबंधित है और वे कीमतों जिन पर सैमसंग पेट्रोकेमिकल द्वारा इन कम्पनियों को माल बेचा गया है, उन कीमतों का प्रतिवेदन करती हैं, जिन पर सामान्य व्यापार अवधि में कम्पनी द्वारा माल निर्यात किया गया है। परन्तु यह सुझाव देने के लिए पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध हैं कि सैमसंग, पेट्रोकेमिकल द्वारा सैमसंग कार्पोरेशन द्वारा की गई

बिक्रीयों पर सामान्य व्यापार अवधि में बिक्री के रूप में विचार नहीं हो सकता। उदाहरणार्थ प्रकाशित पुस्तिका (ब्रोशर) समूचे ग्रुप के समेकित आंकड़े दर्शाती है, जहां सैमसंग कार्पोरेशन और सैमसंग पेट्रोकेमिकल के (टर्न ओवर) को ग्रुप के कारोबार (टर्न ओवर) के अन्तर्गत दर्शाया गया है। अतः प्राधिकारी निर्यातक द्वारा किए गए निर्यात कीमत के दावे को गलत बताते हैं।

संबंधित देशों से पी.टी. ए. के आयातों के संबंध में आयातकर्ताओं/आयातकों द्वारा दी गई सूचना का उस कीमत के सह-संबंध की दृष्टि से, जिस पर सैमसंग पेट्रोकेमिकल द्वारा सैमसंग कार्पोरेशन को माल का बीजक बनाया गया था, का विश्लेषण किया गया था। आयातों ने सी.एण्ड एफ. कीमतें दी हैं, जिन पर उनके द्वारा माल खरीदा गया है, जिसे सैमसंग कार्पोरेशन द्वारा निर्यात किया गया था। प्राधिकारी के पास उपलब्ध इन ब्यौरो के आधार पर निर्यात कीमत मानी गई है।

कीमत समायोजनों के विषय में, क्योंकि भारत को निर्यातों पर सैमसंग कार्पोरेशन द्वारा उठाए गए अन्तर्देशीय भाड़ा समुद्री भाड़ा, विपणन, प्रशासनिक और सामान्य लागत (एस.जी.ए.) जैसे खर्चों के ब्यौरे सैमसंग पेट्रोकेमिकल द्वारा या सैमसंग कार्पोरेशन द्वारा किसी ने भी प्राधिकारी को प्रस्तुत नहीं किए हैं। प्राधिकारी कोरिया जनवादी गणराज्य अर्थात् को है या और सन्ध्यों से अन्य सहयोगी निर्यातकों द्वारा उठाए गए औसत खर्चों के आधार पर निर्यात कीमत से समायोजनों की अनुमति देने उपयुक्त समझते हैं। चूंकि, एस.जी.ए. खर्चों के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है इसलिए निर्यात कीमत 3% तक घटाना ही उपयुक्त समझा गया है, जो कमीशन है, जो कि कम्पनी द्वारा अन्यथा देय होता, क्योंकि इसे कुछ अन्य कम्पनी के माध्यम से निर्यात किया था।

(ii) संख्योग इण्डस्ट्रीज लि. (संख्योग) .

16. प्राधिकारी ने निर्यात के परिसरों में किए गए विस्तृत सत्यापन की दृष्टि से निर्यातक द्वारा किए गए सभी समायोजनों के दावे को अनुमति दे दी है।

(iii) कोहप पेट्रोकेमिकल कार्पोरेशन:

घरेलू बाजार में बिक्री कीमतों के संबंध में स्थल-सत्यापन के समय यह पाया गया है कि कोहप कोरिया जनवादी गणराज्य में अंतिम खपत के लिए कोरिया जनवादी गणराज्य की संबद्ध कम्पनी को बिक्री करती रही है। इस संबद्ध कम्पनी को बिक्री के समय घरेलू बाजार में कम्पनी की कुल बिक्री के करीब 84% को ध्यान में रखा गया है। नियमों के अन्तर्गत प्राधिकारी को ऐसी परिस्थितियों में कीमतों को निर्धारित करने की जरूरत होती है जिन पर संबद्ध कम्पनी ने कोरिया जनवादी गणराज्य में पहली असम्बद्ध कम्पनी को माल बेचा। परन्तु वर्तमान मामले में संबद्ध पार्टी ने माल की खपत की और इसलिए संबद्ध पार्टी की कीमत पर विचार नहीं किया जा सकता।

इसलिए, प्राधिकारी ने कोहप द्वारा इसकी संबद्ध कम्पनी को की गई बिक्री पर ध्यान नहीं दिया और कोरिया जनवादी गणराज्य में अन्य ग्राहकों को की गई बिक्री के आधार पर बिक्री की कीमतें निर्धारित की। प्राधिकारी टिप्पणी करते हैं कि अन्य असम्बद्ध कम्पनियों द्वारा की गई बिक्रियां काफी हैं और इन पर कोरिया जनवादी गणराज्य में बिक्री कीमतों के प्रतिनिधि के रूप में विचार किया जा सकता है।

प्राधिकारी ने कम्पनी द्वारा सभी मूल्य समायोजनों के लिए किए गए दावों की अनुमति दे दी है।

(iv) टंटेक्स पेट्रोकेमिकल्स (थाइलैण्ड) पब्लिक कम्पनी लि.; (टंटेक्स):

21. टंटेक्स के परिसरों में किया गया विस्तृत सत्यापन यह उजागर करता है कि कम्पनी द्वारा घरेलू बाजार में बिक्री के मामले में किए गए अन्तर्देशीय भाड़े का दावा कम्पनी द्वारा उठाए गए वास्तविक खर्चों पर आधारित नहीं है और वे काल्पनिक खर्चें थे। कम्पनी ने अन्तर्देशीय भाड़े के कारण *** के का औसत खर्च उठाया है जिसका कम्पनी द्वारा *** के रूप में दावा किया गया। प्राधिकारी ने कम्पनी द्वारा उठाए गए वास्तविक अन्तर्देशीय भाड़े के आधार पर अन्तर्देशीय भाड़े की अनुमति दी है। प्राधिकारी ने निर्यातक द्वारा दावा किए गए सभी अन्य कीमतों के समायोजनों की अनुमति दे दी है।

(v) इंडोनेशिया से निर्यातक

23. प्रारंभिक जांच के बाद भी इंडोनेशिया में पेरटामीना के अतिरिक्त किसी निर्यातक से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। क्योंकि जांच अवधि के दौरान पेरटामीना ने भारत का कोई पी टी ए निर्यात नहीं किया है, यह मामला नियम 22 के तहत आता है तथा पाटन एवं पाटन मार्जिन के निर्धारण हेतु इस पर विचार नहीं किया जा सकता है। अतः प्राधिकारी ने इंडोनेशिया के मामले में प्रारंभिक जांच में किए गए अंतिम निर्धारण के अनुसरण में कार्य किया है। प्राधिकारी ने इंडोनेशिया से निर्यातकों के मामले में पाटन के निर्धारण के संबंध में प्रारंभिक निष्कर्ष की पुष्टि की है।

24. सामान्य मूल्य की निर्यात कीमत से तुलना के संबंध में यह तर्क दिया गया है कि जहां तक प्राधिकारी द्वारा सामान्य मूल्यों तथा निर्यात कीमतों की मासिक औसत के आधार पर सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत के बीच तुलना की गई है, अतः प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक निष्कर्ष में पाटन सीमा का निर्धारण करना गलत है। इच्छुक पार्टियों ने तर्क दिया है कि संसार भर में पाटन सीमा का निर्धारण केवल भारत औसत के आधार पर किया जाता है तथा प्राधिकारी द्वारा भी अब तक सभी मामलों में ऐसा ही किया गया है। पार्टियों ने तर्क दिया है कि सौदा दर सौदा प्रक्रिया केवल असाधारण परिस्थितियों में अपनाई जाती है जैसा कि जब मरकन्डाइज्ड माल की बहुत कम बिक्री हो। इस नियम के तहत, प्राधिकारी जांच अवधि के लिए केवल भारत औसत सामान्य मूल्य तथा भारत औसत निर्यात कीमत के आधार पर पाटन मार्जिन का निर्धारण कर सकता है। प्रारंभिक निष्कर्ष में प्राधिकारी द्वारा तुलना के संबंध में दिए गए निष्कर्ष प्राधिकारी द्वारा दी गई इस धारणा से नहीं निकलते हैं कि घरेलू बाजार में कीमतें तथा भारत को निर्यात घट रहे थे। यह भी तर्क दिया गया है कि जहां बाजार मूल्यों को वृद्धि अथवा कमी दोनों साथ-साथ दृष्टिगत होती है वहां भारत औसत ऐसे उतार चढ़ाव में समायोजित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त पाटन सीमा का महीने दर महीने आधार पर निर्धारण कानून द्वारा अनुमत नहीं है।

प्राधिकारी की स्थिति

25. प्राधिकारी ने नोट किया है कि तुलना के संबंध में उपरोक्त तर्क तथ्यपरक वैचारिक तथा कानूनी रूप से गलत हैं। प्राधिकारी ने "भारित औसत आधार" पर पाटन मार्जिन भी निर्धारित किया है। तथापि, जांच की अवधि में सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमतों के भारत औसत का प्रत्येक महीने के लिए निर्धारण किया गया है। प्राधिकारी ने जांच अवधि के दौरान सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत दोनों में आई महत्वपूर्ण गिरावट कुछ निर्यातकों द्वारा कुछ महीनों में घरेलू बाजार या भारत को निर्यात में हुई शून्य बिक्री को ध्यान में रखते हुए तुलना की है।

प्राधिकारी द्वारा यह नोट किया गया कि कुछ महीनों में बहुत अधिक बिक्री हुई थी जबकी अन्य कुछ महीनों में भारत को कोई निर्यात नहीं किया गया था।

पूरी जांच अवधि के लिए सामान्य मूल्य के भारत औसत आधार पर निर्धारण करना जहां जांच की अवधि में कुछ महीनों में कोई निर्यात नहीं हुआ है तथा जांच अवधि में महीने दर महीने आधार पर निर्यात कीमतों में काफी गिरावट आई है वहां भारत औसत सामान्य मूल्य की निर्यात कीमत (जो कि जांच की अवधि में केवल कुछ महीनों में हुई बिक्री को दर्शाती है) से तुलना करना अनुचित, गलत और भ्रामक भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में जहां जांच की अवधि में केवल एक महीने में भारत को निर्यात किया गया है जैसे अक्टूबर, 1996 तथा जांच अवधि में कीमतों में गिरावट आई है, जैसा कि इस मामले में हुआ है, तुलना हेतु भारत औसत आधार पर निकाले गए परिणाम काफी भ्रामक हो सकते हैं परिणामस्वरूप वहां मार्जिन का निर्धारण कर दिया गया हो जहां कोई पाटन ही न हुआ हो। इसके विपरीत भी ठीक है। उदाहरणार्थ घरेलू बाजार में अप्रैल, 1996 में महीने में कौहैप का बिक्री मूल्य अब अगले महीने (मई, 1996) में $\times\times\times$ की तुलना में $\times\times\times$ पी एम टी आंका गया है। अप्रैल, 1996 के महीने में भारत को कोई निर्यात नहीं किया गया है। अगर प्राधिकारी ने एकल भारत औसत सामान्य मूल्य का उपयोग किया होता तो अप्रैल, 1996 माह के लिए बिक्री मूल्य ने कौहैप का सामान्य मूल्य बढ़ा दिया होता जबकि भारत को कोई निर्यात नहीं किया गया था। इससे पाटन मार्जिन अधिक हो सकता था जबकि यह वास्तविकता नहीं है। ऐसी स्थिति में पूरी जांच अवधि के लिए एकल औसत के बजाए माह दर औसत के आधार पर तुलना अधिक उचित है, तथा वास्तव में, निर्यातकों के हित में है। इसके अलावा, अलग-अलग निर्यातकों के संबंध में भिन्न तुलना प्रक्रिया अपनाया उचित नहीं होगा। फिर, यह किसी भी इच्छुक पार्टी (यों) द्वारा नहीं दर्शाया गया है कि सामान्य मूल्य की निर्यात कीमत से माह-दर आधार पर की गई तुलना में गलत सिद्ध हुई है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी पाटन (सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा तुलना) के संबंध में प्रारंभिक जांच की पुष्टि करते हैं। पाटन मार्जिन निम्नानुसार है :—

देश/निर्यातक का नाम	डपिंग मार्जिन (डपिंग मार्जिन का %)
कोरिया जनवादी गणराज्य के संबंध में	
(क) सैमसंग पैट्रोकेमिकल्स क. लिमि०	9.25
(ख) सन कार्यांग इंडस्ट्रस लिमि०	9.63
(ग) कोहैप पैट्रोकेमिकल्स कोपोरेशन	6.65
थाईलैंड के संबंध में	
टुनटैक्स पैट्रोकेमिकल्स (थाईलैंड) पब्लिक कम्पनी लि.	9.43
इंडोनेशिया के संबंध में	14.97

क्षति

26. प्रति पाटन शुल्क की सिफारिशों का विरोध करने वाली इच्छुक पार्टियों द्वारा उठाए गए तर्क इस प्रकार हैं :—

27. सम्पूर्ण क्षति का विश्लेषण डी एम टी के उत्पादकों के संदर्भ में किया गया है। शुल्कों की सिफारिश पी टी ए के आयातों पर की गयी है जो कि अयोग्य घरेलू उद्योग के एक मात्र लाभ है। ऐसा प्रतीत होता है कि जांच की शुरुआत केवल एक अयोग्य घरेलू उत्पादक का पक्ष लेने के लिए की गई है। अगर पी टी ए उत्पादकों को हुई क्षति का विश्लेषण किया गया होता तो निष्कर्ष कुछ अलग ही होते। उपरोक्त तर्क, घरेलू उद्योग के दायरे को देखते हुए तर्क संगत नहीं है जैसा कि घरेलू उद्योग से संबंधित उपरोक्त पैरा में परिभाषित किया गया है। पी टी ए के एकमात्र उत्पादक को हुई क्षति के संदर्भ में जो तर्क दिया गया है वह अनुमानित है और इसके समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

28. डी एम टी घरेलू उद्योग को हुई क्षति और कार्य-कारण संबंधों को केवल उन आयातकों के संदर्भ में देखा जाना है जिनके पास पी टी ए और डी एम टी के उपयोग की सुविधा है चूंकि बी डी एम सी ने प्रथम दृष्टया आधार पर यह स्थापित नहीं किया है कि उसे उन आयातकों द्वारा, पी टी ए का आयात करने के फलस्वरूप क्षति हुई है जो पी टी ए और डी एम टी दोनों का उपयोग कर सकते हैं, इसलिए जांच को खत्म करने की आवश्यकता है।

29. प्रारंभिक निष्कर्षों में गंभीर मतभेद हैं। उन घरेलू उद्योग को कोई वास्तविक क्षति नहीं है जो 100% क्षमता उपयोग पर कार्य करते हुए अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। बी डी एम सी 95% क्षमता उपयोग पर कार्य कर रहा है और वह सतत मुनाफा कमा रहा है।

30. बी डी एम सी संयंत्र 15-5-1996 से 15-6-1996 तक रसायनिक रिसाव के कारण बंद था जिसके कारण उत्पादन में 14000 मी. टन का नुकसान हुआ था। याचिकाकर्ता द्वारा कम क्षमता उपयोग का दावा सही नहीं है।

31. बी डी एम सी ने पैरेक्सिलीन (पी एक्स) की खरीद प्रचलित कम नकद मूल्य की तुलना उच्च संविदा मूल्य पर की है।

32. प्राधिकारी ने समूची क्षति का विश्लेषण पी एस एफ विनिर्माताओं द्वारा पी टी ए और डी एम टी के घरेलू स्रोतों और आयात के बारे में संगत एवं मौलिक कारकों को ध्यान में रखे बिना किया है। इस प्रयोजन से उठाए गए तर्कों पर प्राधिकारी ने कोई निष्कर्ष नहीं दिया है।

उपर्युक्त दावा वस्तुतः गलत है। प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणामों में यह स्थापित किया है कि घरेलू उद्योगों को क्षति पीटित मूल्यों पर पी टी ए के आयातों के कारण हुई है, बिना इस तथ्य पर ध्यान दिए कि क्या आयातक डी एम टी का उपयोग कर सकता है या नहीं। और इस प्रारंभिक जांच परिणाम के पैरा में भी उद्धृत किया गया है।

33. पी टी ए के कम आयात मूल्य को देखते हुए यदि डी एम टी की कीमतें कम रखी जानी थी तो यह आर आई एस को भी इसका सामना करना चाहिए था। आर आई एल द्वारा प्रकाशित वित्तीय परिणामों से कम बिक्री होने या कम लाभ होने का पता नहीं चलता है।

जैसा कि प्रारंभिक जांच परिणाम के पैरा में बताया गया है बी डी एम सी को पाटित मूल्यों पर पी टी ए का आयात करने से वास्तविक क्षति हुई है, बिना इस बात पर ध्यान दिए कि आयात डी एम टी का उपयोग कर सकता है या नहीं। पैरा में प्राधिकारी के निष्कर्षों पर कोई विवाद नहीं है। आर आई एल द्वारा कम बिक्री के बारे में दिया गया तर्क अनुमानित है और आई एल द्वारा अर्जित लाभों के संबंध में दिए गए तर्क को अनदेखा किया जा सकता है क्योंकि यह आर आई एल द्वारा अनेक उत्पादनों से अर्जित औसत लाभों से संबंधित है। इसलिए यह तर्क अस्वीकार्य है।

34. प्राधिकारी ने पी टी ए की बढ़ी हुई खपत के कारणों का विश्लेषण नहीं किया है। उत्पादन और क्षमता उपयोग के बारे में जांच परिणामों को स्थापित 20,000 मी. टन तक स्थापित क्षमता उपयोग में वृद्धि के संदर्भ में देखा जा सकता है। यद्यपि याचिकाकर्ता मांग की स्थिति को देखते हुए मौजूदा क्षमता का उपयोग नहीं कर सका।

प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणामों में कम क्षमता उपयोग अथवा उत्पादन में कमी को बी डी एम सी को हुई क्षति का कारण नहीं माना है। प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणामों में यह निर्धारित करने के लिए कि क्या घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है, इन कारकों का केवल विश्लेषण किया है। हितबद्ध पक्ष पाटन और वास्तविक क्षति के बीच और वास्तविक क्षति तथा कार्य कारण संबंध के बीच अंतर करने में असफल रहे हैं।

35. प्रारंभिक जांच परिणामों के पैरा 36 और 37 में उद्धृत बिक्री वसूली और उत्पादन लागत में गिरावट के संबंध में प्राधिकारी ने सीमा शुल्क में कमी के कारण बिक्री वसूली में गिरावट आने पर विचार नहीं किया है।

यह तर्क विधि संगत नहीं है। यद्यपि यह मान भी लिया जाये कि बिक्री वसूली में गिरावट आने का एक मात्र कारण कम सीमा शुल्कों के फलस्वरूप उत्तराई लागत में गिरावट है, कानूनी तौर पर याचिकाकर्ताओं को क्षति-पूर्ति की मांग करने से कोई नहीं रोक सकता है।

36. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू हुई क्षति के संबंध में प्रारंभिक निष्कर्ष, घरेलू उद्योग को प्रभावित करने वाले किसी एक पैरामीटर जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोगिता, बिक्री, बिक्री मूल्य स्टॉक, लाभप्रदता इत्यादि पर आधारित नहीं। प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणामों में स्पष्ट रूप से माना है कि घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न संकेतक सामूहिक एवं संचयी तौर से यह स्थापित करते हैं कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। इच्छुक पक्षों का यह तर्क कि घरेलू उद्योग को कुछ संघटनों के कारण क्षति नहीं हुई है, अनदेखा किया जा सकता है।

37. पूर्ववृत्तान्त को देखते हुए प्राधिकारी घरेलू उद्योग को हुई क्षति से संबंधित प्रारंभिक निष्कर्षों की पुष्टि कर सकते हैं।

कार्य-कारण संबंध

38. इच्छुक पार्टियों द्वारा उठाया गया सह तर्क कि पी टी ए का आयात पाटन के अतिरिक्त किन्ही और कारणों से बढ़ा है, प्रशंसनीय है। घरेलू उद्योग को हुई क्षति को क्षति का निर्धारण करने वाले सिद्धांतों के संदर्भ में देखा जाना है। क्षति के बारे में प्राधिकारी के निष्कर्षों का तात्पर्य यह नहीं है कि जिन

तथ्यों को आधार मान कर क्षति की जांच की है, उनके आधार पर प्राधिकारी ने यह पाया कि घरेलू उद्योग को पाटित आयात के कारण वास्तविक क्षति हुई है। प्राधिकारी ने प्रारंभिक निष्कर्षों में यह नहीं माना है कि वस्तु देशों से आयातों में हुई वृद्धि या घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन क्षमता उपयोगिता आदि में कमी करने जैसे कारक यह स्थापित करते हैं कि घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति पाटित आयातों के कारण हुई है। प्राधिकारी ने प्रारंभिक निष्कर्षों के पैरा 40 में स्पष्ट रूप से यह माना है कि ये कारक ही पाटन एवं क्षति के बीच कार्य-कारण संबंध यथापित करते हैं, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्रारंभिक निष्कर्षों में कार्य-कारण के संबंध में प्राधिकारी ने जिन कारकों को सूचीबद्ध किया है प्रति पाटन शुल्क का विरोध करने वाले इच्छुक पार्टियों ने किसी का भी खण्डन नहीं किया है।

अंतिम निष्कर्ष

39. पूर्वोक्त पर विचार करने के बाद अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि :—

* थाईलैंड, कोरिया आर पी और इंडोनेशिया मूल की अथवा वहां से निर्यातित पी टी ए का भारत को निर्यात उसके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर निर्यात किया गया है;

* घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है;

* घरेलू उद्योग को यह क्षति थाईलैंड, कोरिया आर पी और इंडोनेशिया मूल की अथवा वहां से निर्यातित पी टी ए को निर्यात किए जाने से हुई है।

40. प्राधिकारी प्रारंभिक जांच परिणामों की पुष्टि करते हैं और थाईलैंड, कोरिया आर पी और इंडोनेशिया के उद्गम वाले या वहां से निर्यात किए गए सभी पी टी ए आयातों पर निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं।

देश/निर्यातक का नाम	राशि (रु० प्रति मै० ट०)
कोरिया जनवादी गणराज्य के संबंध में	
(क) सैमसंग पेट्रोकेमिकल्स के० लिमि०	1166
(ख) सन कार्यान्वयन इंडस्ट्रिज लिमि०	1490
(ग) कोहैप पेट्रोकेमिकल्स कोपोरेशन	1130
(घ) अन्य कोई निर्यातक	
थाईलैंड के संबंध में	1490
(क) टुनटैक्स पेट्रोकेमिकल्स (थाईलैंड) पब्लिक कम्पनी लि०	1939
(ख) अन्य कोई निर्यात	1939
इंडोनेशिया के संबंध में	
कोई निर्यात	3375

41. उपर्युक्त के अधीन, प्राधिकारी दिनांक 4-9-1996 को प्रारंभिक जांच परिणामों की पुष्टि करते हैं।

42. उपरोक्त अधिनियम के अनुसार, इस आदेश के खिलाफ एक अपील सीमा शुल्क, आबकारी और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय ट्रिब्यूनल के पास की जा सकती है।

रत्न विनय झा, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th March, 1998

FINAL FINDINGS

Subject: Anti dumping Investigation concerning imports of PTA from Thailand, Korea RP and Indonesia - Final Findings

14/1/96/ADD.—Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, thereof:

A. PROCEDURE

1. The procedure described below has been followed subsequent to the preliminary findings:
 - i) The Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) notified preliminary findings vide notification dated the 4th Sept., 1997 and requested the interested parties to make their views known in writing within forty days from the date of its publication;
 - ii) The Authority forwarded a copy of the preliminary findings to the known interested parties who were requested to furnish their views, if any, on the preliminary findings within forty days of the date of the letter;
 - iii) The Authority also forwarded copies of the preliminary findings to the Embassies of Thailand, Korea RP, and Indonesia in New Delhi with a request that the exporters and other interested parties may be advised to furnish their views on the preliminary findings;
 - iv) The Authority provided an opportunity to all interested parties to present their views orally on 20th Oct., 1997. All parties presenting views orally were requested to file written submissions of the views expressed orally. The parties were advised to collect copies of the views expressed by the opposing parties and offer written rebuttals, if any
 - v) Subsequent to the appointment of new Designated Authority by the Central Government on 17th Dec., 1997, all interested parties were advised vide letter dated 20th Jan., 1998 to indicate if they would like to explain orally the submissions made by them, which were already on record, in accordance with Rule 6(6). The interested parties were informed that they could appear before the Authority on 10th Feb., 1998, if so desired, to explain their case orally. M/s. J. Sagar & Associates waived its right to oral hearing on behalf of the four exporters (Samsung, Sunkyoung, Kohap and Tuntex) from the subject countries and all the importers in India;
 - vi) The Authority held an oral hearing on 10th Feb., 1998. It was clarified that no new issues could be brought up and that the arguments should be limited to the issues

presented at the hearing on 20th Oct., 1997. No written statements were accepted or taken on record.

- vii) The investigations have been concluded within the time limit extended by the Central Government. The one year time limit expired on 19th Dec., 1997. The same has been, however, extended by the Central Government by three months and the extended time limit expires on 19th March, 1998.
- viii) The Authority made available the public file to all interested parties containing non-confidential version of all evidence submitted by various interested parties. All parties who made request for inspection, in writing, were allowed to inspect the public file;
- ix) M/s. J. Sagar & Associates informed, vide their fax dated 9th Sept., 1998 that the names of the following exporters represented by it were wrongly mentioned by the Authority in the preliminary findings notified and the correct names were as under:

Correct name as per J. Sagar & Associates	Name mentioned by the Authority in the preliminary findings (as per J. Sagar & Associates)
Sunkyong Industries	Sunkyong Ltd.
Kohap Petrochemical Co. Ltd.	Kohap Chemical Corporation

The Authority notes that the correct names of these exporters, as per available information on record furnished by them, are Sunkyong Industries Ltd. and Kohap Petrochemical Corporation and the Authority had also mentioned the same in the preliminary findings and relies on the same;

- x) Argument raised by the interested parties before announcing the preliminary findings, which have been brought out in the preliminary findings notified have not been repeated for sake of brevity. However, the arguments raised by the interested parties have been appropriately dealt in the preliminary findings and/or in these findings.
- xi) In accordance with Rule 16 of the Rules supra, the essential facts/basis considered for these findings were disclosed to known interested parties and comments received on the same have also been duly considered in these findings;

It is clarified that the disclosure statement was issued on 5th March, 1998 by Speed Post. The same was sent by fax also to a large number of interested parties. The Authority has consistently allowed about the same time period for offering comments on disclosure as has been allowed in this case.

B. PETITIONER'S VIEWS

- 2. The petitioners raised the following arguments:
 - a) The volume of PTA imported in the investigation period exceeds the minimum prescribed level of imports qualified for investigations and levy of duty.
 - b) In the circumstances that RIL is excluded from the definition of domestic industry and there doesn't exist an identical product for comparison, the second part of definition of the like product would be applicable in the present case.

- c) It is not disputed by any interested party that polyester can be made from either PTA or DMT. Substitutability is universally accepted norm to determine like article. It is also undisputed that the price of DMT has direct relationship with the price of PTA. There is commercial equivalence between DMT & PTA. DMT & PTA are, therefore, like products within the meaning of the rules.
- d) RIL stated that its second PTA plant went into production in the first quarter of 1997 and the company stopped importing PTA thereafter. The company further argued that since investigations have not yet been completed, it should be considered as domestic industry for the purpose of the present investigations.
- e) The exporters incurred expenditures such as ocean freight, commission, inspection charges at the port, inland freight, interest on the credit extended to the importers, bill of lading charges, higher packing export, etc. associated with exports. When the export price is adjusted for these expenses the dumping margin comes to 2.5 % - 18 %. Dumping is also established in case normal value is calculated based on costs, which establishes dumping margin of 10 % to 30%.
- f) The claims made by the exporters with regard to negotiation fee for the domestic sales needs careful examination.
- g) The claims made by Kohap with regard to dumping need be very carefully scrutinised. The argument that Kohap is selling PTA at much lower prices in their domestic market than others tantamount to Kohap becoming the most competitive supplier of PTA in Korea. Other producers in Korea would not have sustained in such a case, particularly when Korea is a surplus PTA market.
- h) RIL argued that while the cost of production can be claimed confidential, the price and adjustments therein cannot be claimed as confidential by an exporter. The company requested that such information be made available to them.
- i) RIL argued that it had argued in the petition that threat of dumping would become a reality, no sooner its next PTA plant of 350000 MT capacity goes into production. This has become the reality with the commissioning of its second plant.
- j) Dumping of PTA resulted in decline of PTA prices from Rs. 57000 pmt to Rs. 37000 pmt in India. The sole cause for serious price erosion in the Indian market was massive dumping of PTA.
- k) The anti-dumping duty should be levied not only with immediate effect but atleast with effect from 04.09.1997, when the competent authority had come to a conclusion that the duty is necessary.
- l) The normal value claimed by Kohap doesn't appear to be genuine in view of prevailing prices of Paraxylene (referred to as Px hereinafter).
- m) Imports of PTA from Korea have been made at US \$ 515 per MT in the post investigation period.

C. VIEWS OF EXPORTERS, IMPORTERS AND OTHER INTERESTED PARTIES

- 3. The views expressed by the importers and the exporters on the product under consideration, like article, domestic industry, dumping, injury and causal link have

discussed in the relevant paras hereinbelow. Other views expressed by them are briefly mentioned below:

- a) Imposition of anti dumping duty will affect a number of polyester units involving substantial investments and employment.
- b) Anti-dumping duty on PTA would trigger dumping of PSF, PFY, PET resin and films in India.

D. EXAMINATION BY AUTHORITY

4. The submissions made by the petitioner, exporters, importers and other interested parties have been examined, considered and, wherever appropriate, dealt hereinafter.

E. PRODUCT UNDER CONSIDERATION, LIKE ARTICLES AND DOMESTIC INDUSTRY

5. Product under consideration in the present investigations is Purified Terephthalic Acid (also known as PTA and referred to as PTA in this notification). There is no dispute on the product under consideration and, therefore, the Authority confirms preliminary findings with regard to product under consideration.
6. Arguments have been raised with regard to the like article that if the definition of like article is interspersed in the definition of domestic industry, it would be seen that the scope of the term "domestic industry" will be determined only with reference to the domestic producers who produce identical article to the product under investigation. It is only in the absence of such an article, that the second leg of the definition would come into play. There is a domestic producer, producing PTA and the two are identical or alike in all respects. Disqualification of RIL is immaterial as the same is to dissuade domestic producers from importing and enjoying the benefits of dumped products and simultaneously bringing an action against the said product. Interpretation of the term domestic industry in any other manner would be against all established canons of interpretation of statutes. It has further been argued that reasoning of the Authority on this account is erroneous. It is not a case that there is no domestic producer producing the identical article. There exists domestic industry producing PTA but has been disqualified in terms of the statutory definition. The statutory bar cannot be overcome by imparting the interpretation rendered by the Authority.

Authority's position:

The Authority notes that the investigations are being conducted for the alleged dumped product i.e. the product under consideration. Having determined the product under consideration, the Authority is required to decide the like article and the relevant domestic industry. There is no denial of the fact that a domestic producer of PTA exists. However, in view of the fact that RIL, the only producer of PTA, is also one of the petitioners, the Authority considered PTA/DMT as the like article in terms of the definition. It may be re-emphasised that RIL has been excluded only for the purpose of the scope of domestic industry in view of statutory definition.

7. **Petitioners and domestic industry:** Arguments raised on the standing of the petitioners to file the petition and the scope of the domestic industry are as under:
- a) The imports made by RIL are negligible as compared to their own PTA production and rejection of the application on technical ground is not fair. Injury, if any, caused to the

PTA producer should have been considered while recommending duty. As there was no other PTA producer, investigation should have been terminated.

- b) The exclusion of domestic PTA producer is based on unfair logic.
- c) Since the sole producer of PTA has been disqualified as domestic industry, investigations should have been terminated.
- d) Representative of RIL made submission on behalf of the domestic industry at the time of oral submissions. As RIL had imported PTA, their petition was not accepted by the Authority. RIL had no locus standi in the entire matter and yet they were allowed to make submissions. The Authority should not take into account any of their submissions in making final findings.

Authority's position:

The Authority notes that it is grossly incorrect to say that RIL has no locus standi in the present investigations. RIL is a petitioner in the present investigations and is entitled to participate in the present investigations as an aggrieved party. The fact that RIL has been excluded from the definition of domestic industry does not debar it as a petitioner, nor does it lose its locus standi in seeking suitable redress. The contentions made by RIL, therefore, have been taken into account to the extent the same are relevant.

- 8. With regard to the contention of RIL that it has stopped importing PTA after the investigation period and since the investigations have not been concluded, it should now be considered as the domestic industry, the Authority notes that the factors which are relevant for the purpose of the present investigations are the factors pertaining to the investigation period. Since RIL had imported PTA in the investigation period, it would not be appropriate to change the scope of the domestic industry at this stage.
- 9. In view of the forgoing, the Authority confirms preliminary findings in paras 8 to 14 of the preliminary findings notification with regard to the product under consideration, like article, and domestic industry and that the goods produced by the domestic industry are like articles to the product under consideration.

F. DUMPING

- 10. Arguments raised by interested parties on dumping are as follows:

M/s. Pertamina, PT Amoco Mitsui PTA Indonesia, Siam Mitsui PTA Co., Ltd. and Samsung General Chemical Co., Ltd. (also referred to as SGC herein) claimed that they were neither producing PTA during the investigation period, nor had they exported PTA to India. These companies claimed exclusion in accordance with Rule 22 of the Rules supra

Authority's position:

The Authority notes that since these companies have claimed that they have neither produced PTA nor exported the same to India during the investigation period, they fall under Rule 22. All the companies, except for Pertamina have separately filed petition under Rule 22, which are being considered on merits.

- 11. The methodology adopted with regard to determination of dumping and the claims allowed by the Authority in the preliminary findings are discussed hereinbelow. There is no argument raised by any interested party with regard to the methodology adopted,

except for the comparison of normal values with export prices on monthly basis, which has been separately examined hereinbelow. The Authority confirms the preliminary findings with regard to the methodology adopted for determination of dumping.

12. The claims made by these exporters before the preliminary findings with regard to the price adjustments and the adjustments allowed by the Authority at the time of preliminary determination are not being discussed in these findings for sake of brevity. The adjustments allowed by the Authority now for these final findings and the reasoning thereof are discussed hereinbelow.
13. A team of officials deputed by the Authority conducted detailed spot-investigations at the premises of the four co-operating exporters.

I **Samsung Petrochemical Co., Ltd. (Samsung):**

14. Samsung claimed that it has exported PTA through an unrelated party. It is, however, found that the company sold its goods to Samsung Corporation, who has in turn exported the subject goods to India. There is evidence available with the Authority that goods have been exported to India by Samsung Asia Pte. Ltd., also "on advise from Samsung Corpn.", which were stated to be produced by Samsung Petrochemical. The claim of the company is that Samsung Petrochemical is not related to either Samsung Corporation or Samsung Asia Pte. Ltd. and the prices at which goods have been sold by Samsung Petrochemical to these companies represent the prices at which goods have been exported by the company in the ordinary course of trade. There is, however, sufficient documentary evidence available to suggest that the sales made by Samsung Petrochemical to Samsung Corporation can not be considered as sales in the ordinary course of trade. The published brochure, for instance, shows consolidated figures for the entire group, where the turnover of Samsung Corporation and Samsung Petrochemical have been shown under the group turnover. Further, the brochure shows Samsung Petrochemical as an "affiliated" company. The Authority, therefore, disregards the export price claimed by the exporter.
15. The information furnished by the Importers with regard to imports of PTA from the subject countries was analysed with a view to correlate the price at which goods have been exported by Samsung Corporation and the price at which goods have been invoiced by Samsung Petrochemical to Samsung Corporation. The Importers have furnished the C&F prices at which goods have been purchased by them, which have been exported by Samsung Corporation. The export price has been considered on the basis of these details of imports available with the Authority.
16. With regard to price adjustments, since the details of the expenses incurred by Samsung Corporation on exports to India, such as inland freight, overseas freight, marketing, administrative and general costs (SGA) have not been furnished to the Authority either by Samsung Petrochemical or by the exporters, the Authority considers it appropriate to allow adjustments from the export price on the basis of the expenses incurred by the other co-operating exporters from Korea RP, i.e., Kohap and Sunkyoung. Since no information is available with regard to SGA expenses, it is considered appropriate to reduce the export price by 3%, which is the commission which would have otherwise been payable by the company had it exported through some other company. With regard to adjustment on account of credit sales in the home market, the Authority notes that since information about the sales made by Samsung Corporation or Samsung Asia Pte Ltd. has not been made available, either in response to the questionnaire or at any subsequent point of time, it would not be appropriate to allow

adjustment on this account, as similar information with regard to exports to India is not available with the Authority. No adjustment on account of credit sales has been allowed

II Sunkyong Industries Ltd. (Sunkyong):

17. The Authority has allowed all adjustments claimed by the exporter in view of detailed verification carried out at the premises of the exporter.

III) Kohap Petrochemical Corporation (Kohap)

18. With regard to the selling prices in the home market, it is found at the time of the spot verification that Kohap has been selling to a related company in Korea RP for ultimate consumption in Korea RP. Sales to this related company account for nearly 84% of the total company sales in the home market. Under the Rules, the Authority in such circumstances is required to determine the prices at which the related company sold goods to first unrelated company in Korea RP. In the instant case, however, the related company consumed the goods and therefore, the price to related company cannot be considered. The Authority has, therefore, disregarded the sales made by Kohap to its related company and determined the selling prices on the basis of sales made to other customers in Korea RP. The Authority notes that the sales made to other unrelated companies are substantial and can be considered as representative of the selling prices in Korea RP.
19. The Authority has allowed all price adjustments claimed by the company, except for adjustment on account of credit sales. With regard to adjustment on account of credit sales, the Authority notes that the exporter has claimed that exports to India have been done mainly through Kohap Ltd., which holds 42.5% shares in Kohap Petrochemical Corporation. Further, since the payment terms at which Kohap Ltd. has exported PTA to India are not available with the Authority, it would not be appropriate to allow adjustment on account of credit sales in the home market.

IV) Tuntex Petrochemicals (Thailand) Public Company Ltd. (Tuntex):

20. The detailed verification conducted at the premises of Tuntex revealed that the inland freight claimed by the company in case of sales in the home market are not based on the actual expenses incurred by the company and were notional expenditure. The company has incurred an average expenditure of ***** on account of inland freight, as against ***** claimed by the company. The Authority has allowed inland freight on the basis of actual inland freight incurred by the company. The Authority has allowed all other price adjustments claimed by the exporter.

V Exporters from Indonesia:

21. There is no response from any exporter in Indonesia even after the preliminary findings, except from Pertamina. Since Pertamina has not exported any PTA to India during the investigation period, it attracts Rule 22 and cannot be considered for determination of dumping and dumping margin. The Authority has, therefore, proceeded with final determination on the same lines as was done in the preliminary findings in case of Indonesia. The Authority confirms the preliminary findings with regard to determination of dumping in case of exporters from Indonesia.
22. With regard to the comparison of normal value with export price, it has been argued that the determination of dumping margin by the Authority in the preliminary findings is incorrect in so far as the Authority has done comparison of normal value with export

price on the basis of monthly averages of normal values and export prices. The interested parties have argued that world-over the dumping margin is determined only on the weighted average basis and the same has been done by the Authority also in all the cases so far. Transaction-by-transaction method is used only in unusual circumstances such as when there are a very few sales of the subject merchandise, the parties have argued. The statute permits the Authority to determine dumping margin only on the basis of weighted average normal value and weighted average export price for the investigation period. The conclusion drawn by the Authority in the preliminary findings with regard to comparison does not flow from the observation made by the Authority that the prices in the home market and exports to India were declining. It has been further argued that in cases where both the markets witness simultaneous increase or decrease in the prices, the weighted average is tailor made to adjust for such fluctuations. Further, the determination of dumping margin on a month to month basis is not warranted by law.

Authority's position:

The Authority notes that the above arguments with regard to the comparison are factually, conceptually and legally incorrect. The Authority has also determined the dumping margin on "weighted average basis". However, the weighed averages of normal values and export prices have been worked for each of the month in the investigation period. The Authority has done comparison on this basis in view of significant decline in both the normal value and export price during the investigation period and no sales either in the home market or exports to India in some of the months by some of the exporters. It was noted by the Authority that there were very high sales volumes in some months whereas there were no exports to India in some other months. Determination of normal values on the basis of weighted average of normal value for the whole of the investigation period in a case where there are no exports in some of the months in the investigation period and the export price declined significantly from month to month in the investigation period, comparison of weighted average normal value with export price (which represents export price for the sales made in only some of the months in the investigation period) would be inappropriate, unfair and could even be misleading. In a situation where there are exports to India only in one month in the investigation period, say Oct., 1996, and the prices declined in the investigation period, as in the present case, the results drawn using weighted average basis for comparison may be quite misleading and may result in assessment of dumping margin whereas there may not be any dumping. Converse is also true. For instance, the selling price of Kohap in the domestic market in the month of April, 1996 as worked out now is ***** pmt as against ***** in the next month (May, 1996). There are no exports to India in the month of April, 1996. Had the Authority adopted a single weighted average normal value, the selling price for the month of April, 1996 would have increased the normal value of Kohap, whereas there were no exports to India. This could have led to higher dumping margin, whereas the same is not the fact. The comparison on the basis of month-wise averages is more appropriate in such a situation than a single average for the entire investigation period and, in fact, goes to the advantage of the exporters. Further, it would also be inappropriate to adopt different comparison methods for different exporters. Moreover, it has not been demonstrated by any interested party(ies) how the comparison of normal value with export price on month-to-month basis has resulted in distortions, if any, in the comparison.

23. In view of the above, the Authority confirms the preliminary findings with regard to dumping (normal value, export price and comparison). The dumping margin comes as under:

Name of the Country/Exporter	Dumping margin (% of export price)
A. IN CASE OF KOREA RP	
a) Samsung Petrochemical Co., Ltd.	9.25
b) Sunkyoung Industries Ltd.	9.63
c) Kohap Petrochemical Corporation	6.65
B. IN CASE OF THAILAND	
Tuntex Petrochemicals (Thailand) Public Company Ltd.	9.43
C. IN CASE OF INDONESIA	14.97

G. INJURY

24 The arguments raised by interested parties opposing recommendation of anti-dumping duty are as follows.

- a) The entire injury analysis has been done with reference to the producers of DMT. The recommendation of the duties is on imports of PTA, which is to the exclusive benefits of the disqualified domestic industry. The investigation appears to have been initiated for favouring a single disqualified domestic producer. The conclusion would have been different, had injury to the PTA producers could have been analysed.

Authority's position:

The above argument deserves to be ignored in view of the scope of the domestic industry, as defined above in the para (no. 7) relating to domestic industry. The argument advanced with regard to injury to the sole PTA producer is presumptive and is not supported by any evidence. Neither the Authority has investigated in detail injury to RIL nor has any interested party established that RIL has not suffered injury. In view of statutory definition of the term domestic industry, the Authority has no other option but to exclude RIL from the scope of domestic industry and analysis of injury.

- b) Injury to the DMT domestic industry and the causal link have to be seen only with reference to those importer who have the facility to use PTA and DMT. Since BDMC has not established even on prima facie basis that it has been injured as a result of import of PTA by those importers who can use both PTA and DMT, the investigation is required to be terminated.
- c) The preliminary findings suffers from serious contradiction. No real injury has been caused to the domestic industry who are enjoying healthy profits, operating at 100% capacity utilisation. BDMC is working at 95% capacity utilisation and earning profits continuously.
- d) BDMC plant was closed from 15.05.1996 to 15.06.1996 due to chemical leakage, resulting in a loss of production of 14000 MT. The lower capacity utilisation claimed by petitioner is not correct.
- e) BDMC has purchased Px at higher contracted prices compared to ruling lower spot prices.
- f) The entire injury analysis has been done by the Authority without taking into cognisance the fundamental and relevant factors about import and domestic sourcing of PTA and

DMT by the PSF manufacturers. No finding has been given by the Authority on the arguments raised on this account.

Authority's position on (b) to (f):

The above contentions from sub-para (b) to (f) are factually incorrect. The Authority has established in the preliminary findings that injury to the domestic industry has been caused by the imports of PTA at dumped prices regardless of the fact whether the importer could use DMT or not, and the same have been brought out in the preliminary findings. The Authority has considered lower of the contract price and ruling spot prices of Px for determination of fair selling price.

- g) In case DMT prices had to be kept lower in review of lower import price of PTA, the same should have been faced by RIL also. Financial result published by RIL does not reflect any distress sale or reduction in profits.

Authority's position:

As brought out in preliminary findings, BDMC suffered material injury by imports of PTA at dumped prices, regardless of the fact whether the importer can use DMT or not. Preliminary findings of the Authority in this regard has not been disputed. The argument about the distress sale by RIL is presumptive and the argument about profits made by RIL deserves to be ignored as the same relates to overall profits of RIL obtained from a number of products. The argument is, therefore, liable to be rejected.

25. The Authority did not analyse the reasons for the increased consumption of PTA. The findings on production and capacity utilisation have to be seen with reference to increase in installed capacity by 20000 MT even when the petitioner could not utilise the existing capacity in view of the demand situation.

Authority's position:

The Authority has not held under utilisation of capacity or loss of production as the reasons for the injury suffered by BDMC in the preliminary findings. The Authority has merely analysed these factors in the preliminary findings to determine whether the domestic industry has suffered material injury. The interested parties have failed to distinguish between material injury and causal link between dumping and material injury.

26. The Authority notes that preliminary findings with regard to the injury to the domestic industry is not based on any single parameter affecting the domestic industry, such as production, capacity utilisation, sales, selling prices, stocks, profitability, etc. The Authority has clearly held in the preliminary findings that various indicators relating to the domestic industry, collectively and cumulatively establish that the domestic industry has suffered material injury. The arguments of the interested parties that some of the factors do not show injury to the domestic industry deserves to be ignored.
27. The Authority, in view of the foregoing, confirms the preliminary findings with regard to the injury to the domestic industry.

H. CAUSAL LINK

28. The arguments raised by interested parties that imports of PTA increased due to reasons other than dumping are appreciated. Injury to the domestic industry has to be seen with reference to the principles governing injury. The findings of the Authority on injury does not imply that on the basis of the factors on injury examined by the Authority, the Authority has found that the domestic industry has suffered material injury

from dumped imports. The Authority has not held in the preliminary findings that increase in imports from the subject countries or reduction in the production, capacity utilisation, etc. by the domestic industry are the factors which establish that material injury to the domestic industry has been caused by the dumped imports. The Authority has very clearly held in para 40 of the preliminary findings the factors which establish causal link between dumping and injury. The Authority notes that none of the factors listed by the Authority in the preliminary findings with regard to the causal link have been controverted by the interested parties opposing anti-dumping duty

I. **FINAL FINDINGS**

29. The Authority, after considering the foregoing, concludes that

- PTA originating in or exported from Thailand, Korea RP and Indonesia have been exported to India below their normal value;
- the domestic industry has suffered material injury;
- the injury has been caused to the domestic industry by the exports of the subject PTA originating in or exported from Thailand, Korea RP, and Indonesia.

30. The Authority confirms the preliminary findings and recommend imposition of definitive anti-dumping duties on all imports of PTA originating in or exported from Thailand, Korea RP and Indonesia. The final duties comes as under:

Name of the Country/Exporter	Amount of Anti Dumping Duty (Rs. Per MT)
A. <u>IN CASE OF KOREA RP</u>	
I. Samsung Petrochemical Co , Ltd.	1166
II Sunkyong Industries Ltd.	1490
III. Kohap Petrochemical Corporation	1130
IV. Any Other exporter	1490
B. <u>IN CASE OF THAILAND</u>	
I. Tuntex Petrochemicals (Thailand) Public Company Ltd.	1939
II. Any Other exporter	1939
C. <u>IN CASE OF INDONESIA</u>	
All Exporters	3375

31. Subject to above, the Authority confirms the preliminary findings dated 4.9.1997

32. An appeal against this order shall lie to the Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal in accordance with the Act supra.

RATHI VINAY JHA, Designated Authority

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 1998

अंतिम जांच परिणाम

विषय : यू.एस.ए., कनाडा तथा रूस से अखबारी कागज के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच-अंतिम परिणाम।

21/एडीडी/96-1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन तथा संग्रहण एवं क्षति का निर्धारण) नियम 1995 की ;

क. प्रक्रिया

(1) नीचे निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है :

- (i) प्राधिकृत अधिकारी ने दिनांक 11 जून, 1997 की अधिसूचना सं 21/एडीडी/1/डब्ल्यू के द्वारा प्रारम्भिक जांच परिणाम अधिसूचित किए तथा इच्छुक पार्टियों से इसके प्रकाशन की तिथि से 40 दिन के भीतर अपने विचारों को लिखित में अवगत कराने के लिए अनुरोध किया ;
- (ii) प्राधिकारी ने उन सभी ज्ञात इच्छुक पार्टियों को प्रारम्भिक जांच-परिणामों की एक प्रति प्रेषित की जिनसे कि पत्र जारी होने की तिथि से 40 दिन के भीतर प्रारम्भिक जांच-परिणामों पर अपने विचार, यदि कोई हो तो, भेजने का अनुरोध किया गया था ;
- (iii) प्राधिकारी ने प्रारम्भिक जांच-परिणामों की एक प्रति संयुक्त राज्य अमेरिका तथा रूस के नई दिल्ली स्थित दूतावास तथा कनाडा उच्चायोग को भी इस अनुरोध के साथ भेजी कि वे निर्यातक तथा अन्य इच्छुक पार्टियों को प्रारम्भिक जांच परिणामों पर अपने विचार भेजने की सलाह दें ; प्रारम्भिक जांच परिणामों पर अपने विचार भेजने हेतु जहाँ भी समय सीमा को बढ़ाने के लिए समय पर जिन अनेक इच्छुक पार्टियों ने समय पर अनुरोध किया , यह सीमा 25-7-1997 तक बढ़ा दी गयी।
- (iv) प्राधिकारी ने सभी इच्छुक पार्टियों को मौखिक रूप से उनके विचार रखने के लिए दिनांक 7 अगस्त, 1997 को अवसर प्रदान किया। निम्नलिखित पार्टियों ने मौखिक सुनवाई में भाग लिया :

आनन्द बाजार पत्रिका

देशोषा सेल्स लिमि.

देशोषा इंक.

दि ट्रीब्यून ट्रस्ट

जनरल ट्रेडिंग एंड सेल्स कारपोरेशन

हिन्दुस्तान टाइम्स

वालिया ब्रोस (प्रा.) लिमि.

मनीपाल प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स

अमरचंद एंड मंगलदास

इंडियन न्यूजप्रिंट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन

इंडियन एग्री पेपर मिल्स एसोसिएशन

ओवरसीज ट्रेडिंग

इंडियन पेपर

मैसूर पेपर मिल्स

आईएपीएमए

एआईएसपीएमए (आल इंडिया पेपर मिल्स एसोसिएशन)

दि संदेश लिमि.

पारिख पेपर एजेन्सिज (प्रा.) लिमि.

मेकर ईट. कंसल्टियम मास्को

रशियन ट्रेड रिप्रेजेंटेशन

यशोधया पब्लिकेशन

कनाडियन हाई कमिशन

इंडियन एक्सप्रेस

हरिनको एक्सपोर्ट्स
 यशोधया इंटरप्राइसिस
 मालायला मनोरामा
 टाइम्स ऑफ इण्डिया
 न्यूजप्रिंट ट्रेडिंग एंड सेल्स कारपोरेशन
 न्यूजप्रिंट सेल्स कारपोरेशन
 राजिन्द्र नारायण एंड कंपनी
 हिन्दुस्तान टाइम्स
 इंडियन न्यूज पेपर सोसायटी
 आज
 जे. सागर एंड एसोसिएट्स
 इंडियन एक्सप्रेस
 एक्सप्रेस पब्लिकेशन (मद्रास) लिमि.

सार्वजनिक सुनवाई में विचार रखने वाले सभी पक्षों से मौखिक रूप से रखे गए विचारों को लिखित में भेजने का अनुरोध किया गया। पक्षों को सलाह दी गई कि वे विरोधी पक्षों के विचारों की प्रति लेकर उन पर अपने खण्डन, यदि कोई हैं, प्रस्तुत करें। प्राधिकारी ने अनेक इच्छुक पार्टियों को उनके अनुरोध पर 7 अगस्त, 1997 के बाद अपने विचार मौखिक रूप से रखने की अनुमति भी दी।

- (v) उपरोक्त नियमों के नियम 16 के अनुसार जांच परिणामों के लिए जिन आवश्यक तथ्यों/आधारों पर विचार किया गया उनकी जानकारी इच्छुक पक्षों को दी गई थी तथा उनके विचार रखने की अनुमति दी गई यदि कोई हो तो। उस पर प्राप्त टिप्पणियों पर भी इन जांच परिणामों पर विचार किया गया है।
- (vi) अनेक पक्षों ने प्राधिकारी द्वारा रखी सरकारी फाईल का निरीक्षण करने का अनुरोध किया। जिन सभी पक्षों ने लिखित में निरीक्षण का अनुरोध किया था, उन्हें विभिन्न इच्छुक पक्षों द्वारा प्राधिकारी को भेजे गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंशों के निरीक्षण की अनुमति प्रदान की गई।
- (vii) अनेक इच्छुक पक्षों ने विभिन्न पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों की प्रति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। जिन पार्टियों ने विशिष्ट कागजातों को प्राप्त करने का अनुरोध किया उन सभी को वे दस्तावेज दिए गए।
- (viii) एबीटीबी कन्सोलिडेटेड इंक ने अनुरोध किया कि उनके द्वारा प्राधिकारी को भेजी गई गोपनीय सूचना वित्त मंत्रालय सहित भारत सरकार में किसी भी पार्टी को नहीं दी जानी चाहिए तथा इसका इस्तेमाल प्राधिकारी द्वारा केवल सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य तथा पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए ;

केन्द्रीय सरकार द्वारा 17 दिसम्बर, 1997 को नए निर्दिष्ट प्राधिकारी की नियुक्ति के बाद सभी हितबद्ध पार्टियों को सलाह दी गई थी कि यह बताएं कि क्या वे नियम 6 (6) के अनुसार उनके द्वारा किए गए अनुरोधों को मौखिक रूप से स्पष्ट करना चाहेंगे जो उन्होंने पहले ही लिखित में दिए हैं। इच्छुक पार्टियों को सूचित किया गया था कि यदि वे चाहें तो अपने मामले को मौखिक रूप से स्पष्ट करने के लिए प्राधिकारी के समक्ष 12 फरवरी, 1998 को उपस्थित हो सकते हैं। तत्कालीन निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा दिनांक 6-11-97 के अपने पत्र में दिए गए स्पष्टीकरण की नए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने स्वतंत्र रूप से जांच की थी जिन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि दिनांक 6-11-97 के सूचना पत्र में बताए गए अनिवार्य तथ्यों को उनके अंतिम जांच परिणाम के लिए भी आधार बनाया जाएगा इसलिए अनिवार्य तथ्यों पर और स्पष्टीकरण की आवश्यकता महसूस नहीं की गई।

प्राधिकारी ने 12 फरवरी, 1998 को मौखिक सुनवाई की। यह स्पष्ट किया गया था कि कोई नए मामले नहीं उठाए जाएंगे और तर्क पूर्व प्राधिकारी के समक्ष सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किए गए मामलों तक ही सीमित होंगे। इस बारे में कोई लिखित में ब्यौरे नहीं लिए गए।

इस जांच कार्य को केन्द्र सरकार द्वारा विस्तारित समय-सीमा के भीतर अर्थात् 19 मार्च, 1998 तक पूरा कर लिया गया है।

- (ix) प्राधिकारी ने एक इच्छुक पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के केवल अ-गोपनीय अंशों को ही दूसरे इच्छुक पक्षों को उपलब्ध करवाया। एक इच्छुक पक्ष द्वारा गोपनीय आधार पर भेजी गई जानकारी दूसरे हितबद्ध पक्ष (पक्षों) को उपलब्ध नहीं करवायी। आदेश के इस सार्वजनिक विवरण में गोपनीय सूचना छुपा दी गयी है तथा इसे "....." या "....." के रूप में दर्शायी गयी है।
- (x) विभिन्न इच्छुक पक्षों द्वारा दिए गए तर्कों को यथा संभव सीमा तक प्राधिकारी द्वारा उसकी जांच के साथ इन निष्कर्षों में संबंधित स्थानों पर रखा गया है। अन्य तर्कों तथा याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों को इन निष्कर्षों में प्राधिकारी द्वारा इनकी जांच के साथ अलग-अलग रखा गया है। हितबद्ध पक्षों द्वारा उठाए गए तर्कों को "उठाए गए तर्क" तथा प्राधिकारी द्वारा इनकी जांच को "प्राधिकारी का विचार" के रूप में दर्शाया गया है।
- (xi) याचिकाकर्ता तथा सहकारी निर्यातकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की जहां तक आवश्यक समझा गया, नियमानुसार जांच की गई। एबीटीबी,

स्टोन कनसोलीडेटेड, एवनोर, कोंडोपोंगा, बालाखाना, सोलीकाम्स, एमपीएम, टीएनपीएल, एच एन एल तथा नेपा द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना की प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से जांच की गई।

(xii) इन निष्कर्षों में उल्लिखित गैट/डब्ल्यू. ई. ओ. करार का संबंध टैरिफ तथा व्यापार पर सामान्य करार, 1994 के अनुच्छेद VI के क्रियान्वयन संबंधी समझौते से है।

(xiii) संकेतचिह्न : इन जांच परिणामों में निम्नलिखित संकेत चिह्नों का इस्तेमाल किया गया है :

शब्द	जिसके लिए इस्तेमाल किया गया
एबीटीबी	एबीटीबी-ग्राहस इंक
एवनोर	एवनोर इंक
प्राधिकारी	निर्दिष्ट प्राधिकारी
बालाखाना	जे एस सी बोल्गा (बालाखाना पेपर मिल्स)
सोलीकाम्स	जे एस सी सोलीकाम्सप्रोम
कोंडोपोंगा	कोंडोपोंगा पल्प एंड पेपर मिल्स
उपरोक्त नियम	सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियम
आईएनएस	इंडियन न्यूज पेपर सोसाइटी
आईएनएमए/याचिकाकर्ता	भारतीय न्यूजप्रिंट उत्पादक संघ
एच एन एल	हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि०
टीएनपीएल	तमिलनाडु न्यूजप्रिंट लि०
नेपा	नेपा लिमि०
एम पी एम	मैसूर पेपर मिल्स लिमि०
यूनीवर्सल	यूनीवर्सल पेपर मिल्स एक्सपोर्ट कं०
एसजीए	बिक्री, सामान्य तथा प्रशासनिक खर्च
एक्सप्रेस पब्लिकेशन्स	एक्सप्रेस पब्लिकेशन्स (मद्रास) लिमि०

ख. याचिकाकर्ता द्वारा व्यक्त विचार :

2. विभिन्न मामलों पर याचिकाकर्ता अर्थात् आई एन एम ए द्वारा व्यक्त विचार निम्नानुसार है :

- (क) प्राधिकारी द्वारा तय की गई जांच की अवधि संपूर्ण याचिका दायर कराने से पहले 6 महीने की है तथा यह अंतर्राष्ट्रीय मानदण्डों तथा घरेलू प्रथा के अनुसार है जहां जांच की अवधि छः महीने से एक वर्ष तक होती है।
- (ख) याचिकाकर्ता, याचिका दायर करने की स्थिति से संतुष्ट है क्योंकि भारत में अखबारी कागज के विभिन्न विनिर्माता इसके सदस्य हैं। प्राधिकारी के समक्ष चार बड़े विनिर्माता भी याचिकाकर्ता हैं। याचिका न तो प्रेरित है और न ही यह बचाव चाहने वाले मुट्ठी भर लोगों के लाभार्थ है। इस संबंध में पर्याप्त सुरक्षा उपाय संबंधी नियम हैं क्योंकि अनेक ऐसी प्रारम्भिक बाधाएं हैं जिन्हें याचिका पर प्राधिकारी द्वारा विचार किए जाने से पहले दूर की जानी हैं।
- (ग) घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित तथा वस्तु देशों से आयातित अखबारी कागज का इस्तेमाल विनियम आधार पर उपयोग किया जा रहा है। नियमों के अर्थ में दोनों एक जैसी वस्तुएं हैं हालांकि घरेलू अखबारी कागज तथा आयातित अखबारी कागज की गुणवत्ता में भिन्नता हो सकती है। समान वस्तु की परिभाषा काफी विस्तृत है।
- (घ) सामान्य मूल्य : हालांकि याचिकाकर्ता ने घरेलू बाजार के बीजकों/निविदाओं की प्रतियों के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है, फिर भी प्राधिकारी ने आई एन एम ए द्वारा दिए गए आंकड़ों पर ध्यान न देते हुए निर्यातकों द्वारा भेजी गई सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है।
- (ङ) निर्यात मूल्य : निर्यात मूल्य का निविदाओं/बीजकों के आधार पर दावा किया गया था परन्तु प्राधिकारी ने निर्यातकों द्वारा दिए गए आंकड़ों को अपनाया है।
- (च) पाटन के निर्धारण तथा इन जांचों के प्रयोजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों की कोई प्रासंगिकता नहीं है।
- (छ) हानि : पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हानि पहुंची है तथा पहुंच रही है तथा इस संबंध में प्राधिकारी के जांच परिणामों को दोहराया तथा

उल्लेख किया जाता है।

- (ज) समाचार पत्रों की वास्तविक आय विज्ञापनों से है। जनवरी, 1996 में, जब आयात का मूल्य 750 यू. एस. डालर प्रति मी० टन था, तब प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापनों की दर 2150/- रुपए प्रति कालम प्रति से०मी० थी। जब आयात मूल्य गिर कर 430 यू. एस. डालर पीएमटी तक हो गया तब विज्ञापनों की दर बढ़कर 2400/- रुपए हो गई। यदि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है तो समाचार उद्योग को कोई हानि नहीं पहुंचेगी। पाटनरोधी शुल्क लगाने से घरेलू विनिर्माताओं को केवल एक समान कार्य क्षेत्र मिलेगा। प्राधिकारी द्वारा अपनाया गया निम्न शुल्क का सिद्धान्त घरेलू उद्योग की कमियों, यदि कोई हो तो, को संरक्षण प्रदान करता है। इस प्रकार घरेलू उत्पादकों की कमियों के लिए आयातकों द्वारा भुगतान न करवाया जाए।
- (झ) आयातकों ने जिन दीर्घकालीन अनुबंधों का उल्लेख किया है उसके संबंध में, यह कहा जाता है कि दीर्घकालीन अनुबंध निश्चित मूल्य अनुबंध नहीं हैं तथा जब तक कि निर्यात मूल्य सामान्य मूल्य से कम हैं दीर्घकालीन अनुबंधों के मामले में भी पाटन हो सकता है।
- (ञ) जांच की अवधि के बाद निर्यात मूल्य में हुई बढ़ोतरी के संबंध में यह सुस्थापित है कि वर्तमान जांच के उद्देश्य से जो प्रासंगिक हैं वे जांच अवधि के दौरान के कारक हैं। जांच अवधि के बाद विक्री मूल्य में हुई बढ़ोतरी से संबंधित प्रश्न बाल बियरिंग मामले में यूरोपीय आयोग के समक्ष उठाया गया था जिसमें आयोग ने पाया कि मूल्यों में वृद्धि जांच अवधि के बाद हुई है अतः इसकी उपेक्षा की गई है। आयोग ने पाया कि अन्यथा इसका तात्पर्य होगा "....." निर्यातकों को अल्पकालिक मूल्यवृद्धियों के आधार पर परिणामों में हेराफेरी करने की अनुमति प्रदान करना। बिप्पोन सी को तथा टोयो बियरिंग के मामले में ईयू में कोर्ट ने (आयोग के) इस तर्क का यह कहते हुए समर्थन किया कि यह जरूरी है कि जांच अवधि एक सीमित तथा विशिष्ट अवधि की है, तथा इस तर्क को स्वीकार करना असंभव था कि कार्रवाई को बंद कर दिया जाए या शुल्क न लगाया जाए केवल इसलिए कि जिन कंपनियों पर शुल्क लगाया जाना था उन्होंने जांच की अवधि के बाद मूल्यों में वृद्धि की है।
- (ट) यहां तक की जर्मनी, जिसकी अर्थव्यवस्था पूर्णतः परिपक्व है, ने भी कनाडा अखबारी कागज के आयात पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाना ठीक तथा उचित समझा है। ई. यू. ने कनाडा से होने वाले अखबारी कागज के आयात को 50,000 मी० टन तक सीमित कर दिया है। इस सीमा के बाहर होने वाले किसी भी मात्रा के आयात पर टैरिफ लगाया जाएगा। यहां तक कि डब्ल्यू टी ओ भी होने वाली परिस्थितियों एवं दशाओं में विषमताओं को दूर करने के लिए 25% तक टैरिफ लगाने की अनुमति देता है।
- (ठ) जब अंतर्राष्ट्रीय मूल्य 1000 यू. एस. डालर प्रति मी० टन के आसपास थे, तब समाचार पत्रों ने आसानी से गुजारा किया। अतः ऐसा कोई कारण नहीं है कि उद्योग को पाटनरोधी शुल्क लगाने में चिन्ता करनी चाहिए।
- (ड) सभी अखबारी कागज की मिलें घाटा उठा रही हैं जबकि समाचार पत्र अप्रत्याशित मूल्यों का लाभ उठा रहे हैं।
- (ढ़) अखबारी कागज के आयात के उदारीकरण का लाभ केवल 5-6 प्रमुख समाचार-पत्रों को ही पहुंचा है। छोटे समाचार पत्र घाटे में हैं।
- (ध) संपूर्ण अखबारी कागज तथा कागज उद्योग का भविष्य खतरे में है, जो कि प्रत्यक्ष रूप से 2,00,000 लोगों तथा अप्रत्यक्ष रूप से 10,00,000 से भी अधिक लोगों के रोजगार को प्रभावित कर रहा है।
- (न) उपभोक्ताओं के लिए आयात पर निरंतर निर्भरता के परिणामस्वरूप भविष्य में अधिक ऊँची कीमतें अदा करनी होंगी और इससे अखबारी उद्योग रुग्ण हो जाएगा।
- (ख) इच्छुक पक्षों द्वारा व्यक्त विचार तथा प्राधिकारी द्वारा जांच :

3. इच्छुक पक्षों द्वारा व्यक्त विचारों, प्रति-पाटन शुल्क लगाने का विरोध, जांच का क्षेत्र, सामान्य घरेलू उद्योग, पाटन, हानि तथा कार्य-कारण के संबंध में प्राधिकारी ने इन जांच परिणामों में उचित स्थान पर विचार-विमर्श के साथ-साथ इनकी जांच भी की है।

4. इच्छुक पार्टियों द्वारा अन्य मसलों पर व्यक्त किए गए विचार निम्नलिखित हैं :—

- (1) उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में अखबारी कागज पर शुल्क के औचित्य के संबंध में उठाए गए तर्क :

(क) इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ प्रकरण में प्राधिकारी से उच्चतम न्यायालय के फैसले के पैरा 63, 66, 67, 68, 80, 82, 83, 87, 88, और 101 पर ध्यान आकर्षित किया गया है। इस फैसले से उत्पन्न समस्याएं इस प्रकार हैं :—

- 0 अखबारी कागज पर लेवी के औचित्य पर सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखने के बाद सीमा-शुल्क लगाने की कार्यकारी अधिसूचना जारी की जानी है।
- 0 सरकार को किसी समाचार-पत्र के कारोबार पर सामाजिक नियंत्रण लगाने की आवश्यकता तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को सुरक्षित रखने की आवश्यकता के बीच एक न्याय और तर्कसंगत संतुलन बनाए रखने पर ध्यान देना चाहिए।
- 0 सरकार को इस तथ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1)(क) द्वारा संरक्षित क्रियाकलाप पर कार्रवाई कर रही है।

- 0 लागू प्रतिबंधों का औचित्य निश्चित करने में सरकार को निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए :—
- 0 कथित अधिकार के स्वरूप का हनन हुआ है।
- 0 लागू पाबंदियों का मुख्य उद्देश्य।
- 0 अर्थदण्ड में असंगति।
- 0 संगत समय में प्रचलित दशाएं।
- 0 अखबारी कागज पर शुल्क लगाना समाचार पत्र के अधिकार पर पाबंदी लगाना समझा जाता है।
- 0 किसी प्रमुख कारक के प्रभाव जो किसी समाचार पत्र पर पृष्ठों में कटौती करने या मूल्य बढ़ाने के लिए दबाव डालते हैं तो यह अनुच्छेद 19 (1)(क) का उल्लंघन होगा।
- 0 अखबारी कागज पर कर उचित लेवी के रूप में न्यायोचित होने में समर्थ होना चाहिए। प्राधिकारी ने समाचार पत्रों पर अपनी सिफारिशों के प्रभाव को निर्धारित नहीं किया, जो न्यूजप्रिंट का आयात करता है। यद्यपि हर दूसरे मामले में जांच को आयात के होने वाले प्रभाव तक सीमित किया जा सकता है, तथापि न्यूजप्रिंट के मामले में समाचार-पत्रों पर सिफारिशें करते समय सिफारिशों के प्रभाव पर अलग हटकर विचार हो सकता है। प्राधिकारी की सिफारिश का न्यूजप्रिंट की लागत से सीधा संबंध होगा, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) के अन्तर्गत संरक्षण-प्राप्त समाचार-पत्रों की स्वतंत्रता पर पड़ेगा। पाटनरोधी शुल्क, सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 के तहत अधिसूचना के द्वारा सार्वजनिक हित में लगाया जाता है। जबकि यद्यपि यह अविवादित है कि जब कभी समाचार-पत्र उद्योग पर कोई विशिष्ट शुल्क लगाया जाता है तो उसे भी बाकी समुदाय के साथ-साथ कुल कराधान के बोझ का अपना उचित हिस्से का वहन करना चाहिए तथापि यह उचित शुल्क के रूप में न्यायोचित होने के योग्य होना चाहिए।

प्राधिकारी की स्थिति :

प्राधिकारी ने नोट किया कि प्रति पाटन शुल्क की धारणा का उपर्युक्त सापेक्ष में मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इच्छुक पार्टियों द्वारा प्रति पाटन शुल्कों को सीमा शुल्कों के साथ जोड़ा जा रहा है। प्राधिकारी का विचार है कि हालांकि प्रति पाटन शुल्कों को सीमा शुल्कों के रूप में संग्रहीत किया जाता है, तथापि, प्रति पाटन शुल्कों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि देश में सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर माल का आयात न किया जाए। दूसरे शब्दों में प्रति पाटन शुल्क का स्वरूप किसी निर्यातक द्वारा विभेदकारी मूल्य से हुए हानिकारक प्रभाव को खत्म करना है। इस बात पर जोर देना महत्वपूर्ण होगा कि प्रति पाटन शुल्क, कर के स्वरूप में नहीं होते हैं और प्राधिकारी को भी यह शक्ति प्रदान की गयी है कि वह निर्यातक द्वारा मूल्य की वचनबद्धता देने पर इन शुल्कों को स्थगित कर सकता है। प्रति पाटन शुल्क केवल निर्यातकों के लिए हैं और इस कानून के तहत या आर्थिक दृष्टि से सीमा शुल्कों के साथ जोड़ा या मिलाया नहीं जा सकता। इस बात को भी स्वीकार किया जाना चाहिए कि प्रति पाटन शुल्क प्रणाली में उस स्थिति में वापसी की भी व्यवस्था है यदि जांच अवधि के बाद स्थिति में काफी हद तक परिवर्तन हो गया हो। यह सुनिश्चित करने हेतु अनेक पूर्वोपाय हैं कि इच्छुक पार्टी (पार्टियों) के हित पर, उस स्थिति में कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े यदि पाटन को रोक दिया गया हो या स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गया हो।

प्राधिकारी ने माना है कि सिफारिश की जा रही प्रति पाटन शुल्क, ऊपर उल्लिखित सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के संदर्भ में उचित, न्यायसंगत और अनुरूप है।

30. वर्ष 1995—96 के बीच एक्सप्रेस प्रकाशन के वितरण आंकड़ों के विश्लेषण से निम्नांकित का पता चलता है :—

वर्ष	अखबारी कागज की कीमत	प्रतियां (संख्या)	कीमत रु.	कमीशन के बाद निबल कीमत रु.
अप्रैल—जून, 95	27606	267137	2.25	1.74
जुलाई—सितम्बर 95	31496	263054	2.25	1.74
अक्टू.—दिस. 95	34342	263054		
अप्रैल—जून 96	24535	274011	2.25	1.74
जुलाई—सितम्बर 96	20735	274011	2.25	1.74
अक्टू.—दिस. 96	17208	284112	2.25	1.74
			(1.50 बंगलौर)	1.16

प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि अखबारी कागज की कीमत की तुलना में अखबारों की कीमतें अलोचशील हैं, चूंकि वह 2.25% रु. प्रत्येक प्रति पर बना रहा जबकि आयातित अखबारी कागज की कीमत 34342 रु. पी. एम. टी. से 17208 रु. पी. एम. टी. के बीच थी। प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि संदर्भाधीन देशों के निर्यातों पर प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना, जो कि घरेलू उद्योग की क्षति को रोकने के लिए आवश्यक हैं, से अखबारों पर कोई

गम्भीर परिणाम नहीं पड़ेगा विशेषकर तब जबकि इन उपायों में अन्य देशों से आयात, भारतीय उत्पादकों की आपूर्ति और संदर्भाधीन देशों से उचित कीमत पर आयात को प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव नहीं है।

दिया गया तर्क :—

प्राधिकारी को अखबारों पर उगाही से होने वाले संघात पर विचार करना चाहिए। इस संबंध में एक्सप्रेस पब्लिकेशन (मदुरई) लि. द्वारा अपने लाभ/हानि का उल्लेख किया गया है, जो निम्नानुसार हैं :

वर्ष	लाभ/हानि (मूल्य लाख रु. में)
1993-94	343.94
1994-95	352.06
1995-96	877.00 (हानि)
1996-97 (प्रथम छमाही)	486.00 (हानि)

आई. एन. एस. ने भी प्राधिकारी द्वारा सिफारिशों के संघात को दिखाने के लिए एक विवरण प्रस्तुत किया है। इन कथनों की छानबीन से पता चलता है कि आई. एन. एस. ने सदस्यों को इस सिफारिश से सुझाए गए पाटनरोधी शुल्क के कारण नुकसान/लाभ में गिरावट दर्शाया है, और इससे पड़ने वाले वित्तीय बोझ तथा अखबारी कागज उद्योग के लाभ पर पड़ने वाले प्रभाव का ब्यौरा भी दिया है।

प्राधिकारी का विचार—

प्राधिकारी ने नोट किया कि “एक्सप्रेस पब्लिकेशन” ने हानि और 10% के सीमा शुल्क के बीच में कोई संबंध नहीं पाया है, क्योंकि उक्त शुल्क केवल 27-10-96 को लगाया गया था जबकि 1996-97 में हुआ घाटा, वर्ष 1995-96 में दर्शाए गए घाटे की तुलना में कम है। इसलिए “एक्सप्रेस पब्लिकेशन” पर शुल्क का कोई प्रभाव नहीं पाया गया है।

विवरण की जांच करने पर यह पता चलता है कि आई. एन. एस. ने इस बात पर विचार करते हुए यह अनुमान लगा लिया है कि यदि उसके सदस्य उसी स्रोत से तथा उसी तादाद में खरीदना जारी रखते हैं तो उसके सदस्यों को कितना भुगतान करना होगा। तथापि, आई. एन. एस. ने प्रकाशकों को समस्त लाभ देयता पर इस कल्पित अतिरिक्त भार के संघात को प्रकट नहीं किया है और न ही आई. एन. एस. या किसी अन्य इच्छुक पाटो (पार्टी) ने यह सिद्ध किया है कि प्रस्तावित उगाही के परिणामस्वरूप कोई अनुचित प्रतिबंध लगेगा। इसके विपरीत, प्राधिकारी का यह विचार है कि प्रस्तावित प्रति पाटन शुल्क का लगाया जाना भारतीय अखबार उद्योग के दीर्घकालिक तथा व्यापक हित में होगा, जैसाकि, प्रारंभिक निष्कर्षों से पता चला है, और इसे यह सुनिश्चित करने के लिए लगाए जाने की आवश्यकता है कि भारतीय न्यूजप्रिंट उपभोक्ताओं को न्यूजप्रिंट की अपनी-अपनी आवश्यकता के लिए दीर्घकालिक स्रोत उपलब्ध किए जाएं।

(II) आई. एन. एम. ए. द्वारा दायर की गयी याचिका पर दिया गया तर्क :—

(क) व्यापकता निर्यातकों के संबंध में याचिका में पाटन के सही-सही आंकड़े तथा ब्यौरे का कोई उल्लेख नहीं किया गया है और इसे पाटन के अनुमान एवं औसत तक ही सीमित रखा गया है, यद्यपि, इसमें पांच कनाडा तथा 8 रूस के निर्यातकों के नाम दिए गए हैं। प्राधिकारी ने ऐसी याचिका का स्वीकार करने में गलती की है और वह इसमें दिए गए आंकड़ों के आधार पर प्रारंभिक निष्कर्षों पर पहुंच गए हैं।

(ख) याचिका अनुमानों एवं कल्पनाओं से भरी हुयी है, जैसे कि निर्यातकों द्वारा समुद्री भाड़े और बोमा, एजेंटों का कमीशन, माल की निकासी एवं उत्तरार्ध प्रभाओं इत्यादि की तरफ कथित रूप से किए गए अतिरिक्त व्यय के संबंध में हैं।

(ग) याचिकाकर्ता ने पाटन को सिद्ध करने के लिए अनेक पत्रों का सहारा लिया है इनमें से किसी भी पत्र में ऐसी कोई प्रामाणिक सामग्री चिह्नित नहीं है जिसके आधार पर किसी तर्क अथवा तथ्य को स्थापित किया जा सके।

(घ) लुगदी और पेपर बॉक का जो सहारा लिया गया है वह उसमें दी गयी पादटिप्पणी को देखते हुए त्रुटिपूर्ण है।

(ङ) जहां तक पाटन का मूल्यांकन और इसकी मात्रा का संबंध है, निविदाओं से कोई सहायता नहीं मिल सकती है। वास्तविक बिक्री के आंकड़े ही संगत होते हैं। याचिकाकर्ता ने अमेरिकन प्रेजीडेंट लाईस, द्वारा निरंतर की गयी खेपों संबंधी हवाई भाड़े की दर से संबंधित निविदाओं का सहारा लिया है जबकि अखबारी कागज की खेप रूस से बड़ी मात्रा में रुक रुक कर आती है।

प्राधिकारी का विचार :—

यू. एस. ए. और कनाडा से निर्यातों के मामले में, प्राधिकारी ने निर्यातकों द्वारा दी गई सूचना और प्राधिकारी के पास उपलब्ध अन्य सूचना के आधार पर पाटन की प्रारंभिक आकलन किया है। रूस से निर्यातों के मामले में, रूस के उत्पादकों द्वारा असहयोग को ध्यान में रखते हुए भर्त्सक उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकारी को सामान्य मूल्य का आकलन करना था।

चूंकि उक्त आकलन याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गयी सूचना पर आधारित नहीं है और न ही पाटन से संबंधित मौजूदा निष्कर्ष याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गयी सूचना पर आधारित हैं, इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा किए गए दावे असंगत हो जाते हैं।

(III) प्रारंभिक आकलन के लिए अपनाई गई कार्यविधि पर दिया गया तर्क :—

(क) इण्डियन एक्सप्रेस, मुम्बई ने लिखा कि उन्हें प्रारंभिक निष्कर्षों की प्रति प्राप्त नहीं हुई है।

प्राधिकारी का विचार :—

प्राधिकारी ने कंपनी को एक प्रति प्रेषित कर दी थी और निष्कर्षों को भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था। इसलिए इस संबंध में इच्छुक पार्टी (पार्टियों) द्वारा दिया गया तर्क गुण-दोष रहित है।

(ख) कुछ सदस्यों को इसकी शुरुआत का काफी समय बाद पता चला था और इसीलिए उन्होंने प्रत्युत्तर को दायर करने हेतु समय अवधि को बढ़ाने की मांग की थी लेकिन प्राधिकारी ने 28-2-97 से आगे उक्त अवधि को बढ़ाने के संबंध में सहमति नहीं दी थी।

प्राधिकारी का विचार :—

जैसाकि प्रारंभिक निष्कर्षों से भी स्पष्ट किया गया है, जिस दिन को जाँच की कार्रवाइयां शुरू की गई थी उसी दिन शुरुआत संबंधी सूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई थी, और इसलिए, इच्छुक पार्टी (पार्टियों) का तर्क गुण-दोष रहित है।

(ग) अधिसूचित किए गए प्रारंभिक निष्कर्षों के तहत प्रति पाटन शुल्कों को पूर्वव्याप्ति प्रभाव से लागू किया जाएगा क्योंकि जाँच-अवधि अप्रैल-अक्टूबर, 1996 की थी। यह कानून के अन्तर्गत अनुमत्त नहीं है।

प्राधिकारी का विचार :—

यह तर्क तथ्यतः और वैचारिक तौर पर गलत है। आरोप की जाँच हेतु जाँच-अवधि को चुना जाता है और जाँच अवधि के लिए कोई शुल्क देय नहीं होगा (अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए)। इस मामले में प्रति-पाटन शुल्कों को पूर्वव्याप्ति आधार पर लगाया जाने का प्रस्ताव नहीं है। प्रति पाटन शुल्क जब तक कि भविष्यलक्षी आधार पर संदेय होते हैं। प्राधिकारी ने शुल्क को पूर्वव्याप्ति आधार पर लगाने की सिफारिश नहीं की है और, इसलिए, पार्टी की दलील तथ्यतः गलत है।

(घ) विभिन्न विदेशी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा वसूले गये मूल्य एक ही समय पर एक समान ही थे। इसके अतिरिक्त, ऐसा माना गया है कि पश्चिमी देशों में व्याप्त मुक्त बाजार परिस्थितियों में विक्रय मूल्य भी एक ही समय पर कमोबेश एक समान ही होते होंगे। ऐसी दशा में, यह असंगत प्रतीत होता है कि भिन्न-भिन्न आपूर्तिकर्ताओं के लिए पाटन मार्जिन भिन्न-भिन्न होना चाहिए जैसा कि प्राधिकारी ने अपने प्रारंभिक निष्कर्षों में अनुमान लगाया है। प्राधिकारी द्वारा कनाडा के निर्यातकों के संबंध में सिफारिश किए गए प्रति-पाटन शुल्कों के अत्यधिक भिन्न-भिन्न स्तर न्यायसंगत नहीं हैं।

प्राधिकारी का विचार :—

प्राधिकारी द्वारा व्यक्तिगत निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के वास्तविक स्तर का निर्धारण किया गया है। व्यक्तिगत निर्यातकों का सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य समान होना आवश्यक नहीं है। इच्छुक पार्टी (पार्टियों) द्वारा भिन्न-भिन्न निर्यातकों के सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य के बारे में दिया गया तर्क कल्पनाओं पर आधारित है। भिन्न-भिन्न निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनाओं से यह पता चलता है कि एक ही समय में भिन्न-भिन्न निर्यातकों के निर्यात मूल्य अलग-2 थे। जाँच अवधि के दौरान सभी पार्टियों ने निर्यात किया था। जिसके परिणामस्वरूप शुल्कों का अलग-अलग स्तर निर्धारित किया गया था।

(ङ) चुनिंदा आंकड़े और याचिकाकर्ता एवं अन्य द्वारा उपलब्ध की गई सूचनाओं के आधार पर, प्राधिकारी ने प्रारंभिक निष्कर्षों को पारित किया है।

प्राधिकारी का विचार :—

यह तर्क तथ्यतः गलत है। प्रारंभिक निष्कर्ष इच्छुक पार्टियों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनाओं पर आधारित होते हैं जैसा कि प्रारंभिक निष्कर्षों में स्पष्ट किया गया है।

(च) प्राधिकारी के उन प्रारंभिक निष्कर्ष, जिसने अनंतिम रूप से प्रति पाटन शुल्कों को लगाने की सिफारिश की गई है, के परिणामस्वरूप खास कर निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए गंभीर संकट उत्पन्न होगा। अख्त्यारी कागज एक प्राथमिक एवं महत्वपूर्ण कच्ची सामग्री है जिसको एक अखबार को प्रकाशित करने में आयी कुल लागत का 50/60% तक का हिस्सा होता है।

दस प्रतिशत सीमा शुल्क का उद्ग्रहण करते समय सरकार ने प्रति मी. टन 575 अमरीकी डालर का प्रारंभिक मूल्य निर्धारित किया था, उसी समय पर 10% के उक्त सीमा शुल्क को भी हटा लिया जाना चाहिए। अतः सरकार ने यह स्पष्ट किया था कि 575 अमरीकी डालर वह उचित विक्रय मूल्य है, जिस पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रतिस्पर्धा करने और अपने बाजारगत हिस्से को बरकरार रखने की आशा की जाती है। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय कीमतें इस स्तर पर लगभग पहुंच चुकी हैं इसलिए उक्त 10% सीमा शुल्क को भी हटा लिया जाना चाहिए।

*प्राधिकारी ने अचानक एवं अस्पष्ट रूप से अधिसूचना जारी की, जिसमें प्रति मी. टन 140 अमरीकी डालर से अधिक के प्रति पाटन शुल्क को लगाने की सिफारिश की गई है।

*प्रारंभिक निष्कर्ष एक तरफा अनुचित हैं और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध हैं और इन पर लिखित अनुरोधों के बावजूद भी सुनवाई का अवसर दिए बिना पहुँचा गया है।

*किसी भी श्रेणी का अखबार विशेष रूप से छोटे एवं मध्यम श्रेणी का अखबार प्रति पाटन शुल्क का बोझ सहन करने में असमर्थ होगा।

प्राधिकारी का विचार :—

जहां तक उगाही के औचित्य का संबंध है, उपर्युक्त तर्क अनुमानिक हैं। आई. एन. एस. सहित अनेक इच्छुक पार्टियों को प्राधिकारी द्वारा की जा रही जांच संबंधी कार्रवाइयों की जानकारी थी। प्राधिकारी द्वारा 20-12-1997 को जांच संबंधी कार्रवाइयां शुरू की गई थी और अनेक इच्छुक पार्टियों ने सूचना और/या अपने विचारों को प्रस्तुत किया था, जिन पर प्राधिकारी द्वारा कानून के अनुसार इन निष्कर्षों पर पहुंचने से पहले विचार किया गया है। अतः ये निष्कर्ष एक तरफा, अनुचित नहीं हैं और न ही ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध हैं। नियमों में सिफारिश किए जा रहे प्रति पाटन शुल्क की उस स्थिति में समीक्षा करने की व्यवस्था है यदि जांचोत्तर अवधि के दौरान परिस्थितियों में वास्तविक परिवर्तन हो गया हो। अतः इन तर्कों के तथ्यों के अभाव में अस्वीकृत किया जाता है।

(ज) इन सिफारिशों के जरिए, प्राधिकारी ने मांग और आपूर्ति के उन काफी पुराने सिद्धांतों को तिलांजलि देने का प्रयास किया है, जिनसे किसी जिस का मूल्य अधिशायित होता है और इससे उपभोक्ताओं द्वारा आपूर्ति के अपने स्रोत को चुनने के अधिकार को कम किया गया है और इससे अखबारों के पाठकों द्वारा अतिरिक्त उगाही को वहन करना होगा।

प्राधिकारी का विचार :—

ये सिफारिशें विधि के अनुसार हैं, और इच्छुक पार्टियों का उपरोक्त तर्क गुण-दोष रहित है।

(झ) प्राधिकारी ने कानून के अन्तर्गत निर्धारित की गयी कार्य प्रणाली का अनुपालन करते समय सभी इच्छुक पार्टियों के प्रति निष्पक्ष बने रहने और सभी के प्रति निष्पक्ष दिखने से संबंधित पहलू की उपेक्षा की है। इसकी पुष्टि निम्नलिखित तथ्यों द्वारा की जाती है :—

- * विलम्ब से हुए पत्राचार के बावजूद भी अनेक इच्छुक पार्टियों के मामले में समयावधि को नहीं बढ़ाया गया है।
- * प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक निष्कर्षों की घोषणा करते समय अनेक उपयोगकर्ताओं द्वारा दायर किए गए प्रत्युत्तरों पर विचार नहीं किया गया है।
- * अनेक इच्छुक पार्टियों द्वारा प्रारंभिक निष्कर्षों को जून के आखिरी सप्ताह में ही प्राप्त किया गया था और इसलिए इन पार्टियों द्वारा समय पर जवाब नहीं दिया जा सका था।
- * प्रारंभिक निष्कर्षों के ब्यौरे प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख के लगभग साढ़े तीन महीने के बाद प्रकाशित किया गया है।

प्राधिकारी का विचार :—

निम्नलिखित को देखते हुए उपरोक्त तर्क गुण-दोष रहित हैं और/या तथ्यतः गलत है :—

आई. एन. एस. सहित अनेक इच्छुक पार्टियों को स्पीड पोस्ट द्वारा प्रारंभिक निष्कर्ष भेजे गये थे। प्रारंभिक निष्कर्षों को भारत के राजपत्र, असाधारण में निष्कर्षों के दिन ही तत्काल प्रकाशित किया गया था। अनेक प्रमुख अखबारों में सिफारिशों के बारे में जानकारी दी गयी थी। आई. एन. एस. ने भी सिफारिशें तुरंत बाद ही मामले को उपयुक्त समय पर उठाया था ;

जिन इच्छुक पार्टियों ने निश्चित तारीख से पहले तर्कसंगत कारण देते हुए अवधि को बढ़ाने का अनुरोध किया था उनके मामले में अवधि को बढ़ाया गया था ;

सूचना की प्राप्ति के बाद प्रारंभिक एवं/या अंतिम निर्धारण को पूरा करने के लिए कोई समय सीमा नहीं है (जाँच को पूरा करने के लिए समय-सीमा को छोड़कर) और न ही सूचना की प्राप्ति और निष्कर्षों के प्रकाशन के मध्य समय के अंतराल से किसी इच्छुक पार्टी (पार्टियों) को सूचना दायर करने का अधिकार तदन्तर प्राप्त हो जाता है। प्राधिकारी को सूचनाओं के विश्लेषण और परीक्षण करने से पूर्व बड़ी मात्रा में आंकड़े इकट्ठे करने होते हैं। निर्धारित तिथि के बाद सूचनाओं को स्वीकार करना संभव नहीं होगा क्योंकि इससे तो यह प्रक्रिया निरंतर चलती ही रहेगी जिससे अंतिम जाँच परिणाम में विलंब होगा। तथापि यह ध्यातव्य है कि सभी अभ्यावेदनों को अंतिम जाँच परिणाम के लिए ध्यान में रखा जाएगा।

(ग) प्रति पाटन शुल्क लगाने के परिणामस्वरूप विषयाधीन देशों में अन्य प्रकार से प्रतिकार की भावना पैदा हो सकती है।

प्राधिकारी का विचार :—

यह तर्क आनुमानिक है। गैर करार के तहत किसी भी देश को, वर्तमान सिफारिशों को देखते हुए प्रतिपाटन कार्रवाई का विरोध करने वाले किसी सदस्य देश के विरुद्ध प्रतिकारात्मक कार्यवाही की स्वीकृति नहीं दी जाती है। इस संबंध में भारत सरकार के हितों को पूर्णतः सुरक्षित रखा जाता है।

(ट) **मौखिक सुनवाई पर :** प्राधिकारी द्वारा मौखिक सुनवाई के संबंध में अपनाई गई कार्यप्रणाली, निष्पक्ष कार्य शैली और प्राकृतिक न्याय के निर्धारित और सुस्थापित सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है इच्छुक पार्टियों को अभ्यावेदन करने का पूरा और उचित अवसर प्रदान नहीं किया गया था और अभ्यावेदन की प्रतियाँ पार्टी की सुनवाई किए जाने से पहले उपलब्ध नहीं की गई थी। प्राधिकारी के इस आदेश पर भी पुनर्विचार किए जाने की अपेक्षा है कि मौखिक सुनवाई के उपरान्त दलीलों का आदान-प्रदान और प्रतिप्रत्युत्तर को दायर किया जाएगा।

प्राधिकारी का विचार :—

नियम 6(6) के तहत, प्राधिकारी द्वारा इच्छुक पार्टी को मौखिक सूचना प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जा सकती है लेकिन इस तरह की मौखिक सूचना पर प्राधिकारी द्वारा तब विचार किया जा सकता है जब इसे बाद में लिखित रूप में पुनः प्रस्तुत किया जाता है। प्राधिकारी ने नोट किया है कि इसके लिए निम्नलिखित का दायित्व नहीं है इच्छुक पार्टी (पार्टियों) प्रारंभिक निष्कर्षों से पहले मौखिक रूप से सूचना प्रस्तुत करने की अनुमति देना। मौखिक सुनवाई जाँच की कार्रवाइयों के दौरान किसी भी समय की जा सकती है।

मौखिक सुनवाई की प्रक्रिया के संबंध में इच्छुक पार्टियों की दलील भी उपर उल्लिखित नियम को देखते हुए अव्यवहारिक है जिसमें स्पष्ट तौर पर यह व्यवस्था है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी किसी इच्छुक पार्टियों को मौखिक रूप से सूचना प्रस्तुत करने की स्वीकृति दे सकते हैं। निर्दिष्ट प्राधिकारी सभी इच्छुक पार्टियों को दस्तावेजों की प्रतियाँ उपलब्ध कराने के लिए बाध्य नहीं है जैसा कि नियमों में प्रावधान किया गया है। हालाँकि इच्छुक पार्टियों के पास अपनी -2 सुविधानुसार सार्वजनिक फाइलों की जाँच करने का अवसर भी उपलब्ध था, और, इसलिए यह तर्क कि इच्छुक पार्टी के पास दस्तावेज की जाँच करने का अवसर उपलब्ध नहीं था, सही नहीं है। वास्तविकता यह है कि ऐसी कोई भी इच्छुक पार्टी नहीं थी जिसने प्रारंभिक निष्कर्षों से पहले सार्वजनिक फाइल की जाँच की हो। इसलिए, प्राधिकारी ने स्वविवेकानुसार पहली मौखिक सुनवाई के दौरान उपस्थित सभी इच्छुक पार्टियों को सार्वजनिक फाइल की जाँच करने और लिखित ब्यौरे प्रस्तुत करने की समय-सीमाओं की समाप्ति से पूर्व जरूरत पड़ने पर एक अन्य मौखिक सुनवाई के लिए अनुरोध करने का अवसर प्रदान किया था। अनेक इच्छुक पार्टियों ने सार्वजनिक फाइलों की जाँच के लिखित ब्यौरे प्रस्तुत किए और उनकी मौखिक सुनवाई की गई। इस दूसरी सुनवाई के दौरान भी, इन इच्छुक पार्टियों को दिनांक 7-8-1997 को घोषित की गयी लिखित ब्यौरे को दायर करने की अंतिम तारीख से पूर्व दूसरी सुनवाई के समय उनके द्वारा व्यक्त किए गए विचारों के लिखित ब्यौरे दायर करने की स्वीकृति दी गई थी। कुछ इच्छुक पार्टियों ने, निश्चित तारीख से पहले लिखित ब्यौरों का एक अन्य सैट दायर किया जिस पर प्राधिकारी द्वारा विधिवत विचार विमर्श स्वीकार किया गया तथा इन निष्कर्षों पर पहुँचते समय उस पर विचार भी किया गया। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि किसी भी इच्छुक पार्टी के पास मौखिक रूप से अपने विचारों को व्यक्त करने का पूरा अवसर उपलब्ध नहीं था।

(ड.) गोपनीयता पर :—गोपनीयता का दावा करने वाली किसी भी इच्छुक पार्टी को उसका दावा सुस्पष्ट एवं पुष्टा कारणों के आधार पर करना होता है। गोपनीयता का आधार केवल अत्यधिक सार्वजनिक हित हो सकता है, उदाहरणार्थ राष्ट्रपति रक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, साम्प्रदायिक सौहार्द आदि के क्षेत्र में हित जैसे सर्वोपरि राष्ट्रीय हित से जुड़े सार्वजनिक हित सामान्य रूप से मिले व्यापारिक सूचना को गोपनीय रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्राधिकारी के पास गोपनीयता का दावा करने वाली किसी पार्टी द्वारा दिए गए कारणों, यदि कोई हो, की जाँच करने का वैधानिक दायित्व होता है और वह दावा की स्वीकृति केवल तब दे सकता है यदि उक्त प्राधिकारी संतुष्ट हो गया हो। किसी भी स्थिति में शिकायतकर्ता गोपनीयता का दावा नहीं कर सकता है। क्योंकि यह शिकायतकर्ता का मानना है, जिसका मुकाबला उगाही का विरोध करने वाली इच्छुक पार्टियों द्वारा किया जाना है। जब तक कि याचिकाकर्ता द्वारा सहारा लिए गए तथ्यों एवं आंकड़ों और उगाही का विरोध करने वाली इच्छुक पार्टी (पार्टियों) को स्रोत उपलब्ध न कर दिए जाते हैं तब तक किसी भी इच्छुक पार्टी के लिए याचिकाकर्ता के मामले का खण्डन करना असंभव होगा। पारदर्शिता और दलीलों एवं आंकड़ों की उपलब्धता की कमी होने की स्थिति में कानून के इस मौलिक सिद्धान्त की पूर्ति नहीं होगी कि न्याय न केवल किया ही गया है बल्कि किया गया प्रतीत भी होता है।

गोपनीयता का झूठा दावा करने के परिणामस्वरूप गोपनीयता का दावा करने वाली प्रत्येक पार्टी के लिए एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जैसी कि मौजूदा मामले में विद्यमान है, जिसमें निर्यातक, निर्यातकों के भारतीय एजेंट, अखबार और याचिकाकर्ता गोपनीयता का दावा करते हैं। इसलिए प्राधिकारी द्वारा गोपनीयता संबंधी मुद्दे को सुलझाने के लिए स्पष्ट एवं पुष्टा मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार किए जाने चाहिए। कस्तूरी एण्ड संस ने 12-2-98 को सुनवाई के समय तर्क दिया कि इंडियन एक्सप्रेस के पास याचिकाकर्ता अर्थात् आर. एन. एम. ए. द्वारा दायर किये गये गोपनीय दस्तावेज मौजूद थे।

प्राधिकारी का विचार :—

गोपनीयता के संबंध में इच्छुक पार्टियों की उपर्युक्त दलील को निम्न को देखते हुए रद्द किया जाता है।

*प्राधिकारी के पास गोपनीयता की अनुमति देने के लिए एक सुस्थापित नीति और मार्गदर्शी सिद्धान्त है, जो कि "गाट" करार के अनुरूप हैं।

*यद्यपि ऐसी सूचना के संबंध में भारतीय नियम निश्चित नहीं हैं जिसका गोपनीयता के रूप में दावा एवं उसे स्वीकार किया जा सकता है, तथापि इन सभी का स्पष्ट उल्लेख गाट करार में किया गया है। अनुच्छेद 6.5 में स्पष्ट तौर पर इस प्रकार की सूचना के स्वरूप के उदाहरण दिये गए हैं; जिसे गोपनीय होने का दावा किया जा सकता है, जिसमें ऐसी कोई भी सूचना शामिल होती है जिसका खुलासा होने से किसी प्रतिस्पर्धा को अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ होगा या इस सूचना का खुलासा होने से सूचना देने वाले व्यक्ति पर या जिस व्यक्ति से सूचना प्राप्त की गयी है उस पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यह भी नोट किया गया है कि गाट करार में सूचीबद्ध ऐसी सूचना, जिसका गोपनीय होने का दावा किया जा सकता है, का स्वरूप व्यापक न होकर निर्देशात्मक है।

*प्राधिकारी यह समझता है कि प्राधिकारी द्वारा गोपनीय सूचना का खुलासा न किया जाना एक ऐसी प्रथा है जिसे सारे संसार के अधिकांश जांच प्राधिकारियों द्वारा अपनाया जा रहा है। वास्तव में, प्राधिकारी को मालूम हुआ है कि यू. एस. ए. में जांच प्राधिकारी ने कुछेक मामलों में उस देश का नाम दबाकर रखा जिसके बारे में यह पाया गया था कि वह यू. एस. ए. को भाल का निर्यात भी कर रहा है।

*प्राधिकारी ने किसी भी पार्टी को गोपनीय सूचना नहीं दी है। तथापि, पार्टियाँ इस बात के लिए स्वतंत्र हैं कि वे आपस में एक दूसरे को जानकारी का आदान-प्रदान कर सकते हैं।

(द) प्राधिकारी ने प्रारंभिक निष्कर्षों में काफी संख्या में प्रमुख आंकड़ों का उल्लेख नहीं किया है। आदेश में इस प्रमुख सूचना का उल्लेख नहीं होने से प्राधिकारी द्वारा मामले के गुण-दोष के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका।

प्राधिकारी का विचार :—

प्राधिकारी ने व्यापक आदेश पारित कर दिया है और केवल वही सूचना का, जिसे गोपनीय रूप में स्वीकार किया गया है, या ऐसी गोपनीय सूचना पर आधारित विश्लेषण एवं निष्कर्षों का उक्त आदेश में उल्लेख नहीं किया गया। प्राधिकारी को उसी प्रकार की गोपनीयता बनाए रखना अपेक्षित है जैसी कि कानून के तहत इच्छुक पार्टियों को प्रदान की गई है। प्राधिकारी ने आगे नोट किया कि प्रारंभिक निष्कर्षों में, गोपनीय रूप में माने गए सूचना के संबंध में पर्याप्त जानकारी प्रकट की गई है। ऐसी गोपनीय सूचना का खुलासा नहीं करने मात्र से इच्छुक पार्टी द्वारा अपने मामले पर भी संगत सूचना और तर्कों को मुहैया कराने से पार्टियों के अपने हितों की रक्षा करने के अधिकारों में किसी भी प्रकार से कमी नहीं हुयी है।

(ण) अनिवार्य तथ्यों को प्रकट करने पर : अपेक्षित सूचना जिसे प्राधिकारी द्वारा नियम 16 के तहत प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होता है, में उन अनिवार्य तथ्यों को प्रकट नहीं किया जाता है जिन के आधार पर निर्णय किया जाता है। उनके द्वारा दी गयी विभिन्न दलीलों पर प्राधिकारी द्वारा किए गए प्रकटन में विचार नहीं किया गया है। प्रकटन में किसी तथ्यों को प्रकट नहीं किया गया है।

प्राधिकारी का विचार :—

इच्छुक पार्टियों ने जिन दलीलों पर प्रकटीकरण विवरण में विचार न किए जाने का तर्क दिया है, वे किसी तथ्य को स्थापित (या अस्मिद्ध) करने के लिए उठाए गए तर्कों के स्वरूप की हैं। इच्छुक पार्टियाँ तर्कों एवं तथ्यों के मध्य अंतर करने में अस्फल रही हैं। तथ्य तर्क से भिन्न होते हैं और चूंकि नियम 16 के अन्तर्गत अनिवार्य तथ्यों का प्रकटीकरण (और न कि अनिवार्य तथ्यों का), आता है, इसलिए प्राधिकारी ने केवल अनिवार्य तथ्यों को प्रकट किया है और इसके अतिरिक्त, नियम 16 का उद्देश्य इच्छुक पार्टियों को उनके द्वारा दावा किए गए तथ्यों की पुष्टि करने का एक और अवसर प्रदान करने की व्यवस्था करना है, जिन पर प्राधिकारी का उचित एवं निष्पक्ष निर्णय पर पहुँचने हेतु विचार करने का प्रस्ताव है। न तो प्राधिकारी द्वारा प्रकटीकरण पर टिप्पणी प्राप्त करने से पहले दावा किए गए तथ्यों की स्वीकृति या अस्वीकृति के बारे में कोई निर्णय लिया जाना अपेक्षित है और न ही इन तथ्यों के प्रकटीकरण से प्राधिकारी द्वारा दावों की स्वीकृति का या प्राधिकारी द्वारा किसी निर्णय पर पहुँचने के लिए अपनायी जाने वाली कार्यप्रणाली का आधार बनता है।

अपनाई गई जांच कार्यविधि के बारे में प्राधिकारी का विचार :—

प्राधिकारी ने अधिनियम और नियमों के तहत कानूनी विधिवत प्रक्रिया का अनुपालन किया है। नियम 6 के सभी प्रावधानों को विधिवत अनुपालन किया गया है। प्राधिकारी ने नोट किया है कि :—

- (क) नियम 6(2) के तहत, प्राधिकारी द्वारा ज्ञात निर्यातकों और निर्यातक देशों की सरकारों का सार्वजनिक सूचना की एक प्रति अग्रेषित किया जाना अपेक्षित है। इसका अनुपालन किया गया है।
- (ख) नियम 6(3) के तहत, प्राधिकारी द्वारा ज्ञात निर्यातकों और निर्यातक देशों की सरकारों को याचिका की एक प्रति उपलब्ध किया जाना अपेक्षित है इसका अनुपालन किया गया है।
- (ग) प्राधिकारी द्वारा ऐसी किसी भी अन्य इच्छुक पार्टी को याचिका की एक प्रति उपलब्ध किया जाना अपेक्षित है, जो उल्लिखित रूप में इसका अनुरोध करती है। प्राधिकारी सभी इच्छुक पार्टियों को अपनी ओर से प्रति भेजने के लिए बाध्य नहीं है। प्राधिकारी केवल उन इच्छुक पार्टियों को याचिका की एक प्रति उपलब्ध करता है, जिनके द्वारा लिखित अनुरोध किया जाता है।
- (घ) नियम 6(4) के तहत, प्राधिकारी द्वारा निर्यातकों, विदेशी उत्पादकों और अन्य इच्छुक पात्रियों से सूचना मांगी जा सकती है और उसे नोटिस प्राप्त होने से 30 दिनों के अंदर प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होता है। प्राधिकारी का यह दायित्व नहीं है कि वह सभी इच्छुक पार्टियों से सूचना मांगे और न ही प्राधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उन सभी पार्टियों से प्रत्युत्तरों की प्रतीक्षा करें जो सूचना और/या टिप्पणी प्रस्तुत करने की इच्छुक हैं। जांच शुरू होने की तारीख से एक साल के अंदर प्राधिकारी द्वारा अपनी अंतिम सिफारिशें दिया जाना अपेक्षित है और इस तरह समस्त जांच संबंधी कार्रवाइयां समयबद्ध तरीके से पूरी करनी होती हैं।
- (ङ) नियम 6(5) के तहत, प्राधिकारी द्वारा औद्योगिक उपभोक्ताओं को सूचना प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना अपेक्षित है इसका भी अनुपालन किया गया है।
- (च) नियम 6(6) के तहत, प्राधिकारी द्वारा इच्छुक पार्टी (पार्टियों) को मौखिक रूप से सूचना प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सकती है। इसका भी अनुपालन किया गया है।
- (छ) नियम 6(7) के अंतर्गत प्राधिकारी को उसके पास उपलब्ध साक्ष्य को सभी इच्छुक पार्टियों को उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। प्राधिकारी सार्वजनिक मिसिल रखता है जिसे निरीक्षण के लिए खुला रखा जाता है जिनका पार्टियाँ निरीक्षण करती हैं। प्राधिकारी ने आगे नोट किया कि सार्वजनिक मिसिल का रखरखाव भारत में जांच प्राधिकारियों द्वारा अपनाई जाने वाली कोई विलक्षण पद्धति नहीं है। इस पद्धति का प्रयोग विश्व भर में अधिकांश जांचों में किया जाता है। किसी भी स्थिति में जांच में भाग लेने वाली सभी इच्छुक पार्टियाँ तथा वे पार्टियाँ जिन्होंने दस्तावेजों का निरीक्षण करने की इच्छा व्यक्त की थी उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी गई थी।
- (ज) प्राधिकारी ने गोपनीयता के आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना पर विचार किए बिना प्रारंभिक और/अथवा अंतिम आदेश पारित नहीं किए हैं।

*प्राधिकारी की जांच शुरुआत के बारे में निर्णय करते समय दूसरे देशों से हुई डंपिंग की स्वविवेक से जांच करने के लिए बाध्य नहीं है।

गोपनीय सूचना को प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के सार्वजनिक रूपांतर से छुपाया गया है। प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के गोपनीय रूपांतर में सभी गोपनीय जानकारी शामिल है। इस स्थिति में इच्छुक पार्टी/पार्टियों के तर्क वास्तव में सही नहीं हैं। नियम 12(2) और 17(4) में व्याख्या की गई है कि प्राधिकारी को प्रारंभिक निष्कर्ष और/या अंतिम निष्कर्ष को दर्ज करने वाली सार्वजनिक सूचना जारी करेगा। यह सार्वजनिक सूचना सभी इच्छुक पार्टियों को परिचालित की गई थी और इसमें गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना शामिल नहीं थी।

- (झ) यह तर्क कि कुछेक पार्टियां तो यह भी नहीं जानती थी कि जांच चल रही है अथवा प्रारंभिक निष्कर्षों जिनको नकारा जा सकता था, की प्रति प्राप्त करने में भी विलंब हुआ। रिकार्ड पर दिखाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं कि प्रयोक्ता उद्योग संघ तथा बड़ी संख्या में इच्छुक पार्टियां चल रही जांच के बारे में पूरी तरह से अवगत थी। इसके अतिरिक्त जांच को शुरू करने के बारे में सार्वजनिक सूचना जारी की गई थी जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, में अधिसूचित किया गया था। कुछेक समाचार पत्रों ने भी जांच की शुरुआत के तत्काल बाद प्राधिकारी द्वारा जांच शुरू करने के बारे में कहानियां लिखी थी। उपर्युक्त को देखते हुए प्रकाशकों का यह दावा की, वे चल रही जांचों के बारे में जानते तक नहीं थे, को ठीक नहीं कहा जा सकता।

जहां तक प्रारंभिक निष्कर्षों के प्राप्त न होने के बारे में तथा टिप्पणियों को प्रस्तुत करने के लिए समय वृद्धि का संबंध है, प्रारंभिक निष्कर्ष भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित की गई थी तथा साथ ही इन्हें ज्ञात इच्छुक पार्टियों को स्पीड पोस्ट द्वारा भेज दिया गया था।

नियम 6(4) के तहत प्राधिकारी को अधिसूचना का उत्तर प्राप्त करने के लिए 30 दिन की अनुमति देने की आवश्यकता है और पत्र प्रेषण की तारीख के सात दिन के भीतर भेज दिए गए माने जाने चाहिए। चूंकि प्राधिकारी ने शुरुआत करने की अधिसूचना और/अथवा प्रारंभिक निष्कर्षों का उत्तर देने के लिए 40 दिन के समय की अनुमति दी थी, यह कहना गलत होगा कि इच्छुक पार्टियों को पर्याप्त समय नहीं दिया गया। इसके अतिरिक्त प्राधिकारी ने 27-2-97 तक का समय (कानून के तहत लगभग 5 सप्ताह के स्थान पर 9 सप्ताह से अधिक समय) प्रारंभ करने की नोटिस का उत्तर देने के लिए दिया था। इसके अतिरिक्त जिन मामलों में अनुरोध देय तारीख से पहले प्राप्त हुआ था उन्हें प्रारंभिक निष्कर्षों का उत्तर देने के लिए समय-वृद्धि की अनुमति दी गई थी।

IV जांच की अवधि पर उठाए गए तर्क

क. जांच की अवधि सामान्यतया जांच की अवधि के शुरू होने से पहले 12 मास का समय लिया जाता है। सामान्य मूल्य का विश्लेषण तथा 7 मास की अल्प अवधि के लिए निर्यात कीमत से सही चित्र प्रस्तुत नहीं होता है। यदि क्षति का निर्धारण करने के लिए 1991-92 से अक्टूबर, 96 की लम्बी अवधि को लिया जाता है तो लम्बी अवधि को जांच की अवधि के रूप में लिया जा सकता है।

ख. प्राधिकारी ने 1991-92 से अक्टूबर, 96 तक आयात की मात्रा, बाजार शेयर उत्पादन तथा क्षमता का उपयोग के आंकड़ों को ध्यान में रखा है। इस अवधि को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी जांच को 7 मास की सीमित अवधि तक प्रतिबंधित नहीं कर सका।

प्राधिकारी की स्थिति

यह सर्वप्रचलित प्रथा है कि पाटन संबंधी जांच विस्तृत विश्लेषण तथा जांच सुपरिभाषित अवधि पर आधारित होती है जिसे खुला नहीं रखा जा सकता। इसके अतिरिक्त नियमावली के अनुबंध II में निर्धारित किए गए सिद्धांतों के अनुसार प्राधिकारी को प्रत्यक्ष रूप से क्षति का निर्धारण करने की आवश्यकता है। इन सिद्धांतों के तहत क्षति के निर्धारण में कुछ समयवधि का मूल्यांकन शामिल है।

ग. जांच का कार्य क्षेत्र

मौजूदा जांच में शामिल किया गया उत्पाद ग्लेज़्ड अखबारी कागज को छोड़कर अखबारी कागज है। जो यू. एस. ए. कनाडा तथा रूस मूल का अथवा वहां से निर्यातित है। अखबारी कागज जिसमें ऐश की मात्रा 8% से अधिक होती है, सामान्यतः इसे ग्लेज़्ड अखबारी कागज कहा जाता है, को मौजूदा जांच के कार्य क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाता है। अखबारी कागज अनकोटिड प्रकार का कागज होता है जिसका इस्तेमाल अखबारी कागज की प्रिंटिंग में नहीं किया जाता है जिसमें से कुल फाइबर मात्रा का 65% से कम पुड फाइबर का 65% तक यांत्रिकी अथवा रसायनिक यांत्रिकी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है जो बिना नाप के अथवा बहुत हल्के आकार का होता है, जिसकी सतह प्रत्येक और मोटी पारकर प्रिंट सर्ट (1 एम. पी.ए.) है जो 2.5 मोटी माइक्रोमीटर (माइक्रोन) से अधिक नहीं होती, जिसका वजन 40 जी एस एम होता है और 65 जी एस एम से अधिक नहीं होता। अखबारी कागज का सीमाशुल्क अधिनियम, 1995 की अनुसूची की 48.01 सीमाशुल्क कोड के तहत वर्गीकरण किया गया है।

जांच के कार्य क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित तर्क दिए गए हैं :—

प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिपाटन जांच विभेदकारी है जिसमें केवल कनाडा, यू एस ए तथा रूस तथा स्कानडीनेवियनस तथा यूरोपीय संघ शामिल हैं जिनकी कीमतें कुछेक मामलों में बहुत ही कम हैं, को शामिल नहीं किया गया। उदाहरण के लिए इंडियन एक्सप्रेस (मद्रास) लि. ने 19635 रु. प्रति मी. टन की कीमत पर स्वीडन से अखबारी कागज का आयात किया जो कि सबसे कम कीमत है जिसे उन्होंने समस्त जांच की अवधि के दौरान खरीदा था। कुछ अन्य पार्टियों ने तर्क किया कि अखबारी कागज को संबद्ध देशों जैसे दक्षिणी अफ्रीका, जर्मनी तथा कोरिया लोकतांत्रिक गणराज्य से खरीदा था।

प्राधिकारी ने नोट किया कि पाटन तब होता है जब निर्यात की निर्यात कीमत निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में प्रचलित वस्तु के सामान्य मूल्य से कम हो। देश से केवल कम कीमतों का तात्पर्य पाटन नहीं है। न तो याचिकाकर्ता ने इन देशों (कनाडा, रूस तथा यू एस ए को छोड़कर अन्य देश) से अखबारी कागज के सामान्य मूल्य के बारे में कोई सूचना प्रस्तुत की थी और न ही जांच की शुरुआत के समय प्राधिकारी के शिकायत ही की। प्राधिकारी

भी जाँच शुरुआत के बारे में निर्णय करते समय दूसरे देशों से हुई डंपिंग की स्वविवेक से जाँच करने के लिये बाध्य नहीं है ; अतः यह प्रथम दृष्टया स्थापित नहीं होता कि अन्य स्रोतों से आयात शुरुआत के समय डम्प की गई कीमतों पर थे। इसके अतिरिक्त गैर-विमेदन के संबंध में नियमावली के नियम 19 प्रति पाटन शुल्क लगाने के लिए तभी प्रचालनात्मक होता है "जब उत्पाद अनेक स्रोतों से डम्प किए गए उत्पाद हो" तथा केन्द्रीय सरकार कुछेक स्रोतों पर शुल्क लगाने का निर्णय करती है (इनमें कुछ स्रोतों पर शुल्क नहीं लगाया जाता)। चूंकि प्राधिकारी ने अन्य स्रोतों से आयातों की जाँच नहीं की है अतः यह नहीं कहा जा सकता कि प्राधिकारी ने विमेदकारी आधार पर जाँच की है।

ऊ समान वस्तुएं, स्थिति तथा घरेलू उद्योग

नियम 2(घ) के तहत "समान वस्तु" का अर्थ एक ऐसी वस्तु से है जो भारत में डम्प की गई वस्तु, जिसकी जाँच की जा रही है, उस वस्तु के हर तरह से समरूप अथवा समान है अथवा ऐसी वस्तु की अनुपस्थिति में ऐसी अन्य वस्तु जो यद्यपि हर तरह से समान नहीं है लेकिन जाँच की जा रही वस्तु से बहुत मिलती जुलती विशेषताएं रखती है।

समान वस्तु के बारे में निम्नलिखित तर्क दिए गए हैं।

(क) इस मामले में तुलना के लिए निर्धारित वस्तु आयातित अखबारी कागज की तुलना में देशीय रूप से मुद्रित अखबारी कागज है अतः नियमावली के तहत समान वस्तु की परिभाषा के पहला भाग लागू होता है जिसके अनुसार आवश्यकता इस बात की है कि आयातित अखबारी कागज तथा घरेलू रूप से उत्पादित अखबारी कागज "सभी प्रकार से" समान होने चाहिए। अखबारी कागज की अतः परिवर्तनीयता एक तरह है और न की सभी तरह से। गुणवत्ता, टैक्सचर तथा स्थायीत्व अन्य विशेषताएं हैं जो समानता अथवा असमानता का निर्धारण करेगी।

(ख) संयुक्त राज्य तथा यूरोपीय संघ द्वारा अपनाई गई नीति यह है कि यदि उत्पाद में अंतर के कारण कीमत समायोजन विनिर्माण की कुल लागत का 20% से अधिक होता है तो उत्पाद को समान उत्पाद के रूप में नहीं माना जाएगा। घरेलू अखबारी कागज निम्नलिखित की दृष्टि से आयातित से अलग होता है।

- * आयातित अखबारी कागज के मामले में मुद्रण समय 20% तक की कटौती
- * विनिर्माण के लिए प्रयुक्त कच्चे माल में अंतर
- * आयातित अखबारी कागज में टैक्सचर और गुणवत्ता के रूप में स्थायीत्व
- * भारतीय अखबारी कागज के उत्पादक कृषि अपशिष्ट, मुद्रित अखबारी कागज तथा अन्य घटिया कच्चे माल से अखबारी कागज का उत्पादन करता है न की लकड़ी की लुग्दी से। यह विश्वास किया जाता है कि भारत में गैर-सरकारी मिलों द्वारा उत्पादित अखबारी कागज तो आई एस आई की विशिष्टियों तक को भी पूरा नहीं करते हैं। विदेशी उत्पादकों तथा घरेलू उत्पादकों द्वारा अलग-अलग कच्चे माल का इस्तेमाल उपज के टैक्सचर तथा स्थायीत्व को प्रभावित करता है।

(ग) भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित अखबारी कागज की गुणवत्ता की तुलना सम्बद्ध देशों से आयातित अखबारी कागज से नहीं की जा सकती।

(घ) जहां तक अखबारी कागज को ग्राम्मेज का सम्बन्ध है, घरेलू कागज की मिलों में अनुरूपता नहीं है और ग्राम्मेज मानकों द्वारा अनुमत सहिष्णुता के ऊंचे स्तर पर है।

(ङ.) प्रारंभिक निष्कर्षों से इसके समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं मिलता कि याचिका घरेलू उद्योग की ओर से दायर की गई है। कनाडा के दूतावास ने प्राधिकारी से अनुरोध किया था कि वह स्थिति *** के मामले की सावधानी पूर्वक जाँच करे और सह सुनिश्चित करे कि करार के अनुच्छेद 5.4 की आवश्यकताओं को पूरा किया जाए।

प्राधिकारी की स्थिति

प्राधिकारी ने नोट किया कि कुछ उपभोक्ताओं द्वारा तर्क प्रस्तुत किए गए हैं कि कुछेक घरेलू उत्पादकों जैसे टी एन पी एल तथा एच एन एल द्वारा उत्पादित अखबारी कागज की गुणवत्ता स्वीकार्य है। तथापि इसका किसी भी इच्छुक पार्टी/पार्टियों द्वारा विरोध नहीं किया गया कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुएं सम्बद्ध देशों से आयातित वस्तुओं का वाणिज्यिक और तकनीकी दोनों ही रूपों से स्थान ले सकती हैं। प्राधिकारी ने आगे नोट किया कि सम्बद्ध देशों में उत्पादकों द्वारा प्रयुक्त कच्चा माल भी समान नहीं है। उदाहरणतया कनाडा के उपजकर्ताओं द्वारा उत्पादित अखबारी कागज में रद्दी कागज का इस्तेमाल किया जाता है। अन्य की तुलना में कच्चे माल के विशेष प्रकार की प्रयोग न तो उत्पादकों द्वारा अथवा न ही उपभोक्ता द्वारा महत्वपूर्ण कारक नहीं माना गया। यह स्थापित करने के लिए क्या घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित अखबारी कागज संबंध देशों द्वारा निर्यातित अखबारी कागज की तुलना में समान वस्तु है, प्राधिकारी ने अन्य उत्पादकों द्वारा उत्पादित अखबारी कागज की विशेषताओं की जैसे वस्तुगत विशेषताएं (आधार, रसायनिक संरचना कच्चा माल), विनिर्माण प्रक्रिया तथा प्रौद्योगिकी, कार्य तथा उपयोग, उत्पाद विशिष्टियां, कीमत निर्धारण, संवितरण तथा विपणन और वस्तुओं के वर्गीकरण को भी ध्यान में रखा। प्राधिकारी को घरेलू उद्योग अर्थात् एम पी एम, एच एन एल, टी एन पी एल तथा नेपा द्वारा उत्पादित अखबारी कागज की विशिष्टियों की तथा घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित तथा बिक्री किए गए अखबारी कागज से तुलना करना आवश्यक है। प्राधिकारी ने नोट किया कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित तथा बेचा गया अखबारी कागज संबंध देशों से निर्यातित अखबारी कागज में बहुत ही मिलती जुलती विशेषताएं हैं, यद्यपि कुछेक कारक समान नहीं। अतः प्राधिकारी ने कहा कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित अखबारी कागज सम्बद्ध देशों से निर्यातित अखबारी कागज के समान वस्तु है।

आई एन एम ए याचिका को दायर करने के लिए स्थिति के संबंध में निर्धारित शर्तों को पूरा करता है। आई एन एम ए ने याचिका दायर की है जो भारत में अखबारी कागज के विनिर्माताओं का प्रतिनिधित्व करता है। किसी भी अखबारी कागज के उत्पादक द्वारा याचिका के लिए विरोध नहीं किया और एम पी एम टी, एम पी एल, एच एन एल, नेपा का उत्पादन भारत में अखबारी कागज के कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख अनुपात होता है। एम पी एम, टी एन पी एल, एच एन एल और नेपा ने अलग-अलग हस्ताक्षर नहीं किये हैं और आई एन एम ए द्वारा दायर की गई याचिका का समर्थन किया है, परन्तु इसके साथ ही, प्राधिकारी द्वारा मांगी गई सभी जानकारी प्रस्तुत की है और प्राधिकारी द्वारा किए गए किसी सत्यापन के लिए स्वयं को प्रस्तुत करने की पेशकश भी की है।

प्राधिकारी ने याचिका को दायर करने के लिए याचिकाकर्ता की स्थिति के बारे में प्रारंभिक निष्कर्षों की पुष्टि की है तथा इस बात की भी पुष्टि की है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित अखबारी कागज विचाराधीन उत्पाद अर्थात् भारत को निर्यातित अखबारी कागज समान उत्पाद है जो नियम सुपरा के अर्थ के भीतर संबद्ध देशों के मूल को अथवा वहां से निर्यातित है।

(च) पाटन

धारा 9क(i)(ii) के तहत, वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है :—

(i) व्यापार के सामान्य क्रम में समान वस्तु के लिए तुलनात्मक मूल्य जब वह निर्यात देश या राज्य क्षेत्र के उपभोग के लिए हो, जैसा की उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार इसका निर्धारण हो, या

(ii) जब निर्यातक देश या राज्य क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार के सामान्य क्रम में समान वस्तु की कोई बिक्री न हो, या जब किसी विशेष बाजार स्थिति के कारण अथवा निर्यातक देश या राज्य क्षेत्र के घरेलू बाजार में कम बिक्री के कारण ऐसी बिक्रियों की उपायुक्त तुलना की गुंजाइश नहीं हो तब सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा :

(क) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार या निर्धारित वस्तु का तुलनात्मक प्रतिनिधि मूल्य, जब इसका निर्यात निर्यातक देश या राज्य क्षेत्र या किसी उपयुक्त तीसरे देश से किया जाए, या

(ख) उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत, जिसमें प्रशासनिक लागत, बिक्री लागत तथा सामान्य तथा लाभ के लिए उचित राशि जोड़ी गई हो इसका निर्धारण उपधारा (6) के अंतर्गत बताए गए नियमों के अनुसार किया जाता है।

जशर्त कि उद्गम वाले देश से इतर किसी अन्य देश से उक्त वस्तु के आयात के मामले, जहां वस्तु को निर्यात वाले देश से केवल जहाज से भेजा गया है या ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात वाले देश में नहीं होता है या निर्यात वाले देश में कोई तुलनात्मक मूल्य नहीं है तब सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसके सामान्य मूल्य के संदर्भ में किया जाएगा।

उठाए गए तर्क तथा सिफारिश का विरोध करने वाली पार्टियों द्वारा प्राधिकारी द्वारा उनकी समीक्षा निम्नानुसार है :—

(क) जब प्राधिकारी ने आयात मात्रा, बाजार शेयर, उत्पादन तथा क्षमता उपयोग के बारे में अप्रैल, 1996 से पूर्व आंकड़ों का उल्लेख किया, तो ऐसा कोई कारण नहीं था कि अप्रैल, 96 से पूर्व की अवधि भीतर अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमतों तथा उतार-चढ़ाव पर ध्यान नहीं दिया जाता।

प्राधिकारी की स्थिति

प्राधिकारी ने नोट किया कि पाटन मार्जिन को नियम के तहत परिभाषित किया गया है जिसमें बताया गया है कि निर्यात कीमत तथा सामान्य मूल्य के बीच वही अंतर था।

(ख) पाटन मार्जिन की जांच की अवधि में आकलन किया जाना चाहिए। घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में अनुबंध-II ने बताया कि प्राधिकारी डम्प किए गए आयात की मात्रा के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष तथा समान वस्तु के लिए घरेलू बाजार में इनका प्रभाव तथा ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के प्रभाव की जांच करेगा। नियमों में व्यवस्था की गई है कि प्राधिकारी यह विचार करेगा कि डम्प किए गए आयातों में पर्याप्त वृद्धि हुई है या इन आयातों की भारतीय बाजारों में कीमत की मंदी अथवा दबाव की पर्याप्त कटौती हुई है। प्राधिकारी को और सभी आवश्यक कारकों तथा बिक्री में कमी उत्पादन, लाभ, क्षमता उपयोग वाले सूचकांक की जांच करने की आवश्यकता है। जैसा कि पहले ही विचार-विमर्श किया गया है कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति का मूल्यांकन क्षति की अवधि के लिए माना जाना चाहिए जो पाटन अवधि से अधिक होती है।

ख. डंपिंग मार्जिन का निर्धारण प्रत्येक निर्यातक और आयातक के बारे में किया जाना चाहिए कि आयात का प्रत्येक कारोबार एक समान हो अथवा न हो।

प्राधिकारी की स्थिति

इस बात के तर्क उठाए गए हैं कि प्राधिकारी प्रत्येक निर्यातक के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण न करें और प्रत्येक देश के लिए एक ही सामान्य मूल्य का निर्धारण करना चाहिए। तथापि प्राधिकारी ने नोट किया कि सामान्य मूल्य कानून के तहत सुपरिभाषित किया गया है तथा उसके अनुसार उसका निर्धारण किया जाना चाहिए। पाटन निर्यातक विशिष्ट है और नियमों में इस बात की अपेक्षा की जाती है कि प्राधिकारी प्रत्येक ज्ञात निर्यातक के लिए अलग-अलग पाटन मार्जिन का निर्धारण करे। अतः प्राधिकारी ने प्रत्येक सहयोगी निर्यातक के लिए अलग से पाटन मार्जिन निर्धारित किया है।

ग. यू. एस. ए. की अपेक्षा थी कि अखबारी कागज की मांग में पर्याप्त रूप से वृद्धि होगी जो न हो सकी। यू. एस. ए. तथा कनाडा में मिलों द्वारा नियोजित अधिक उत्पादन को प्रतिযোগी कीमतों पर, एशिया के बाजारों को छोड़कर, नहीं बेचा जा सकता।

प्राधिकारी की स्थिति

प्राधिकारी को कम निर्यात कीमतों के कारणों की जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्राधिकारी को कानून के अनुसार पाटन की मौजूदगी की जांच करने की आवश्यकता है अधिक उत्पादन के कारण कम निर्यात कीमत के बारे में तर्क पाटन के सम्बंध में स्थिति को बदल नहीं सकते।

घ. प्राधिकारी ने अपने निष्कर्ष अन्य बातों के साथ-साथ न्यूयार्क में जर्मनल में प्रकाशित कीमतों के आधार पर दिए हैं।

प्राधिकारी की स्थिति

यह विवाद गलत है और वास्तविक स्थिति प्रारंभिक निष्कर्षों तथा इन निष्कर्षों में, दी गई है। प्राधिकारी ने निर्यातकों द्वारा किए गए दावों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है तथा उसके बाद प्राधिकारी ने इनका सन्धान किया है।

ङ. थरेलू उद्योग ने 727 अमरीकी डालर की पोतपर्यन्त निशुल्क निर्यात कीमत पर 1995-96 में थाईलैंड को निर्यात किया था। इससे पता चलता है कि भारत में थरेलू कीमत को ध्यान में रखे बिना भारतीय अखबारी कागज के उत्पादक को प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर या उनके लगभग पर निर्यात करना पड़ता है। यही स्थिति भारत में 1996-97 में भी आयातों के संबंध में थी।

प्राधिकारी की स्थिति

भारतीय उद्योग द्वारा थाईलैंड को निर्यात की गई कीमत या थाईलैंड में प्रचलित कीमत पाटन की मौजूदगी का निर्णय करने के लिए आवश्यक है।

च. बेकर ने कहा कि 1996 में कनाडा से 180,000 मी० टन के निर्यात हुए जो सोलाका मस (जिसने 40,000 मी० टन का निर्यात किया) द्वारा भेजी गई मात्रा से 4-5 गुना अधिक थे। इसके परिणामस्वरूप निर्यातक ने तर्क किया कि कनाडा से निर्यातकों ने भारतीय बाजार में आयातित अखबारी कागज के लिए कीमतों के स्तर को सुपरिभाषित किसी है। निर्यातक ने फिर कहा कि कंपनी द्वारा उत्पादित कागज की गुणवत्ता में मौजूदा अंतरों, कनाडा और यू. एस. ए. से निर्यातकों द्वारा उत्पादित कागज तथा दी गई सेवाओं के स्तर की दृष्टि से निर्यात द्वारा कीमतों में वृद्धि के लिए गए सभी प्रयास विफल रहे।

प्राधिकारी की स्थिति

प्राधिकारी ने नोट किया कि पाटन संबंधी कार्य न कि उसके कारण मौजूदा जांच का प्रयोजन है।

छ. लुग्दी तथा कागज के उत्पादों के लिए कीमतों में पर्याप्त कमी हुई है। जिसके परिणाम स्वरूप अखबारी कागज की कीमतों में कमी हुई है।

प्राधिकारी की स्थिति

जैसा की प्रारंभिक निष्कर्षों में ऊपर दिया गया है, पाटन का कार्य और न की उसके कारण मौजूदा जांच का प्रयोजन है। लुग्दी की कीमतों में कमी से उत्पादन की लागत पर प्रभाव पड़ेगा तथा जो समान रूप से दोनों बाजारों अर्थात् भारत को निर्यात तथा आंतरिक बाजार में बिक्री पर लागू होगा।

ज. प्रतिपादन शुल्क सामान्य तथा धारा 9क (ख) में उल्लिखित केवल कुछ परिस्थितियों को छोड़कर भावी आधार पर होता है। यह न याचिकाकर्ताओं का मामला था और न ही प्राधिकारी के निष्कर्ष का यह तथ्य तथा परिस्थितियों धारा 9क (ख) के अनुसार है। इन परिस्थितियों में प्राधिकारी केवल उस तारीख को पाटन की मौजूदगी के संबंध में निष्कर्ष दर्ज कर सका जब उन्होंने अपने निष्कर्ष दिए कि पिछली अवधि में कोई पाटन हुआ था। परिस्थितियों में परिवर्तन को ध्यान में रखना पड़ा और निष्कर्ष पर पहुंचते समय उनको नकारा नहीं जा सकता था।

प्राधिकारी की स्थिति

न. यह तर्क कानूनी रूप से युक्ति संगत है। प्राधिकारी को जांच की अवधि के दौरान पाटन की मौजूदगी के बारे में निष्कर्ष देने की आवश्यकता है। जैसा कि इन निष्कर्षों में कहीं दिया गया है कि जांच की अवधि के बाद के कारक पाटन की मौजूदगी का निर्णय करने के लिए आवश्यक है और यदि पिछली जांच की अवधि के कारक वास्तव में बदल जाते हैं इच्छुक पार्टी/ पार्टियों कानून के अनुसार समीक्षा के लिए अनुरोध कर सकती हैं। इच्छुक पार्टी/पार्टियों का तर्क युक्तिसंगत है। क्रियाविधिक, संकल्पनात्मक रूप से तथा तरीके के अनुसार निष्कर्ष को दर्ज करने की तारीख पर पाटन संबंधी निष्कर्ष देने के लिए तर्कसंगत है।

झ. मौजूदा परिस्थितियों में अखबारी कागज की प्रतिनिधि कीमत, जब उक्त देशों से उनका निर्यात किया जाता है अथवा उपयुक्त तृतीय देश उत्पादन की लागत के सामान्य मूल्य के रूप में लिया जाना चाहिए। वह कीमत जिस पर अखबारी कागज को संबंध देशों से निर्यात किया जाता है, वह लगभग उसी कीमत पर होता है जिससे अन्य यूरोपीय देशों से आयात किए जाते हैं। वर्तमान मामला ऐसा मामला नहीं है जहां निर्यातक देश के थरेलू बाजार में कोई बिक्री न हो अथवा बिक्री की मात्रा कम हो। यह ऐसा मामला है कि जहां बाजार की स्थिति बड़ी विचित्र है अतः थरेलू बिक्री उचित तुलना की अनुमति नहीं देती है। सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के बारे में समस्त दृष्टिकोण ही गलत है और जो अधिनियम के अनुसार नहीं है।

प्राधिकारी की स्थिति

यह तर्क कानूनी रूप से युक्तिसंगत है। वह कीमत जिसमें अखबारी कागज का निर्यात तृतीय देश से किया जाता है, संबंध देशों से पाटन के निर्धारण पर निर्णय लेने के लिए आवश्यक नहीं है। पाटन के लिए संबंध देश/देशों में केवल निर्यातक का सामान्य मूल्य तथा निर्यातक कीमत ही आवश्यक

है। जहाँ तक सामान्य मूल्य के निर्धारण का संबंध है सम्बंधित पार्टियों ने इस बारे में कुछ नहीं कहा कि धारा 9 के तहत सामान्य मूल्य की परिभाषा को क्यों स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, तथा विशेष बाजार स्थिति का मामला क्या है।

भारत में अखबारी कागज की खपत की विश्व की मांग का 1.2% से अधिक नहीं है अतः निर्यातक के लिए भारत में अपने माल को पाटन करने का कोई कारण नहीं।

प्राधिकारी की स्थिति

प्रतिपाटन उपबंधों के तहत व्यापार की मात्रा के प्रभाव की समीक्षा आयातक देश के घरेलू बाजार (आयात सहित) के संदर्भ में की जानी चाहिए और विश्व मांग की तुलना में अखबारी कागज की खपत के संदर्भ का कोई महत्व नहीं।

घ. ऐबीटीबी से आयात संविदाकारी करार (दीर्घावधि) आधार पर थे जिसके यू एफ बाजार संपादित कीमत के साथ निश्चयात्मक संबंध थे। अतः ऐबीटीबी द्वारा पाटन का कोई प्रश्न नहीं।

प्राधिकारी की स्थिति

जैसा कि प्रारंभिक विष्कर्षों में बताया गया है, यह तर्क अनावश्यक है। इसके अतिरिक्त यह दावा कि ऐबीटीबी से आयात संविदाकारी करार के आधार पर है, भी सही नहीं है चूंकि ऐबीटीबी ने अनेक पार्टियों को निर्यात किए थे जिनके दीर्घावधि संविदाएं नहीं थी।

च. रूस में अखबारी कागज की घरेलू कीमत उत्तरी अमरीका की कीमतों से अधिक नहीं रही है।

प्राधिकारी की स्थिति

मौजूदा जांच का निर्णय करने के लिए यह तर्क अनावश्यक है। रूस में अखबारी कागज की कीमत तथा रूस को निर्यात किए गए अखबारी कागज की कीमत रूस द्वारा पाटन का निर्णय करने के आवश्यक कारक हैं और उत्तरी अमरीका में प्रचलित कीमतें आवश्यक नहीं हैं।

छ. सही उत्पादन आयोजना, विपणन, ग्राहक के समर्थन के कारण विदेश की मिलें कम कीमतों पर बिक्री कर सकीं।

प्राधिकारी की स्थिति

प्राधिकारी के पास उपलब्ध साक्ष्य से पता चलता है कि कनाडा और यू एस ए से निर्यातकों की लाभप्रदता जांच अवधि के दौरान बहुत कम हो गई और इन देशों में कुछेक निर्यातकों दोनों बाजारों अर्थात् भारत को निर्यात तथा आंतरिक बाजार में बिक्री को क्वाटर 4, 1996 में उत्पादन की लागत के बहुत ही कम कीमतों पर बेचने को बाध्य होना पड़ा तथापि इच्छुक पार्टी/पार्टियों का तर्क मौजूदा जांच का निर्णय के लिए अनावश्यक है। आवश्यक कारक सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत ही है।

पाटन का निर्धारण

पाटन सीमा के निर्धारण के लिए अपनाई गई प्रक्रिया और विशेष निर्यातकों के मामले में प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत दावे निम्नानुसार हैं :

स्टोन कंसोलिडेटेड

निर्यात कीमत

प्राधिकारी द्वारा भेजी गई प्रश्नावली के उत्तर में निर्यातकों ने सी एंड एफ कीमत, कमीशन अन्तर्देशीय/समुद्री भाड़ा और कारखानागत से पत्तन तक के आन्तरिक भाड़े के साथ-साथ भारत को निर्धारित अखबारी कागज की मात्रा का माहवार विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। स्थल जांच के दौरान निर्यातकों ने जांच अवधि में प्रत्येक महीने में हुई विदेशी बिक्री का विवरण प्रस्तुत किया जिसमें अखबारी कागज का स्तर, निर्यातक ने किसे निर्यात किया, पोतलदान की गई अखबारी कागज की मात्रा, इकाई कीमत, भाड़ा, कमीशन और निवल बिक्री मूल्य दर्शाया गया था।

मै. जे सागर एंड एसोसिएट्स के जरिए प्रश्नावली का उत्तर भेजते समय स्टोन कंसोलिडेटेड ने परिशिष्ट 3(क)(2) के अधीन उल्लेख किया था कि विदेशी भाड़े की राशि ***** थी। परिशिष्ट 3(क)(2) भारत को की जाने वाली निर्यात बिक्री के मूल्य ढांचे से संबंधित है और जिसमें निर्यातक को उनके द्वारा कारखानागत निर्यात मूल्य का दावा किए जाने वाले समायोजन के साथ सूची मूल्य देना होता है।

यह नोट करना प्रासंगिक होगा कि प्राधिकारी द्वारा भेजी गई प्रश्नावली से यह स्पष्ट है कि निर्यात मूल्य के समायोजन के दावे को निर्यातक द्वारा किए गए वास्तविक व्यय पर आधारित होना चाहिए। निर्यातक द्वारा किए गए व्यय के उचित दावे के बावजूद मै. जे सागर एसोसिएट्स के प्रतिवेदन में कहा गया है कि भाड़े का दावा परिशिष्ट 3(क)(2) के अंतर्गत विदेशी भाड़े के लिए किया गया है। प्राधिकारी का मानना था कि यह राशि निर्यातक द्वारा समुद्री भाड़े पर खर्च की गई वास्तविक रकम है। यह नोट किया गया कि परिशिष्ट 3(क)(2) में वर्णित विदेशी भाड़े का घटक "स्टोन कंसोलिडेटेड" द्वारा निर्यातित ग्रेड अखबारी कागज के क्रेता के ब्यौरे से मेल नहीं खाता था, जो कंपनी द्वारा पुनरीक्षा के समय प्रस्तुत किया गया था। न ही इसे जांच दल के दौरे के बाद निर्यातक द्वारा प्रस्तुत दिनांक 29-10-97 की जांच रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया। तथापि स्पष्टीकरण वाले बयान के बाद मै. जे. सागर एंड एसोसिएट्स ने एक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया कि स्टोन कंसोलिडेटेड द्वारा प्रस्तुत "कस्टमर बाई ग्रेड एक्सपोर्ट्स स्टेटमेंट" से केवल सांकेतिक समुद्री भाड़े का पता चलता है। बाद की तारीख में निर्यातक का यह दावा करना कि उसने केवल प्रतीकात्मक भाड़े का दावा किया था, हताशावाला और भ्रामक है खासकर तब जब कि न तो प्रश्नावली के जबाब में ऐसा कोई संकेत दिया गया था और न ही जांच अवधि से पहले ही कभी ऐसा किया गया। निर्यातक के दावे को स्वीकार नहीं

किया जा सकता क्योंकि निर्यातक ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया था जिसका भारतीय नागरिकों को समग्र बिक्री के लिए यूनिवर्सल को की गई आपूर्ति से कोई संबंध हो। लदान के चार बिलों की छायाप्रति से यूनिवर्सल के लदानकर्ता होने का पता चलता है किन्तु जघाब में या जांच दल को खेपों के वजन के संबंध में कोई वास्तविक जानकारी नहीं दी गई थी। निर्यातक ने इस तरह का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया था जिससे यह प्रमाणित हो सके कि

***** के अंतर को स्टोन कंसोलिडेटेड की लेखा बही में डाल दिया गया था। समुद्री भाड़े के घटक के कारण

** की बचत से संबंधित

अपने दावे के पक्ष में भी जांच दल को कोई साक्ष्य नहीं दिखाया गया है। दिनांक 13-11-1997 के अपने उत्तर में जे सागर एंड एसोसिएट्स का यह दावा कि कम भाड़े का मुद्दा जिसे ग्राहक बनने में यूनिवर्सल सक्षम था, जिसे मान्द्रियल में जांच दल को स्पष्ट किया गया था, वह भ्रामक है। इसके विपरीत, जांच दल ने निर्यातकों और जे. सागर एंड एसोसिएट्स के प्रतिनिधियों श्री पी एल एवं श्री आर पी जो जांच दल की सहायता कर रहे थे, को स्पष्ट रूप से बताया था कि निर्यात मूल्य में समायोजन के तौर पर कम भाड़े का लाभ प्राप्त करने के दावे को देखते हुए हमें स्टोन कंसोलिडेटेड की लेखा बही में बचत का पता लगाना होगा। निर्यातक का स्वेच्छा तैयार करने की पद्धति इस प्रकार है कि ग्राहकों को दी गई अतिरिक्त रियायत (जिसका भुगतान संदर्भ अवधि में ग्राहक द्वारा की गई खरीद की मात्रा निर्धारण के बाद अवधि के अंत में किया गया है), को भी ब्यौरे में समायोजित कर लिया गया है। इस परिस्थिति में निर्यातक का यह दावा कि उसने ब्यौरे में "सांकेतिक" व्यय के लिए दावा किया था और इसे समुद्री भाड़े के भुगतान के बाद ठीक नहीं किया गया) को नहीं माना जा सकता है। चूंकि इस साक्ष्य को किसी समय जांच के समय तक भी या उसके बाद भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसलिए प्राधिकारी निर्यातक के इस दावे को केवल एक ऐसा बयान भ्रामक जिसके समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है, अस्वीकार करने के लिए बाध्य है।

चूंकि स्थल जांच के समय निर्यातक द्वारा प्रस्तुत विवरण से यह पता चलता है कि निर्यातक द्वारा अपने क्रियाकलापों के संबंध में रिकार्ड रखा गया है इसलिए विदेशी बिक्री के इस विवरण के आधार पर निर्यात कीमत पर विचार किया गया है और चूंकि विवरण से रियायत भाड़े और अन्य शुल्कों के समायोजन के बाद कारखानागत निवल मूल्य का पता चलता है इसलिए इसे निर्यात मूल्य के रूप में मानने का प्रस्ताव किया जाता है।

कमीशन : प्रश्नावली के उत्तर में निर्यातक ने तर्क दिया कि वह मै. यूनिवर्सल पेपर निर्यात कंपनी को कारखाना में निवल कमीशन देता है और उन सभी निर्यातों पर वह कमीशन दिया जाता है जिसका उसने सीधे-निर्यात किया है या यूनिवर्सल के माध्यम से किया है। सामान्य मूल्य निर्धारण के लिए निर्यातक ने घरेलू बाजार में बिक्री मूल्य से एस जी ए आधार पर समायोजन का दावा किया है। तथापि स्थल जांच के दौरान यह पाया गया था कि एस जी ए के संबंध में निर्यातक का दावा दोनों बाजारों अर्थात् घरेलू बाजार और भारत को किए गए निर्यातों के कारण हुए व्यय में अंतर पर आधारित नहीं है। तथापि निर्यातक ने स्थल जांच के बाद तर्क दिया कि सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य में निष्पक्ष तुलना करने के लिए यूनिवर्सल को दिए गए कमीशन के लिए निर्यात मूल्य को समायोजित नहीं किया जाना चाहिए। रिकार्ड में मौजूद तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि स्टोन कंसोलिडेटेड ने भारत को किए गए अपने निर्यातों के लिए कमीशन का भुगतान किया था इसलिए निर्यात कीमत का निर्धारण कमीशन के समायोजन के बाद करना होगा।

प्राधिकारी इस बात को स्वीकार करते हैं कि निर्यातक सामान्य मूल्य को निर्धारित करने के लिए समायोजन के तौर पर उस व्यय का दावा करने का हकदार है जो कि उसे पूर्ण रूप से घरेलू बाजार में बिक्री के कारण करना पड़ा है यह तर्क कि चूंकि सामान्य मूल्य में समायोजनों के रूप में किसी एसजी ए व्यय का दावा नहीं किया गया है इसलिए निर्यात मूल्य के निर्धारण के लिए कमीशन को नहीं घटाया जाना चाहिए, स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निर्यात मूल्य और सामान्य मूल्य का निर्धारण कीमत तुलनीयता को प्रभावित करने वाले सभी कारकों के लिए किया जाना अपेक्षित है जो साक्ष्य के आधार पर प्रत्येक में उचित समायोजन करने के बाद एक दूसरे से बिलकुल अलग-अलग होंगे।

उधार बिक्री : चूंकि भारत को किए जाने वाले निर्यात की तुलना के घरेलू बाजार में बिक्री निम्नतर उधार शर्तों पर होती है इसलिए प्राधिकारी ने निर्यात के मामले में अवधि के विभेदी ऋणों के आधार पर उच्चतर ऋण के लिए समायोजन किया है।

ऊपर निर्धारित किए गए निर्यात मूल्य को कारखानागत निर्यात मूल्य के रूप में माना गया है।

सामान्य मूल्य

निर्यातक ने घरेलू बाजार में की गई बिक्री के ग्राहक-वार एक ब्यौरे के साथ एवं विस्तृत बीजक/सौदावार और ग्राहक-वार बिक्रियों का ब्यौरा प्रस्तुत किया है जिसमें बेचे गए अखबारों का गज का स्तर, आदेश संख्या, बीजक संख्या और तारीख, पोतलदान की गई समग्र मात्रा, इकाई मूल्य, बिक्री मूल्य की राशि, भाड़ा, रियायत, कमीशन, अन्य खर्च एवं प्राप्त राशि भी दी गई हैं। माह जुलाई और अगस्त 1996 के ब्यौरों की व्यापक जांच से प्रकट होता है कि प्रश्नावली के उत्तर में निर्यातक द्वारा दावा की गई रियायत का स्थल जांच की प्रक्रिया के दौरान निर्यात द्वारा विस्तृत बिक्री ब्यौरे में दी गई रियायत की राशि के साथ मेल नहीं खाता है। निर्यातक द्वारा घरेलू बिक्री के लिए दिए गए बिक्री कीमत ढांचे के ब्यौरे में स्थल जांच के बाद संशोधित किया गया और उसने स्पष्ट किया कि मूल प्रश्नावली के उत्तर में दर्शाई गई रियायत की राशि में गैर-बीजक रियायत भी शामिल है। निर्यातक ने आगे यह भी स्पष्ट किया कि गैर-बीजक रियायत बाद में साख पत्र द्वारा कनाडा में बड़े ग्राहकों को दी गई थी (अर्थात् वस्तुओं की बिक्री के समापन के बाद) और खरीद के समय ग्राहकों को रियायत की उपलब्धता की जानकारी थी।

मात्रा रियायत : निर्यातक ने दावा किया कि भारत को उसका निर्यात शुरू में दो ग्राहकों मै. बेनेट कोलेमन और दक्षिण भारत में उपभोक्ताओं के एक संघ को किया गया था। इन ग्राहकों को की गई बिक्री की मात्रा बहुत बड़ी होने के कारण निर्यातक ने इस आधार पर (*****) के समायोजन का दावा किया है। इस आधार पर निर्यातक द्वारा प्रारंभिक जांच परिणाम के बाद दावा किया गया है तथापि निर्यातक ने स्थल जांच के बाद और स्पष्टीकरण वाले बयान के उत्तर में तर्क दिया कि प्राधिकारी बड़े ग्राहकों को की गई बिक्री मूल्य के आधार पर ही सामान्य मूल्य का निर्धारण कर सकता है।

निर्यातक द्वारा किए गए दावे की छानबीन से पता चलता है कि निर्यातक ने घरेलू बाजार में अपने छोटे और बड़े ग्राहकों को अभिज्ञात किया है। जांच अवधि के दौरान निर्यातक के पास घरेलू बाजार में एक बड़ा और आठ छोटे ग्राहक थे। निर्यातक ने इन छोटे ग्राहकों के लिए एक औसत बिक्री मूल्य निर्धारित किया है और इसी का उपयोग अपने छोटे और बड़े ग्राहकों के बिक्री मूल्य में अंतर की गणना के लिए किया गया है। छोटे और बड़े ग्राहकों के

लिए बिक्री मूल्य में अंतर पर विचार करते हुए निर्यातक ने इसके लिए

(*****) के समायोजन का दावा किया है।

मात्रा रियायत के संबंध में निर्यातक का दावा स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्राधिकारी को सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य का निर्धारण तुलनीय स्तर पर करना होता है तथापि प्राधिकारी यह मानते हैं कि बड़ी निर्यात मात्राओं को देखते हुए सामान्य मूल्य के रूप में बड़े ग्राहकों के लिए बिक्री मूल्य विचार किया जाना चाहिए। यद्यपि निर्यातक घरेलू बाजार में बिक्री मूल्य निर्धारण के लिए अपनाई जाने वाली क्रियाविधि के संबंध में एकमत नहीं है और उन्होंने अलग-अलग दावे किए हैं तथापि प्राधिकारी इसे उचित मानते हैं कि बड़े ग्राहकों के लिए जो मूल्य है उसके आधार पर बिक्री मूल्य निर्धारित किए जाएं। इस लिए प्राधिकारी ने बिक्री मूल्य का निर्धारण घरेलू बाजार में बड़े ग्राहकों के लिए बिक्री मूल्य के आधार पर जांच अवधि के दौरान प्रत्येक माह के लिए किया है और निर्यातक द्वारा किए गए दावे के आधार पर छोटे ग्राहकों को की गई बिक्री को महत्व नहीं दिया है। छूट की स्वीकृति बीजक बनाते समय दी गई वास्तविक छूट के आधार पर दी गई है। निर्यातक द्वारा दिए गए शाख-पत्रों के रूप में बिक्री पश्चात् दी गई छूट को स्वीकृति नहीं दी गई है क्योंकि इस आशय का कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है जिससे कि बिक्री किए जाने या उसकी मात्रा के निर्धारण हो सके।

भाड़ा : निर्यातक ने निर्यातक द्वारा प्रत्येक बिक्री के लिए किए गए भाड़े के भुगतान के आधार पर भाड़े का दावा किया है जिसके ब्यौरे मदवार बिक्री ब्यौरे में दिए गए हैं। दावा किए गए भाड़े की स्वीकृति दी गई है।

समतुल्य भाड़ा : निर्यातक ने समतुल्य भाड़े के आधार पर समायोजन का दावा किया है जिसमें निर्यातकों द्वारा अखबारी कागज के भंडारण और कारखाना से भंडारगृह तक दुलाई पर खर्च किए गए भाड़े पर हुआ व्यय शामिल है। निर्यातक ने इस बात को कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि कनाडा के ग्राहकों को माल निर्यातकों ने अपने पास मौजूद भंडार गृहों से भेजा है जबकि इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि यू. एस. के ग्राहकों को इन भंडारगृहों से माल भेजा गया है। भंडारण लागत (भंडारगारण) के लिए समायोजन की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि इसे मूल्य में अंतर के लिए उत्तरदायी मानते हुए न तो उत्पादन लागत में शामिल किया जा सकता है और न ही इसे दोनों बाजारों में से किसी बाजार में बिक्री के मामले में किए गए किसी कार्य या क्रियाकलाप से जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा निर्यातक ने इस प्रयोजन से कनाडा में की गई बिक्री पर हुए व्यय (भाड़ा सहित) को अलग नहीं किया है। इसलिए समतुल्य भाड़े के लिए समायोजन की अनुमति नहीं दी गई है।

बिक्री-व्यय, सामान्य व्यय और प्रशासनिक व्यय : स्थल जांच के दौरान यह पाया गया कि निर्यातक द्वारा इसके लिए किया गया दावा निर्यातक द्वारा सेवाओं के लिए किए गए एस. जी. ए. व्यय पर आधारित है जो या तो दोनों क्रियाकलापों में उभयनिष्ठ है (भारत को निर्यात और घरेलू बाजार में बिक्री) या उनमें से किसी से इसका सीधा सम्बन्ध नहीं है। निर्यातक दावा किए गए एस. जी. ए. व्यय के लिए यह प्रमाण नहीं दे सके कि यह खर्च केवल घरेलू बाजार में की गई बिक्री पर हुआ है। चूंकि निर्यातक ने इस प्रयोजन से किए गए व्यय का ब्यौरा स्थल जांच के बावजूद भी नहीं दिया है इसलिए इसके लिए कोई समायोजन संभव नहीं है।

सतत/खेपों में उत्पादन : निर्यातक ने भारत को निर्यात के मामले में सतत उत्पादन की तुलना में घरेलू बाजार में बिक्री के लिए खेपों में उत्पादन के लिए समायोजन का दावा किया था। निर्यातक ने इस के लिए कोई सत्यापन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निर्यातक ने इस प्रयोजन के लिए प्रारंभिक जांच परिणाम के बाद किसी समायोजन के लिए दबाव दिया है (प्राधिकारी ने इसे प्रारंभिक जांच परिणाम में अस्वीकार कर दिया था)। उपरोक्त के संदर्भ में, प्राधिकारी ने इस आधार पर अंतिम जांच परिणाम में भी किसी समायोजन पर विचार नहीं किया है।

उपर यथानिर्धारित सामान्य मूल्य को कारखानागत सामान्य मूल्य के रूप में स्वीकार किया गया है।

(II) एबीटीबी कीमत, कनाडा :

निर्यात कीमत

निर्यातक ने भारत को किए गए निर्यातों का सौदा-वार ब्यौरा अखबारी कागज को समुद्र-पार कुल बिक्री प्रस्तुत किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निर्यातित अखबारी कागज की मात्रा, इकाई कीमत, कुल बिक्री मूल्य रियायत और भाड़ा (अन्तर्देशीय और विदेशी) का ब्यौरा दिया है। इनमें से प्रत्येक रिपोर्ट में कनाडा के सभी कारखानों से विश्व के विभिन्न देशों में अखबारी कागज के लिए गए निर्यात का क्षेत्रवार ब्यौरा दिया गया है। सभी मिलों की रिपोर्ट के समर्थन में प्रत्येक मिल द्वारा विदेशों में की गई अखबारी कागज की बिक्री का विवरण संलग्न था। भारत को निर्यात चांदलर और ग्रांड फाल्स द्वारा किया गया था। निर्यात कीमत का निर्धारण इस विवरण के आधार पर किया गया है। कमीशन और भाड़े के लिए समायोजन को भी समुद्र-पार अखबारी कागज को कुल बिक्री के ब्यौरे में दर्शाए गए वास्तविक व्यय के आधार पर स्वीकृति दी जाती है।

उधार बिक्री :

चूंकि भारत को निर्यात की तुलना में घरेलू बाजार में बिक्री निम्नतर ऋण शर्तों पर होती है इसलिए प्राधिकारी ने विभेदी ऋण अवधि और ब्याज दर के आकार पर निर्यात के मामले में उच्चतर ऋण के लिए एक समायोजन किया है।

उपरोक्त निर्धारित निर्यात मूल्य को कारखानागत निर्यात मूल्य के रूप में स्वीकार किया गया है।

सामान्य मूल्य

निर्यातक ने घरेलू बाजार में बिक्री मूल्य का दावा बीजक-वार सूचीकरण के विस्तृत ब्यौरे के आधार पर किया है जिसमें सकल बिक्री मूल्य छूट, भाड़ा और निवल बिक्री मूल्य की राशि दी गई है। बिक्री मूल्य का निर्धारण बिक्री के समय दी गई छूट और भाड़े पर वास्तविक व्यय को घटाकर किया जाता है।

अतिरिक्त छूट

ग्राहक द्वारा अखबारी कागज की खरीद की मात्रा के संबंध में कुछ शर्तों को पूरा करने पर माल की बिक्री के बाद निर्यातक ने शाख पत्रों के जरिए अतिरिक्त रियायत दी है। चूंकि बिक्री की समय भार या मात्रा किसी रूप में अतिरिक्त राशि का पता नहीं था, इसलिए प्राधिकारी ने अतिरिक्त छूट के दावे को मंजूर नहीं किया है।

परिणाम में रियायत : निर्यातक ने दावा किया है कि भारत को निर्यात बड़े परिमाण (15000-20000 मी. टन) में किया गया है। घरेलू बाजार में बिक्री के मामले में लगभग 1000 मी. टन औसत वाले छोटे ग्राहकों की तुलना में एक बड़े ग्राहकों ने 30000 मी. टन माल उठाया। इसलिए निर्यातक ने घरेलू

बाजार में छोटे और बड़े ग्राहकों के बिक्री मूल्यों में अंतर के कारण (****) के समायोजन का दावा किया है।

प्राधिकारी ने नोट किया है कि कंपनी ने जांच अवधि के दौरान एक लम्बी अवधि तक घरेलू बाजार में बड़ी मात्रा में और लाभ पर बिक्री की है तथापि कंपनी को लाभप्रदता 1996 की प्रत्येक तिमाही में घटती गई जो इस हद तक घटी कि कंपनी वर्ष 1996 को चौथी तिमाही में प्रथम तिमाही 1996 में हुए पर्याप्त लाभ की तुलना में विपरीत क्षति हुई।

जहां तक बड़े ग्राहकों का संबंध है प्राधिकारी को ए बी टी बी के मामले में भी सामान्य मूल्य का निर्धारण उसी आधार पर करना था जिस आधार पर स्टोन कंसोलिडेटेड के मामले में किया गया है। ए बी टी बी ने कभी भी इस तरह से निर्धारण का दावा स्पष्टीकरण के बावजूद भी नहीं किया है (हालांकि स्टोन कंसोलिडेटेड और ए बी टी बी के मामले में एक ही कंपनी अर्थात् ए बी टी बी कंसोलिडेटेड इंक द्वारा ही प्रत्युत्तर दर्ज किया था और न ही कंपनी ने जांच अवधि के किसी महीने में बड़े ग्राहकों के मूल्य को उजागर किया। बड़े ग्राहकों को की गई माहवार बिक्री का पूरा ब्यौरा भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसलिए प्राधिकारी बड़े ग्राहकों को की गई बिक्री के आधार पर बिक्री मूल्य का निर्धारण करने से बचता है। इसलिए प्राधिकारी ने घरेलू बाजार के लिए बिक्री का मूल्य का निर्धारण घरेलू बाजार में कुल बिक्री के आधार पर किया है।

मात्रा रियायत से संबंधित निर्यातक के दावे को मंजूर नहीं किया गया है क्योंकि सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए माना गया बिक्री मूल्य छोटे ग्राहकों तथा बड़े ग्राहकों के औसत भारत मूल्य पर आधारित है और इसीलिए बड़े ग्राहकों के अपेक्षाकृत कम मूल्य पर की गई बिक्री में पहले ही इसका समायोजन कर दिया गया है। प्राधिकारी ने नोट किया कि निर्यातक ने भी पाटन सीमा का गणना "मात्रात्मक रियायत को ध्यान में रखे बिना" की है।

एस जी एंड ए खर्चों के लिए कटौती : ए बी टी बी ने बिक्री, व्यव सामान्य व्यव और इसके लिए तर्क वहाँ दिया है जो कि स्टोन कंसोलिडेटेड के मामले में दिया है। निर्यातक इस आशय का उपयुक्त सत्यापन देने में असमर्थ रहा है कि दावा किया गया एस जी ए व्यव विशेष रूप से घरेलू बाजार में की गई बिक्री के लिए हुआ है। चूंकि निर्यातक ने दोनों बाजारों में विशेषकर इस कारण से हुए व्यव के ब्यौरे स्थल जांच के बाद भी नहीं दिए हैं इसलिए इस बारे में कोई समायोजन संभव नहीं है।

उपरोक्त निर्धारित सामान्य मूल्य को कारखाना गत सामान्य मूल्य के रूप में माना गया है।

(iii) ए बी टी बी कीमत, यू एस ए : ए बी टी बी ने कनाडा में स्थल जांच के समय संकेत दिया कि यू एस कंपनी की मिलों के संबंध में उन्हें और अधिक जानकारी नहीं देनी है और कंपनी जांच में आगे सहयोग करने में इच्छुक नहीं दिखाई देती है इसीलिए प्राधिकारी ने जैसा कि प्रारंभिक जांच परिणाम में किया गया है उसी आधार पर सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए कार्यवाही की है।

(iv) एवनर मेरीटाइम्स : एवनर मेरी टाइम्स के मामले में भारत को निर्यात एवनर इंक द्वारा किया गया है जबकि अखबारी कागज एवनर मेरीटाइम्स के द्वारा निर्मित किया गया था जो कंपनी की सहायक इकाई है। एवनर के पास भी अनेक मिलें हैं जो अखबारी कागज का निर्माण कर रही हैं तथापि कंपनी ने दावा किया कि एवनर इंक और एवनर मेरीटाइम्स का अलग-अलग वैधानिक अस्तित्व है और एवनर इंक के क्रियाकलाप को एवनर मेरीटाइम्स से नहीं जोड़ा जा सकता है।

निर्यात कीमत:

एवनर ने भारत को भेजे गए अखबारी कागज का सौदेवार विस्तृत ब्यौरा दिया है। निर्यातक द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि ब्यौरे रद्दी अखबारी कागज सहित स्टैंडर्ड अखबारी कागज का लदान भी शामिल था।

भारत को रद्दी और अच्छे अखबारी कागज की बिक्री का विश्लेषण निम्नानुसार है:-

*भारत को किए गए निर्यातों की तारीखवार व्याख्या से यह स्पष्ट होता है कि लगभग एक ही समय में रद्दी और अच्छे अखबारी कागज की बिक्री कीमत अलग-अलग है। उदाहरण के लिए, रद्दी अखबारी कागज की बिक्री मूल्य अप्रैल माह में अच्छे अखबारी कागज के बिक्री मूल्य की तुलना में था तथापि जुलाई महीने में अंतर था और सितम्बर महीने में। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला गया कि यद्यपि रद्दी और अच्छे अखबारी कागज के बिक्री मूल्य में अंतर था लेकिन यह अंतर एक समान नहीं था।

*भारत को किए गए निर्यातों की तारीखवार व्याख्या से यह स्पष्ट होता है कि अच्छे अखबारी कागज के मूल्य में (अप्रैल 1996) से (सितम्बर 96) तेजी से गिरावट आई है। रद्दी अखबारी कागज के मामले में मूल्य (अप्रैल 96) से (सितम्बर, 96) तक गिर गया।

भारत को किए गए निर्यात की ग्राहक-वार और तारीखवार व्याख्या से पता चलता है कि इस सुझाव का कोई परस्पर सम्बन्ध नहीं है कि भारत ने अच्छे अखबारी कागज की बिक्री ग्राहकों को कम कीमत पर इसलिए की गई है क्योंकि इसके बिक्री रद्दी अखबारी कागज के साथ-साथ की गई है। पार्टी का यह दावा है कि निर्यातक को भारतीय बाजार में विशेष स्थिति ने अपने नियमित ग्राहकों को रद्दी अखबारी कागज बेचने और उससे पर्याप्त लाभ कमाने की अनुमति प्रदान की है। निर्यातक अच्छे अखबारी कागज की बिक्री कुछ ग्राहकों (अर्थात् ग्राहक-1) को की है और रद्दी अखबारी कागज की बिक्री दूसरे ग्राहक (अर्थात् ग्राहक-2) को की है इसीलिए निर्यातक का दावा है कि उसने ग्राहक 1 को कम मूल्य पर बिक्री की है क्योंकि उसने रद्दी अखबारी कागज की बिक्री ग्राहक 2 को की है (इस प्रकार कम वसूली को ग्राहक 1 से पूरा किया गया है)।

निर्यातक से अनुरोध किया गया था कि वे अच्छे और रद्दी अखबारी कागज के कुल उत्पादन का अलग-अलग ब्यौरा दें। निर्यातक ने ऐसा करने में यह कहते हुए असमर्थता जतायी है कि इसका अलग-अलग रिकार्ड रखने और रिपोर्ट करने की प्रणाली उपलब्ध नहीं है। इसीलिए निर्यातक को दूसरी तरह से अच्छे और रद्दी अखबारी कागज की कुल बिक्री का अलग-अलग ब्यौरा देने का सुझाव दिया गया था। निर्यातकों ने जो ब्यौरा दिया है उससे पता चलता है कि निर्यातक की सकल बिक्री में रद्दी अखबारी कागज की बिक्री 3.4 % है। जांच अवधि के दौरान रद्दी अखबारी कागज की भारत में बिक्री निर्यातक की कुल बिक्री का 20.9% है।

उपरोक्त के संदर्भ में, भारत को निर्यात किए गए रद्दी अखबारी कागज का सौदावार आयात ब्यौरा ज्ञात किया गया है और निर्यात कीमत के निर्धारण के उद्देश्य से इसकी उपेक्षा की गई है।

कमीशन : भारत को किए गए निर्यातों के मामले में निर्यातक ने यू एस डालर का कमीशन दिया है, जो कि निर्यात कीमत में से कम कर दिया गया है ।

अंतर्देशीय भाड़ा : निर्यातक ने भारत को किए गए निर्यातों पर कभी-कभी अंतर्देशीय भाड़ा दिया है । यद्यपि निर्यातक का संयंत्र समुद्री बन्दरगाह के निकट स्थित है, तथापि निर्यातक द्वारा यह बताया गया है कि उसे कभी-कभी जहाज पर अखबारी कागज लादने के लिए अंतर्देशीय भाड़ा देना पड़ता है । क्योंकि सामान्य मूल्य निर्धारित करने का प्रस्ताव है, जैसाकि इसके बाद विचार-विमर्श किया जाएगा, तृतीय देशों को निर्यात कीमत के आधार पर (इस मामले में भी निर्यातक को इस आधार पर उतनी राशि खर्च करनी होती है), इस कारण समायोजन करने का कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है ।

समुद्री भाड़ा : निर्यातक ने स्वयं द्वारा किए गए वास्तविक व्यय के आधार पर समुद्री भाड़ा चार्ज किया है इसलिए, इसकी अनुमति दे दी गई है ।

सामान्य मूल्य : एवीनोर इंक ने दावा किया है कि उसके द्वारा होम मार्केट में की गई बिक्री को एवीनोर मेरीटाइम्स के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए हिसाब में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये दोनों अलग कानूनी निकाय हैं । इसलिए एवीनोर इंक ने एवीनोर इंक द्वारा की गई बिक्री के बारे में विवरण प्रस्तुत नहीं किए हैं हालांकि प्राधिकारी ने सत्यापन के समय यही सुझाव दिया था ।

बिक्री मात्रा : अनेक बाजारों में एवीनोर मेरी टाइम्स द्वारा बेची गई मात्रा के आंकड़े निम्नानुसार हैं :—

बाजार	मात्रा	प्रतिशत	
		कुल बिक्री	भारत को निर्यात
घरेलू बाजार (होम मार्केट)	194	0.15	2.25
भारत के निर्यात	8546	6.88	—
अन्य देशों को निर्यात	115490	92.97	1351

एवीनोर इंक ने यह दावा किया कि घरेलू बाजार में एवीनोर मेरीटाइम्स की बिक्री पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए निम्नलिखित दो कारणों से विचार नहीं किया जा सकता :—

* बिक्री की मात्रा नगण्य है (भारत को निर्यातों का 1.8%) इसलिए, गाट के अनुच्छेद 2.2 के अनुसरण में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए आधार नहीं बन सकता ।

* निर्यातक ने अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के लिए न्यू ब्रुक्सविक (एवीनोर मेरीटाइम्स के नाम से) में संयंत्र स्थापित किया है और कनाडियन बाजार में बिक्री नहीं की है । यहां तक कि कनाडियन बाजार में बेची गई छोटी मात्रा भी नई उत्पाद टैस्टिंग का प्रतिनिधित्व करती है ।

यह पाया गया कि एवीनोर इंक ने भारत को एवीनोर मेरीटाइम्स (जो कि एवीनोर की सहायक कम्पनी है) में उत्पादित अखबारी कागज का निर्यात किया है । एवीनोर के अन्य कई संयंत्र हैं जो अखबारी कागज का उत्पादन कर रहे हैं, जिनसे इसने घरेलू बाजार में अखबारी कागज की बिक्री की है । धारा 9 क (1) ग (i) के अन्तर्गत सामान्य मूल्य की परिभाषा समान वस्तु के लिए तुलनात्मक कीमत है जब वह निर्यातक देश या क्षेत्र में उपभोग के निमित्त है । चूंकि निर्यातक के कनाडा में अन्य संयंत्र हैं, वह अन्य संयंत्रों से की जाने वाली बिक्री के लिए घरेलू कीमतों पर आधारित सामान्य मूल्य का दावा कर सकता है । तथापि, निर्यातक ने कनाडा में एवीनोर इंक के संयंत्रों पर आधारित सामान्य मूल्य के निर्धारण का प्रस्ताव नहीं किया है । जैसाकि प्राधिकारी द्वारा विशेष निवेदन करने के बावजूद भी निर्यातक ने एवीनोर इंक के अन्य संयंत्रों के संबंध में बिक्री सूचना उपलब्ध नहीं कराई है ।

एवीनोर इंक द्वारा तीसरे देशों को किए गए निर्यातों के ब्यौरों से यह पाया गया कि एवीनोर मेरीटाइम्स ने कुछेक देशों को निर्यात किया है । निर्यातक ने प्रारंभिक जांच के पश्चात इसके द्वारा फाइल किए गए जबाब में इसके द्वारा किए गए निर्यातों के देशवार ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए हैं । मौके पर जांच के दौरान, जांचकर्ता टीम ने पाया कि अनेक देशों के लिए किए गए निर्यातों के लिए मात्रा, कीमतों और लागत विशिष्ट के संबंध में अलग विवरण निर्यातक के पास उपलब्ध थे । इसलिए, एवीनोर इंक ने निर्यात की गई मात्रा, बिक्री मूल्य और एवीनोर मेरीटाइम्स द्वारा उठाए जाने वाले व्यय, केवल अनेक देशों को किए गए निर्यातों सहित अनेक देशों को एवीनोर मेरीटाइम्स द्वारा किए गए निर्यातों के ब्यौरे प्रस्तुत करने का निवेदन किया है । एवीनोर इंक ने जांच अवधि के लिए माहवार ब्यौरे प्रस्तुत किए हैं, जिनकी जांच से पता चलता है कि एवीनोर मेरीटाइम्स ने निम्नलिखित देशों को निर्यात किया है :

देश
बंगला देश
बरमुडा
चिली
कोलम्बिया
फ्रांस
हांगकांग
इंडिया
इजराइल
इटली
जमैका
जापान
नीदरलैंड
पुर्तगाल
प्यूरटो रीको
सिंगापुर
ताईवान आर ओ
थाईलैंड
यू. के.
योग

एवीनोर इंक ने यह तर्क दिया है कि सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए अन्य देशों को एवीनोर मेरीटाइम्स की निर्यात कीमतों पर निर्भर नहीं रहा जा सकता चूंकि डब्ल्यू टी ओ की धारा 2.2 यह बताती है कि तीसरे देश की कीमतों के उपयोग के लिए "समान उत्पाद की तुलनात्मक कीमत की तुलना करने की जरूरत होती है जबकि इसका निर्यात उपयुक्त तीसरे देश को किया गया बशर्ते कि यह कीमत प्रतिनिधित्व करती हो" की आवश्यकता है। पूर्वोक्त और भारतीय नियमों के पैरा 9 क (ग) (ii) क को ध्यान में रखते हुए, निर्यातक ने तर्क दिया है कि सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए तीसरे देश की निर्यात कीमत पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। निर्यातक ने अपने विवाद के समर्थन में निम्नलिखित कारण प्रस्तुत किए हैं :—

* **ग्रेड/टाइप :** निर्यातक ने दावा किया कि जापान, यू.के., नीदरलैंड, पुर्तगाल, सिंगापुर जैसे देशों पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार नहीं किया जा सकता, चूंकि निर्यातक ने इन देशों को 45 जी एस एम अखबारी कागज का निर्यात किया है (भारत को 48.8 जी एस एम अखबारी कागज का निर्यात किया) गया।

* **बरमुडा, जमैका और प्यूरटो रीको :** निर्यातक ने दावा किया कि इन देशों की निर्यात कीमत पर निम्नलिखित कारणों से विचार नहीं किया जा सकता :—

- * इन देशों में कोई स्थानीय उत्पादन नहीं है ;
- * की गई बिक्री की मात्रा कम है ;
- * बरमुडा बन्दरगाह की उतराई सुविधाएं सीमित हैं, जिसके परिणामस्वरूप समुद्री भाड़ा अधिक हो गया है;
- * इन देशों में एवीनोर केवल एक कंपनी को आपूर्ति करता है जो इन देशों में कीमत को अप्रतिनिधिक बनाता है;
- * प्यूरटो रीको में बाजार यू.एस. ए बाजार के अतिरिक्त, परम्परागत और ऐतिहासिक रूप से प्रीमियम देता है। इसके अतिरिक्त, निर्यातक के लदान का 54% एक ऐसे ग्राहक को नियत किया जाता है जहां एवीनोर एकमात्र आपूर्तिकर्ता है। परम्परागत रूप से, एक एकमात्र आपूर्तिकर्ता का उपयोग करने वाला प्रकाशक एक प्रीमियम देगा जो बदले में कमी की स्थिति में भी अखबारी कागज प्रदान करने की गारंटी देगा;
- * कोलम्बिया में ग्राहक को देश में राजनैतिक जोखिम को ध्यान में रखते हुए प्रीमियम देना होता है।

चिली : चिली अखबारी कागज का उत्पादन खपत से चार गुना है। प्रकाशक अपने आपको स्थानीय उत्पादकों की दया पर निर्भर रहने से बचाने के लिए अखबारी कागज का आयात करते हैं, जिसके बदले में उन्हें अन्य बाजारों की तुलना में प्रभियम देना होता है। चिली को की जाने वाली बिक्री मंहगी होती है और इसके लिए तकनीकी और विपणन स्टाफ की तिमाही आधार पर उपलब्धता की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, एविनोर चिली में केवल एक ग्राहक की सेवा करता है, जो कीमतों को अप्रतिनिधिक बनाता है।

* **बांग्लादेश, हांगकांग, ताइवान और थाईलैंड :** यद्यपि बांग्लादेश, हांगकांग, ताइवान और थाईलैंड में बाजार परिस्थितियां भारतीय बाजार जैसी है, तथापि इन देशों को लदान केवल कन्टेनर्स के द्वारा किया जाता है जो प्रभियम का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अतिरिक्त, इन देशों से संचयी लदाइ एविनोर मेरीटाइम्स की कुल बिक्री का 1.3% था। पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए, एविनोर इंक ने तर्क दिया है कि उसकी किसी अन्य देश की बिक्री कीमत को तुलनीय और प्रतिनिधि के रूप में नहीं समझा जा सकता। अतः एविनोर इंक ने एविनोर मेरीटाइम्स की अपनी उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का आंकलन किया है। निर्यातक का यह दावा कि उसके सामान्य मूल्य का निर्धारण तृतीय देश की निर्यात कीमत के आधार पर नहीं किया जा सकता, निम्नलिखित कारणों से उसे रद्द किया जा सकता है :—

* धारा 9(1)(ii)(क) में समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधि कीमत के आधार पर तब सामान्य मूल्य को निर्धारित करने की व्यवस्था है, जब इसका निर्यात निर्यातक देश से उपयुक्त तृतीय देश को किया जाता है। समान वस्तु की परिभाषा में न केवल समान वस्तुएं आती हैं अपितु ऐसी वस्तु के अभाव में उन वस्तुओं की विशेषताएं लिए हो जो विचाराधीन उत्पाद से बहुत मिलती जुलती हो। उत्पादन की लागत को आधार बनाते हुए और यह कि “समान वस्तु” का जिस उपयुक्त तृतीय देश को निर्यात किया गया है उसकी अनुपलब्धता का तर्क स्वीकार्य नहीं है।

* सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और डम्पिंग मार्जिन के निर्धारण को शासित करने वाले सिद्धान्तों के नियमों के अनुबंध 1 में, जिसमें ऐसे अन्तरों के लिए उचित छूट की व्यवस्था की गई है जिसमें बिक्री की शर्तों में विभिन्नताएं, व्यापार के स्तर और कीमत तुलनीयता को प्रभावित करने वाले कोई अन्य विषेदों सहित कीमत की तुलनीयता को प्रभावित करते हैं।

* यह मान्यता है कि कोई भी दो बाजार एक समान नहीं हैं। वास्तव में, कोई भी दो ग्राहक समान नहीं हो सकते और दो ग्राहकों की बिक्री कीमत, उसी बाजार में भी, कुछ कारकों को ध्यान में रखते हुए परिवर्तित हो सकता है। भारत को निर्यात और अन्य देशों को निर्यातों में बिक्री की निबंधन और शर्तों में इसके अन्तरों को ध्यान में रखते हुए एविनोर ने कीमत समायोजन का दावा किया जो बिक्री के निबंधन और शर्तों में अन्तर के लिए जिम्मेवार है। तथापि, एविनोर ने ऐसे किसी कीमत समायोजन का दावा नहीं किया है और इसके बजाय दावा किया है कि कियी अन्य देश को निर्यात कीमत प्रतिनिधि नहीं है।

निर्यातक का यह तर्क स्वीकार्य नहीं है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण तृतीय देशों को निर्यात कीमत के आधार पर नहीं किया जा सकता और अस्वीकार किए जाने योग्य है। भारत को किए गए निर्यातों और तृतीय देशों को किए गए निर्यातों के लिए कम्पनी द्वारा दिए गए उत्पादन लागत के विश्लेषण निम्नानुसार प्रकट करते हैं :—

- (क) निर्यातक का यह दावा है कि उसकी भारत को निर्यात कीमत उसकी उत्पाद लागत से अधिक से अधिक थी इसलिए डम्पिंग नहीं हुई;
- (ख) एविनोर ने भारत को बेचे गए अखबारी कागज और अन्य देशों को निर्यात किए गए अखबारी कागज के लिए कच्चे माल की अलग-अलग लागत का दावा किया है। निर्यातक ने अन्य देशों को किए गए निर्यात के मामले में कच्चे माल की अधिक लागत का दावा किया है जो कि, एविनोर के अनुसार भारत और जापान को निर्यातित सामग्री में अन्तर दर्शाता है;
- (ग) निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्पादन लागत विवरण पत्र में ब्याज लागत, एविनोर इंक का कमीशन, जो कि एविनोर मेरीटाइम्स द्वारा दिया गया और उचित लाभ जो कि एविनोर मेरीटाइम्स द्वारा भारत को दिए गए निर्यातों पर मिलने का प्रस्ताव है, शामिल नहीं है;
- (घ) निर्यातक का यह दावा कि उसने भारत को निर्यात लागत से अधिक पर किया है, भारत को की गई ट्रिम बिक्री पर विचार करने के बाद किया गया है, जिसकी लागत पर केवल कच्चे माल की लागत को शामिल करके विचार किया गया है। एविनोर ने तर्क दिया है कि ट्रिम को आमतौर पर पेपर मशीन के भीतर ही पुनः घुमा कर किया जाता है क्योंकि इसको बेचना अन्यथा कठिन है। भारत को इसके निर्यातों के मामले में, निर्यातक ने तर्क दिया कि इसने पर्याप्त मात्रा में ट्रिम की बिक्री की है निर्यातक ने तर्क दिया कि ट्रिम की लागत में अखबारी कागज उत्पादन में केवल परिवर्तनीय लागत शामिल है अर्थात् फाइबर, लुगदी, बिजली, रसायनों की लागत और अन्य विविध लागतें हैं। निर्यातक ने यह दावा किया है कि जहां तक ट्रिम उत्पादन का संबंध है, निम्नलिखित के संबंध में, कोई लागत शामिल नहीं है :

* अर्द्ध-परिवर्तनीय लागतें—जैसे श्रमिक, रखरखाव, बिजली तथा अन्य;

* स्थिर लागतें—जैसे विनिर्माण प्रकाशन, बिक्री, प्रशासन, मूल्यहास तथा अन्य।

यह पाया गया कि निर्यातक ट्रिम उत्पादन को बिक्री योग्य उत्पादन के रूप में मानता है। निर्यातक द्वारा प्रस्तुत लागत पत्र में निर्यातक ने उत्पादन लागत का निर्धारण कुल बिक्री योग्य उत्पादन के आधार पर किया है (यानि ट्रिम उत्पादन सहित)। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जबकि निर्यातक द्वारा निर्धारित उत्पादन लागत कुल बिक्री योग्य उत्पादन पर आधारित है (ट्रिम उत्पादन सहित), निर्यातक ने यह तर्क दिया कि ट्रिम उत्पादन की लागत में केवल परिवर्तनीय लागतें शामिल हैं। निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किए गए अखबारी कागज की उत्पादन लागत के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

	भारत को किया गया निर्यात	ट्रिम	तीसरे देशों को किया गया निर्यात
बिक्री (एम टी)	***	***	***
परिवर्तनीय लागतें	***	***	***
अर्द्ध परिवर्तनीय लागत	***	शून्य	***
स्थिर लागत	***	शून्य	***
ऊपरी लागत	***	शून्य	***
कुल लागत	***	***	***
घटाइए—भारत को बेचे गए ट्रिम के लिए ऋण	***		
शुद्ध उत्पादन लागत	***		

* भारत को बेचे गए कुल ट्रिम की मात्रा पर आधारित

प्राधिकारी मानता है कि निर्यातक ने जांच अवधि के दौरान भारत को किए गए ट्रिम निर्यातों के आधार पर ट्रिम बिक्री के लिए ऋण का दावा किया है। चूंकि निर्यातक ने भारत में विभिन्न उपभोक्ताओं को और/अथवा विभिन्न समय पर ट्रिम उत्पादन और अच्छे उत्पादन का निर्यात किया है इसलिए निर्यातक ने भारत को निर्यातित अच्छे अखबारी कागज की लाभप्रदता का निर्धारण करते समय ट्रिम अखबारी कागज की बिक्री से पर्याप्त अधिक कीमत प्राप्ति का लाभ लिया है।

प्राधिकारी ने नोट किया है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण धारा 9 क (1) ग के तहत करना होता है जैसा कि ऊपर बताया गया है। उक्त धारा में व्यवस्था है कि समान वस्तु जब निर्यातक देश में खपत के उद्देश्य से है तो उसके लिए तुलनात्मक कीमत सामान्य मूल्य होगा। यदि निर्यातक की बिक्री घरेलू बाजार में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए पर्याप्त नहीं है तो इसका निर्धारण निर्यातक की घरेलू बाजार अन्य उत्पादकों को बिक्री कीमतों के आधार पर किया जा सकता है। एक ताजा मामले में, जहाँ एविनोर इंक की कनाडा में अनेक मिल हैं, जो घरेलू बाजार में अखबारी कागज की बिक्री कर रही है, सामान्य मूल्य का दावा इन मिलों की बिक्री कीमतों के आधार पर किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त बिक्री के निबंधन और शर्तों में अन्तरों का समायोजन करने के बाद निर्यातक तृतीय देशों की निर्यात कीमत पर आधारित सामान्य मूल्य का दावा कर सकता है, इन परिस्थितियों में, प्राधिकारी कनाडा के अन्य सहकारी निर्यातकों, यानि स्टोन कन्सोलिडेटेड और एबीटीबी की मासिक औसत बिक्री कीमत के आधार पर एविनोर मेरीटाइम्स के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करना पर्याप्त समझता है। एविनोर मेरीटाइम्स के मामले में सामान्य मूल्य का स्टोन कन्सोलिडेटेड और एबीटीबी के सामान्य मूल्यों के आधार पर तदनुसार निर्धारण कर लिया गया है।

रूस के निर्यातक :

प्रारंभिक निष्कर्षों से पहले वर्तमान जांच के संबंध में रूस से किसी भी निर्यातक ने वास्तविक सूचना नहीं भेजी है। तथापि, बालाखाना, खोन्डोपोन्गा और सोलिकम्स ने प्रारम्भिक निष्कर्षों के बाद कुछ सूचना भेजी है। इन निर्यातकों के संबंध में डम्पिंग का निर्धारण करने के लिए अपनाया गया तरीका इसके नीचे बताया गया है :—

प्रारम्भिक कार्यवाई के तुरन्त पश्चात् प्राधिकारी ने निर्यातक से निर्धारित फार्म और तरीकों में सूचना भिजवाने को कहा। अन्य बातों के साथ-साथ, प्राधिकारी ने निम्नलिखित सूचना भिजवाने को कहा :—

- * इस आशय का प्रमाण-पत्र कि प्रस्तुत सूचना सत्य, पूरी और सही है;
- * निर्यातक को इस बारे में रजामंदी कि वह ऐसे किसी भी सत्यापन के लिए तैयार है जो प्राधिकारी उसके परिसर में कराना चाहे;
- * प्रमुख अंशधारियों के बारे में ब्यौरे सहित कम्पनी के बारे में सामान्य सूचना इत्यादि;
- * निर्यातक के संयंत्रों/फैक्ट्रियों का विवरण;
- * निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार भारत को किए गए निर्यातों के पण्यवार ब्यौरे ;
- * जांच अवधि सहित तीन वर्षों के लिए कम्पनी द्वारा अखबारी कागज की बिक्री के संबंध में विवरण-पत्र (प्रोफार्मा 2 ए);
- * जांच अवधि के लिए कम्पनी द्वारा अखबारी कागज की बिक्री के संबंध में माह-वार विवरण पत्र (प्रोफार्मा 2 बी);

- * भारत को निर्यातित अखबारी कागज का विवरण-पत्र, ग्राहकों के प्रकारों यानि बोक विक्रेता/खुदरा/अन्य के अनुसार वर्गीकृत (प्रोफार्मा 2 सी);
- * भरेलू बिक्री का विवरण-पत्र, ग्राहकों के प्रकारों यानि बोक विक्रेता/खुदरा/अन्यों के अनुसार वर्गीकृत (प्रोफार्मा 2 डी);
- * भारत के अतिरिक्त अन्य देशों को निर्यातों का विवरण-पत्र, ग्राहकों के प्रकारों यानि बोक विक्रेता/खुदरा/अन्य के अनुसार वर्गीकृत (प्रोफार्मा 2 ई);
- * भारत को किए गए निर्यातों के लिए बिक्री कीमत ढांचे का विवरण-पत्र (प्रोफार्मा 3 ए) जिसमें सूची कीमत, कीमत समायोजन और निवल कारखाना-गत कीमत दी गई है;
- * भरेलू बिक्री के लिए बिक्री कीमत ढांचे का विवरण-पत्र (प्रोफार्मा 3 बी), जिसमें सूची कीमत, कीमत समायोजन और निवल कारखाना-गत कीमत दी गई है;
- * भारत के अतिरिक्त देशों को निर्यातों के लिए बिक्री कीमत ढांचे का विवरण-पत्र (प्रोफार्मा 3 सी), जिसमें सूची कीमत, कीमत समायोजन और निवल कारखाना-गत कीमत दी गई है ;
- * लाइसेंस की क्षमता, संस्थापित क्षमता, उत्पादन और बिक्री को दर्शाने वाला विवरण-पत्र (प्रोफार्मा 4 ए);
- * भारत को किए गए निर्यातों, आंतरिक बाजार में की गई बिक्री और भारत के अतिरिक्त देशों को किए गए निर्यातों के लिए तत्त्व-वार उत्पादन लागत दर्शाने वाला विवरण-पत्र (प्रोफार्मा 4बी, सी, डी);
- * जांच अवधि सहित पिछले तीन वर्षों के लिए वार्षिक लेखा और वित्तीय विवरण-पत्र ।
बाला, खोण्डो और सोलिकम द्वारा किए गए दावों पर नीचे विचार किया गया है ।

5. बालाखाना :

बालाखाना ने निम्नलिखित तर्क दिए :—

- (क) निर्यातक ने प्राधिकारी के साथ पूरी तरह सहयोग किया और प्राधिकारी द्वारा मांगी गई सारी सूचना प्रस्तुत की;
 - (ख) निर्यातक स्वयं को जांच के लिए प्रस्तुत करने को इच्छुक था;
 - (ग) प्राधिकारी ने स्थान जांच के लिए बहुत कम समय दिया;
 - (घ) विनिर्माण प्रक्रिया, जांच अवधि, साथ ही साथ जांच अवधि के बाद तथा पहले के लिए उत्पादन लागत की गणना करने सहित निर्यातक ने एक विस्तृत सत्यापन प्रस्तुत किया है;
 - (ङ) तुलना पत्र और आय तथा प्रचालन के विवरण-पत्र, उनकी अनुसूची सहित, जांच करने वाली टीम को दिखाए गए, यद्यपि इनकी प्रति बोर्ड की स्वीकृति न होने की वजह से नहीं दी जा सकी (जो कि सक्षम प्राधिकारी की अनुपलब्धता की वजह से प्राप्त नहीं किया जा सका) । तथापि जांच करने वाली टीम द्वारा स्थान जांच करने के पश्चात् इसे जमा करा दिया गया;
 - (च) सामान्य मूल्य की गणना भरेलू बाजार में बिक्री कीमतों के आधार पर की जानी चाहिए;
- उपर्युक्त और प्राधिकारी द्वारा दिए गए विवरण-पत्र को ध्यान में रखते हुए, बालाखाना ने तर्क दिया कि निर्यातक द्वारा पूरा सहयोग दिया गया और जांच करने वाली टीम को पूरी जांच प्रस्तुत की गई ।

प्राधिकारी की स्थिति :

निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए, निर्यातक के उपर्युक्त तर्क वास्तव में अनुचित हैं :—

- (क) अन्य बातों के साथ-साथ बालाखाना ने निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत की :—
 - * जांच अवधि के दौरान आंतरिक बाजार में की गई बिक्री और भारत को किए गए निर्यातों का विवरण-पत्र;
 - * जांच अवधि के दौरान तृतीय देशों को निर्यातित मात्रा;
 - * अखबारी कागज की लागत की गणना, जांच अवधि के लिए महीना-वार;
 - * औसत कीमत की तुलना, भरेलू बाजार में बिक्री के लिए कारखाने के बाहर की कीमत और भारत को निर्यात;
 - * भारत को निर्यातित अखबारी कागज का वैसेल-वार विवरण, जिसमें वैसेल, लोडिंग तिथि का बिल, बुक की गई मात्रा और प्राप्त की गई मात्रा के ब्यौरे दिए गए हैं ।
- (ख) प्रारम्भिक कार्रवाई के तुरंत पश्चात् प्राधिकारी ने निर्यातक से निर्धारित फार्म और तरीके में सूचना भिजवाने को कहा । निर्यातक को, कोई भी सूचना जो आवश्यक हो, की जांच करने की प्राधिकारी के निश्चय से अवगत कराया गया था । पूरी तथा सम्पूर्ण सूचना भेजने का दायित्व निर्यातक का है । न केवल, निर्यातक ने पूरी सूचना उपलब्ध नहीं कराई है, बल्कि जांच करने वाली टीम को भी विवरण नहीं दिखाए हैं, जैसा कि उपर्युक्त से पता चलता है ।

- (ग) उत्पादन लागत जैसे कच्चा माल, उपभोग मानवण्ड और वित्तीय विवरण-पत्र के साथ लागत विवरण पत्र के समाधान के संबंध में सहायक सूचना भेजने को कहा गया। ये भी प्रस्तुत नहीं किए गए।
- (घ) सत्यापन की अवधि के दौरान जांच करने वाली टीम ने पता लगाया कि निर्यातक के पास तीन पेपर मशीनें पी एम 5, 6 और 8 हैं और कम्पनी द्वारा उत्पादन लागत के लिए किया गया दावा केवल उसकी पी एम 8 मशीन के लिए था। यह तथ्य प्रश्नावली के उत्तर में नहीं लाया गया था निर्यातक से अन्य दोनों पेपर मशीनों के लिए लागत शीट उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया, जो कि जांच करने वाली टीम अथवा प्राधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया गया। केवल यह स्पष्ट किया गया कि पी एम 5 और पी एम 6 का केवल पी एम 8 का पूरी क्षमता से प्रचालन करने के पश्चात् उपयोग किया जाता है (और जब कम्पनी को अधिक उत्पादन की आवश्यकता हो)।
- (ङ) जांच करने वाली टीम ने जांच अवधि सहित पिछले तीन वर्षों के लिए कंपनी के उत्पादन के ब्यौरे देखने की इच्छा व्यक्त की। यद्यपि, प्रेषण के ब्यौरे, वह भी केवल जांच अवधि के लिए, उपलब्ध करा दिए गए थे, जांच करने वाली टीम को उत्पादन के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए गए। कम्पनी ने दावा किया कि सूची-तालिका में कोई परिवर्तन नहीं किया गया और उत्पाद बिक्री/प्रेषण के बराबर था। प्रकटीकरण विवरण पत्र के प्रत्युत्तर में कम्पनी ने पहली बार 1996 के दौरान अपना उत्पादन प्रस्तुत किया और यह न तो उत्तर के साथ प्रस्तुत किया गया न ही सत्यापन के समय उपलब्ध कराया गया। तथापि यह पाया गया कि कम्पनी ने कुल () उत्पादन का दावा किया है, जो कि पी एम 8 मशीन की क्षमता से महत्वपूर्ण रूप से अधिक है [पी एम 8 की () क्षमता का दावा किया गया]। इस प्रकार यह साबित होता है कि कम्पनी ने शेष दो पेपर मशीनों से सार्थक मात्रा में उत्पादन किया, जिनकी लागतें प्रकट नहीं की गईं। यह इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि कम्पनी द्वारा वित्तीय लेखा तीनों मशीनों के लिए समेकित आधार पर रखा जाता है और कम्पनी द्वारा प्रत्येक मशीन के लिए अलग वित्तीय रिकार्ड नहीं रखे जाते हैं।
- (च) कम्पनी द्वारा दी गई सूचना, जांच करने वाली टीम को विस्तृत रूप से तत्व-वार लागतें सत्यापित करने में सहायता नहीं करतीं। यह स्पष्ट नहीं था कि क्या उत्पादन लागत में लागत तत्व जैसे स्थिर सम्पत्ति पर मूल्यहास, ब्याज इत्यादि भी शामिल हैं। वास्तव में जांच करने वाली टीम को यह समझाया गया कि सामान्यतया रूप में अनिवार्य लेखा-परीक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं है, और न ही स्थिर सम्पत्ति पर मूल्यहास का प्रबन्ध अनिवार्य था। तथापि, स्थान जांच के पश्चात् निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किए गए 1996 के वार्षिक लेखाओं में यह पाया गया कि तुलन पत्र और आय तथा व्यय का विवरण-पत्र दोनों स्थिर सम्पत्ति पर मूल्यहास पर विचार करने के बाद दिए गए हैं।
- (छ) कुछ सूचनाएं जैसे उत्पादन का समाधान, बिक्री और स्टॉक निर्यातक द्वारा फाइल नहीं किए गए हैं। निर्यातक ने अपने उत्पादन के आधार पर उत्पाद की लागत का निर्धारण किया है और स्पष्ट रूप से यह माना कि बिक्री उत्पादन के समान थी। आय और व्यय के विवरण-पत्र की छान-बीन से यह पता चलता है कि 1-1-1996 की तुलना में 31-12-1996 तक परिष्कृत वस्तुओं की सूची तालिका में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि हुई है। इससे स्पष्ट रूप से यह परिणाम निकलता है कि बिक्री मात्रा महत्वपूर्ण रूप से उत्पादन से कम थी (जिसका परिणाम यह होगा कि निर्यातक द्वारा दावा की गई राशि से उत्पादन लागत अधिक होगा) इसी प्रकार निर्यातक द्वारा दिए गए "अन्य आय (व्यय)" के ब्यौरों से यह प्रकट होता है कि विदेशी मुद्रा कारोबार में पर्याप्त लाभ हुए थे, ब्याज संबंधी व्यय संभवतः ब्याज आय से ही संभव है (जो गैर-प्रचालनात्मक स्रोतों से हो सकते हैं) 31-12-96 की स्थिति के अनुसार चालू भाग को कम करके दीर्घावधि ऋण ----- थे, इसकी लागत की ब्याज दरों से अमरीकी डालर ----- होते हैं जबकि कम्पनी ने अपने वित्तीय विवरण-पत्र में ----- अमरीकी डालर का व्यय दिखाया है। प्राधिकारी को यह ज्ञात नहीं है कि क्या कम्पनी की पहुंच ब्याज मुक्त ऋणों तक है अथवा वित्तीय विवरण-पत्र में दर्शाए गए ब्याज संबंधी व्यय कुछ स्रोतों से ब्याज-संबंधी आयों के ही रूप में है। इनमें से किसी प्रकार के भी ब्यौरे निर्यातक ने प्रस्तुत नहीं किए हैं जिनका उत्पादन की लागत पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।
- (ज) निर्यातक का दावा कि उपलब्ध/संभव सूचना जांच करने वाली टीम को प्रस्तुत की थी, स्वीकार्य नहीं है। किसी इच्छुक पार्टी (पार्टियों) द्वारा दी गई सूचना का सत्यापन स्थान जांच के दौरान किया जाता है। जांच दल ने किसी भी सूचना के लिए ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया है जिसे नई आवश्यकता के रूप में माना जा सके। टीम ने महज सूचना के लिए अनुरोध किया था जो प्रश्नावली में निर्धारित की गई है और ये अनुरोध भी जांच दल द्वारा प्राधिकारी को उन निर्यातकों को एक ओर अवसर देने के भाग के रूप में था, जो प्राधिकारी के साथ सहयोग करने के इच्छुक थे और जिन्होंने सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के बारे में कुछ न कुछ सूचना प्रस्तुत की थी, और प्राधिकारी की ओर से सत्यापन के समय ऐसी सूचना के लिए निवेदन करने की कोई बाध्यता नहीं है।
- (झ) निर्यातक का यह दावा कि कुल औसत उत्पादन लागत (उत्पादन की लागत इकाई तथा कुल उत्पादन मात्राओं से निकाली गई है) तथा उस अवधि के लिए कुल लाभ कमोबेश कारखाने द्वारा अर्जित कुल बिक्री राजस्व के समान ही है, सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों से बहुत दूर है। दावा करते समय निर्यातक ने उत्पादन की लागत का आंकलन करने के लिए "उत्पादन के सिद्धांतों और उत्पादन के व्यय" को नजरअंदाज कर दिया है। वास्तविक तथ्य यह है कि उस अवधि में स्टॉक में पर्याप्त वृद्धि हुई थी (जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन की तुलना में बिक्री की मात्रा बहुत कम थी) और कम्पनी ने विभिन्न बाजारों की आवश्यकताओं को पूरा किया है, निर्यातक द्वारा इसको पूर्ण रूप से नजरअंदाज किया है।

- (अ) प्राधिकारी ने नोट किया कि निर्यातक ने प्रकटीकरण पत्र के उत्तर में 1996 के दौरान उत्पादन के संबंध में विस्तृत ब्यौरे फाइल किए थे, और ये न तो प्रश्नावली के उत्तर में प्रस्तुत किए गए न सत्यापन के समय प्रस्तुत किए गए।
- (ट) घरेलू बाजार में की गई बिक्रियों के संबंध में निर्यातक से घरेलू बाजार में कुल बिक्रियों के साक्ष्यों सहित ब्यौरे प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया। निर्यातक ने घरेलू बाजार में सभी बिक्री संबंधी कारोबार को दर्शाने वाला विवरण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है और केवल बड़ी संख्या में बीजक ही उपलब्ध कराए हैं (जिनमें घरेलू बाजार में हुई बिक्रियों से संबंधित सभी बीजकों के होने का दावा किया है)। प्राधिकारी ने नोट किया कि निर्यातक ने अब तक ऐसे कोई ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए हैं जिनसे घरेलू बाजार में सभी प्रकार की बिक्री संबंधी कारोबार के ब्यौरों का पता चलता है।

VI. कोन्डोपोंगा :

तर्क उठाए गए :

कोन्डोपोंगा ने निम्नलिखित तर्क दिए :

- (क) सारी स्थान जांच पर्याप्त समय दिए बिना की गई। जांच करने वाली टीम के पास कारखाने का दौरा करने का पर्याप्त समय नहीं था।
- (ख) परिचित तुलन-पत्र और लाभ तथा हानि खातों सहित, जो कि ***** (30 मिलियन अमरीकी डालर) का कुल उपार्जन दर्शाते हैं, कम्पनी ने जांच टीम द्वारा मांगी गई सारी सूचना प्रस्तुत की। यह स्पष्ट नहीं था कि ज्ञात निर्यातक द्वारा क्या सूचना फाइल नहीं की गई और क्या सूचना अपर्याप्त थी।
- (ग) प्राधिकारी की इस टिप्पणी के संबंध में कि घरेलू बाजार में की गई बिक्री के ब्यौरे उसी तारीख के हैं, यह स्पष्ट किया गया कि मिल ने समय-समय पर अपनी कीमतों को परिवर्तित किया है (और तब तक कीमतें सभी क्रेताओं के लिए एक समान रहें) कम्पनी ने प्रत्येक अवसर पर बनाई गई इन्वाइसेज की प्रतियां प्रस्तुत की जब जांच अवधि के दौरान कीमतें परिवर्तित की गईं।

प्राधिकारी की स्थिति :

निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए, निर्यातक के उपर्युक्त तर्क वास्तव में अनुचित हैं :

- (क) अन्य बातों के साथ-साथ कोन्डोपोंगा ने निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत की :
- * भारत को निर्यातित अखबारी कागज के ब्यौरे, आंतरिक बाजार में बेचा गया अखबारी कागज, जिसमें बिक्री कीमत दी गई है;
 - * उत्पादन, लागत के ब्यौरे,
 - * सत्यापन के लिए स्वयं को प्रस्तुत करने की इच्छा।
- (ख) प्रारम्भिक जांच के तुरंत पश्चात् प्राधिकारी ने निर्यातक से निर्धारित फार्म तथा तरीके से सूचना, प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। निर्यातक को जहां आवश्यक हो वहां कोई सूचना सत्यापित करने की प्राधिकारी की दृढ़ता से अवगत कराया गया। पूरी तथा सम्पूर्ण सूचना प्रस्तुत करने का दायित्व निर्यातक का था। न केवल निर्यातक ने पूरी सूचना उपलब्ध नहीं कराई, बल्कि ब्यौरे जांच टीम को भी नहीं दिखाए गए, जैसा कि उपर्युक्त से पता चलता है।
- (ग) जैसा कि बालाखाना के मामले में देखा गया सूचना के लिए अनुरोध प्रारम्भिक जांच प्रारम्भ होने के तुरंत बाद किया गया, और निर्यातक का यह दावा कि उसने पूरी सूचना उपलब्ध करा दी है अथवा प्राधिकारी ने सूचना फाइल कराने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया अथवा सूचना जांच टीम को दिखा दी गई है, बिना मैरिट के है। प्राधिकारी ने यह पाया कि निर्यातक ने स्थान जांच के बाद भी परिचित तुलनपत्र और लाभ तथा हानि खाते प्रस्तुत नहीं किए हैं। इसके अतिरिक्त निर्यातक का यह दावा कि दिखाए गए वार्षिक खाते परिचित थे, बालाखाना द्वारा किए गए दावे से विरोधात्मक है कि उस में कानूनी परीक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। घरेलू बाजार में कीमतों में आवधिक परिवर्तन के संबंध में, प्राधिकारी ने यह पाया कि यह बिना किसी प्रमाणित साक्ष्य के है। निर्यातक का दायित्व कम्पनी के लिए उपर्युक्त प्रारूप में सूचना प्रस्तुत करने का नहीं है, बल्कि इसे प्राधिकारी द्वारा मांगें गए प्रारूप में प्रस्तुत करने का है। प्राधिकारी ने घरेलू बाजार में की गई सभी बिक्रियों के ब्यौरे और घरेलू बाजार में की गई सभी बिक्रियों के आधार पर घरेलू बाजार में की गई बिक्रियों की औसत कीमत मांगी। जबकि एक निश्चित अवधि के लिए एक समान कीमतों के संबंध में निर्यातक का दावा समर्थन साक्ष्य के अभाव में अस्वीकृत कर दिया गया, बिक्री कीमतों के संबंध में किया गया दावा, निर्यातक द्वारा किए गए बिक्री कीमतों के अपर्याप्त और असंगत निर्धारण को ध्यान में रखते हुए अस्वीकृत कर दिया गया।

VII. सोलिकेम्स :

उठाए गए तर्क :

सोलिकेम्स ने निम्नलिखित तर्क दिए :

- (क) सारी स्थान जांच पर्याप्त समय दिए बिना की गई। जांच टीम के पास कारखाने का दौरा करने का पर्याप्त समय नहीं था ;

- (ख) परिक्षित तुलन पत्र और लाभ तथा हानि खातों सहित, जो कि रूसी नियमों के तहत एक चार्टर्ड /स्वतंत्र एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित किए गए और 1996 के दौरान बहुत लाभ दर्शाते हैं; कम्पनी ने जांच टीम द्वारा मांगी गई सारी सूचना प्रस्तुत की। यह स्पष्ट नहीं था कि निर्यातक द्वारा क्या सूचना फाइल नहीं की गई और क्या सूचना अपर्याप्त थी।

प्राधिकारी की स्थिति :

- (क) अन्य बातों के साथ-साथ सोलिकेम्स ने निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत की :

- * भारत को निर्यातित अखबारी कागज के ब्यौरे, आंतरिक बाजार में बेचा गया अखबारी कागज, जिसमें बिक्री कीमत दी गई है;
- * उत्पादन लागत के ब्यौरे;
- * सत्यापन के लिए स्वयं को प्रस्तुत करने की इच्छा।

- (ख) जैसा कि बालाखाना के मामले में देखा गया सूचना के लिए अनुरोध प्रारम्भिक जांच प्रारम्भ होने के तुरंत बाद किया गया और निर्यातक का यह दावा कि उसने पूरी सूचना उपलब्ध करा दी है अथवा प्राधिकारी ने सूचना फाइल कराने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया अथवा सूचना जांच टीम को दिखा दी गई है, बिना मैरिट के है। प्राधिकारी ने यह पाया कि निर्यातक ने स्थान जांच के बाद भी परिक्षित तुलन पत्र और लाभ तथा हानि खाते प्रस्तुत नहीं किए हैं। इसके अतिरिक्त निर्यातक का यह दावा कि दिखाए गए वार्षिक खाते रूसी कानूनों के तहत चार्टर्ड/स्वतंत्र एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित हैं, बालाखाना द्वारा किए गए दावे से विरोधात्मक हैं कि रूस में कानूनी परीक्षा का कोई प्रावधान नहीं है और कोन्डोपोंगा द्वारा दावा किया गया कि वित्तीय विवरण-पत्र परिक्षित है। प्राधिकारी को अब तक वास्तविक स्थिति का पता लगाने से रोका गया। प्राधिकारी ने आगे पाया कि निर्यातक ने 1996 के लिए अपनी आय और व्यय को दर्शाते हुए एक विवरण-पत्र प्रस्तुत किया है। कम्पनी द्वारा इस विवरण-पत्र के साथ कोई भी ब्यौरे और इसकी पुष्टि करने वाले विवरण-पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए।

- (ग) दिए गए समय के बारे में यह बताने की आवश्यकता है कि प्रति-पाटन जांच एक सुनिश्चित समय सीमा के भीतर पूरी की जानी है। यहां यह नोट करना भी आवश्यक है कि ये रूस के निर्यातक थे जिन्होंने लगभग 6 महीने के पश्चात् अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत की जबकि कानूनी समय सीमा केवल 40 दिन की है। यद्यपि प्रतिक्रिया 40 दिनों के भीतर प्राप्त नहीं हुई थी, प्राधिकारी ने एक उचित निर्णय पर पहुंचने के लिए उनके द्वारा दी गई सूचना पर विचार किया है।

15. प्राधिकारी द्वारा सोलिकेम्स बालाखाना और कोन्डोपोंगा के संबंध में अपनाई गई प्रणाली :

- (क) जैसाकि पूर्वोक्त परिच्छेदों में विस्तार से स्पष्ट किया गया है, सोलिकेम्स, बालाखाना और कोन्डोपोंगा द्वारा दी गई सूचना किसी भी विधिसम्मत आधार पर इन निर्यातकों के सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इन निर्यातकों द्वारा दिए गए उत्पादन लागत के ब्यौरे भी सामान्य मूल्य-निर्धारण के लिए अपर्याप्त हैं, जैसाकि पूर्वोक्त परिच्छेदों में विवरण दिया गया है। उपरोक्त की दृष्टि से प्राधिकारी ने बालाखाना के मामले में उचित उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य-निर्धारण किया है। कंपनी द्वारा भेजे गए विवरणों में दर्शाए गए ऋणों के उचित ब्याज की लागत पर विचार करने के बाद बालाखाना द्वारा भेजी गई सूचना के आधार पर उत्पादन-लागत की पुनः जांच की गई है। कंपनी द्वारा भेजे गए विवरण में दर्शाए गए अन्य खर्चों को भी उचित उत्पादन-लागत के निर्धारण के लिए सम्मिलित किया गया है। सामान्य मूल्य निकालने के लिए उत्पादन लागत पर उचित लाभ की अनुमति दी गई है। प्राधिकारी ने निर्यातक द्वारा किए गए दावों, जिनका प्राधिकारी द्वारा सत्यापन भी किया गया, के आधार पर निर्यात-कीमत निर्धारित की है। चूंकि, निर्यातक ने फैक्ट्री-द्वार की निर्यात-कीमत भेजी है इसलिए इस पर विश्वास किया गया है।

- (ख) सोलिकेम्स और कोन्डोपोंगा के मामले में चूंकि निर्यातकों द्वारा भेजी गई सूचना, उचित उत्पादन लागत के निर्धारण के लिए भी अपर्याप्त है इसलिए प्राधिकारी द्वारा उत्पादन-लागत के आधार पर भी सामान्य मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सका। परन्तु, प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्य मूल्य को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत निर्यातक देश के घरेलू बाजार में कीमतों के रूप में परिभाषित किया गया है। इसलिए जैसा कि एविनर ईक से संबंधित परिच्छेदों में विचार किया गया है बालाखाना के लिए उपलब्ध सामान्य मूल्य के आधार पर पाटन का निर्धारण करना उचित होगा। इसके अतिरिक्त जैसा कि अंतिम निष्कर्षों से संबंधित परिच्छेद में विस्तार से विचार किया गया, इन दोनों निर्यातकों ने कीमत की वचनबद्धता भेजी है, और इसे प्राधिकारी ने स्वीकार कर लिया है। इन निर्यातकों के विरुद्ध प्राधिकारी ने किसी निश्चित शुल्क की सिफारिश नहीं की है। प्राधिकारी ने इन निर्यातकों द्वारा किए गए दावों के आधार पर निर्यात-कीमत निर्धारित की है। जिनका प्राधिकारी द्वारा सत्यापन भी किया गया था। चूंकि, निर्यातकों ने फैक्ट्री-द्वार की निर्यात कीमत भेजी है, इसलिए इस पर विश्वास किया गया है।

16. कीमत की वचनबद्धता : सोलिकेम्स और कोन्डोपोंगा ने प्राधिकारी को अपने-अपने एजेंटों के माध्यम से कीमत की वचनबद्धता दी है। प्राधिकारी इसे उचित समझते हैं कि कथित वचनबद्धता की शर्तों पर माल की निकासी के लिए उक्त निर्यातकों को अनुमति दे दी जाए।

वचनबद्धता कीमत
(रुपये प्रति मी. टन)

- (क) जे एस सी सोलिकेम्सग्रोम

20280

- (ख) कोन्डोपोंगा पल्प एंड पेपर मिल

20280

VI. कनाडा/संयुक्त राज्य अमरीका/रूस के अन्य उत्पादक

प्राधिकारी ने नीचे दिए गए कारणों से निम्नलिखित निर्यातकों के संबंध में अलग से पाटन सीमा निर्धारित नहीं की है :

- (क) एलायन्स फॉरेस्ट्स प्रोडक्ट्स इंक : कंपनी ने दावा किया है कि इसने भारतीय बाजार में उचित बाजार कीमतों पर बिक्री की थी, उच्च कोटि का स्तर बनाए रखा था इसलिए उसे पाटन के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

प्राधिकारी का विचार : निर्यातक ने प्राधिकारी द्वारा निवेदित सूचना निर्धारित प्रपत्र और ढंग में नहीं भेजी इसलिए निर्यातक का दावा अस्वीकृत किया जाता है।

- (ख) केम्पक पल्प एंड पेपर मिल्स, रूस : कंपनी ने स्वयं को इस आधार पर अलग कर देने का अनुरोध किया कि इसने जांच-अवधि के दौरान किसी भी न्यूजप्रिंट की आपूर्ति नहीं की थी।

प्राधिकारी का विचार : प्राधिकारी यह बात नोट करते हैं कि चूंकि निर्यातक ने जांच-अवधि के दौरान न्यूजप्रिंट का निर्यात नहीं किया था इसलिए उस पर नियम 22 लागू होता है।

- (ग) दि डायशोवा इंक : कंपनी ने बताया कि सुदूर पूर्व दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य और दक्षिण अमरीका और चीन को जिन बिक्री मूल्यों पर निर्यात किया गया था वे भारत को किए गए निर्यात मूल्यों के समान थे अथवा उससे कम थे। भारत में डायशोवा का कुल निर्यात मूल्य जांच-अवधि के दौरान 612.21 प्रति मी. टन था जो कनाडा और अमरीका के निर्यात मूल्यों के बराबर है। उक्त अवधि में भारत में डायशोवा के निर्यात-मूल्य घरेलू मूल्यों से कम नहीं थे और अन्य विदेशी बाजारों को किए गए निर्यात से मामूली रूप से अधिक थे।

प्राधिकारी का विचार

प्राधिकारी यह बात नोट करते हैं कि सामान्य मूल्य के संबंध में उनके अनुरोध करने पर भी डायशोवा ने सूचना नहीं भेजी है। निर्यातक ने केवल उत्तरी अमरीका के मूल्यों के संबंध में ही सूचना भेजी है।

- (घ) फिन्ले फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज इंक

ट्रांस वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स, नई दिल्ली ने तर्क दिया कि फिन्ले फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज इंक, वेंकूवर, कनाडा मैन्यूफैक्चर्स हाई ब्राइट न्यूजप्रिंट का निर्माण करती है और इसने भारत को कोई न्यूजप्रिंट निर्यात नहीं किया था। इसलिए निर्यातक ने भारत में किसी माल का पाटन नहीं किया है।

प्राधिकारी का विचार

प्राधिकारी यह बात नोट करते हैं कि चूंकि निर्यातक ने जांच-अवधि में न्यूजप्रिंट का निर्यात नहीं किया है इसलिए उस पर नियम 22 लागू होता है।

- (ङ) एलायन्स फॉरेस्ट प्रोडक्ट इंक

कंपनी ने कहा कि उसने भारत में उचित बाजार मूल्यों पर बिक्री की थी और उस पर पाटन को दोष नहीं लगाया जा सकता है।

प्राधिकारी का विचार

निर्यातक ने सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य के संबंध में कोई जानकारी नहीं भेजी थी और इसलिए निर्यातक का दावा अस्वीकृत किया जाता है।

- (च) प्राइस एंड पियर्स

प्राइस और पियर्स के माध्यम से आयात करने के संबंध में कुछ इच्छुक पार्टी (पार्टियों) ने तर्क दिया है कि प्राधिकारी ने जांच शुरू करते समय अर्थात् दिसंबर, 1996 में प्रभावी सामान्य मूल्य गलत ढंग से लिया है। प्राधिकारी ने दिसंबर, 96 में लागू भारतीय उत्पादों के सामान्य मूल्य की तुलना की है और जांच-अवधि के दौरान इसकी तुलना निर्यात-मूल्य से की।

प्राधिकारी का विचार

उपरोक्त तर्क वास्तव में गलत है क्योंकि प्राधिकारी ने प्रारम्भिक जांच परिणामों में जांच शुरू करते समय लागू सामान्य मूल्य को नहीं लिया है। प्राधिकारी ने यूनिवर्सल पेपर एक्सपोर्ट कंपनी, कनाडा प्राइस एंड पीस, यू एस ए और प्राइस एंड पीस, सिंगापुर के मामले में अलग से पाटन की सीमा निर्धारित नहीं की है क्योंकि वे न्यूजप्रिंट के विनिर्माता नहीं हैं और उन्होंने अन्य उत्पादकों द्वारा उत्पादित न्यूजप्रिंट का निर्यात किया है।

- (छ) कॉर्नर बुक

कंपनी ने दावा किया कि इसने भारत को प्रत्यक्ष रूप से अखबारी कागज का निर्यात नहीं किया है और न ही कंपनी ने प्राधिकारी को प्रत्यक्ष तौर से कोई प्रत्युत्तर भेजा है।

प्राधिकारी का विचार

प्राइस एंड पीस ने सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य के संबंध में जानकारी भेजी है जो कॉर्नर बूक से संबंधित है। परन्तु, प्राधिकारी ने पाया कि कंपनी ने अपने सामान्य मूल्य के संबंध में जरूरी और पर्याप्त जानकारी नहीं भेजी है और इसलिए अलग से पाटन की सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

(ज) एबिटीबी कंसोलिडेटेड इंक

कंपनी ने दावा किया कि 30-5-1977 से स्टोन कंसोलिडेटेड और एबिटीबी का विलय हो गया है और एबिटीबी कंसोलिडेटेड इंक नाम की एक नई कंपनी का गठन किया गया है। नई कंपनी ने जांच-अवधि के दौरान भारत को किसी भी न्यूजप्रिंट का निर्यात नहीं किया है। इसलिए, नई कंपनी द्वारा किए जाने वाला निर्यात किसी भी पाटनरोधी शुल्क के अधीन नहीं होना चाहिए। निर्यातक भेजने वाले नए वर्ग के अन्तर्गत आता है और इसलिए उसकी समीक्षा की जानी चाहिए।

परन्तु निर्यातक ने यह बात प्रकट होने पर दावा किया कि हालांकि कंपनी 30-5-1977 को ही अस्तित्व में आई है इसलिए इसे जांच-अवधि में भारत के लिए न्यूजप्रिंट के एक निर्यातक के रूप में विचार किया जाना चाहिए क्योंकि नई कंपनी पहले की दो कंपनियों से मिल कर बनी है जिन्होंने प्राधिकारी को जानकारी भेजी थी। निर्यातक ने अनुरोध किया कि प्राधिकारी को अलग-अलग प्रत्युत्तरों में निहित विवरणों को मिलाते हुए इस कंपनी पर एकल पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करनी चाहिए।

प्राधिकारी का विचार

अपने पर लागू होने वाले शुल्क की राशि के संबंध में एबिटीबी कंसोलिडेटेड इंक द्वारा किए गए दावे पर प्राधिकारी उल्लेख करते हैं कि कंपनी ने प्रारम्भ में स्वयं को नए निर्यातक के रूप में किए जाने के लिए एक अनुरोध किया था। बाद में यह अनुरोध किया गया था कि चूंकि नई कंपनी पहले की दो कंपनियों से मिल कर बनी है इसलिए नई कंपनी पर शुल्क की सिफारिश अलग-अलग कंपनियों के विवरणों को शामिल करते हुए करनी चाहिए। नियम 22 के अंतर्गत एक नई कंपनी के रूप में कंपनी का दावा इस कंपनी में अर्थात् एबीटीबी कंसोलिडेटेड इंक में दो भूतपूर्व कंपनियां अर्थात् स्टोन कंसोलिडेटेड और एबीटीबी-प्राइस शामिल हैं, जिन्हें इन जांचों से संबंधित किया गया है। इस तथ्य का कोई महत्व नहीं है कि नई कंपनी केवल जांच अवधि के बाद ही अस्तित्व में आई क्योंकि नियम 22 के अनुसार कंपनी ऐसे किसी निर्यातक अथवा उत्पादकों से संबंधित नहीं होनी चाहिए जो कि जांच का हिस्सा हैं। इसके अतिरिक्त चूंकि नई कंपनी एबीटीबी कंसोलिडेटेड इंक के पास भूतपूर्व दो कंपनियों अर्थात् स्टोन कंसोलिडेटेड और एबीटीबी-प्राइस से संबंधित इसके किसी भी संयंत्र से सामान निर्यात करने का विकल्प है, इसलिए प्राधिकारी स्टोन कंसोलिडेटेड और एबीटीबी-प्राइस के लिए सिफारिश किए गए शुल्कों से अधिक पाटन रोधी शुल्क की सिफारिश करना उचित समझता है।

तुलना

अनेक इच्छुक पार्टियों द्वारा उठाए गए तर्क और प्राधिकारी के विचार निम्नानुसार हैं :—

- (क) प्राधिकारी ने यह अधिसूचना जारी करते हुए कि वर्तमान मूल्य 550 अमरीकी डालर के इर्दगिर्द है, मौजूदा बाजार की वास्तविकता की अनदेखी की है।

प्राधिकारी का विचार

जैसा कि प्रारम्भिक निष्कर्षों में भी स्पष्ट किया गया है, प्राधिकारी ने प्रचलित प्रथा के अनुसार जांच-अवधि के दौरान तथ्यों पर विचार किया है। प्राधिकारी का यह विचार है कि विश्व-भर के जांच-अधिकारियों द्वारा यह पद्धति अपनाई जा रही है क्योंकि जांच-अवधि के बाद के कारकों पर विचार करने से यह एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया बन जाएगी। वास्तव में जांच के बाद की अवधि में विकास के मुद्दे पर यूरोपीय आयोग में जांच-अधिकारियों के निर्णय को कायम रखते हुए, न्यायालय ने निर्णय किया कि यह आवश्यक है कि जांच-अवधि सीमित और निश्चित अवधि की हो और इस तर्क को स्वीकार करना असम्भव है कि पाटनरोधी कार्रवाइयां समाप्त कर देनी चाहिए या शुल्क लगाने का फैसला केवल इसलिए नहीं लिया जा सकता क्योंकि कंपनियों ने जांच-अवधि के बाद कीमतें बढ़ाई हैं।

- (ख) शून्य या नकारात्मक मार्जिन छोड़ा नहीं जा सकता

अनेक इच्छुक पार्टियों ने दलील दी है कि प्राधिकारी द्वारा प्रारम्भिक निष्कर्षों में पाटन-मार्जिन का जो निर्धारण किया वह गलत प्रतीत होता है क्योंकि प्राधिकारी ने शून्य या नकारात्मक पाटन-मार्जिन को ध्यान में नहीं रखा है। इच्छुक पार्टियों ने तर्क दिया है कि जांच-अवधि के लिए माहवार पाटन-शुल्क की सीमा को एकल पाटन-शुल्क की सीमा में परिवर्तित करते समय सकारात्मक और नकारात्मक पाटन-शुल्क का आवश्यक रूप से समायोजन किया जाता है और शून्य मार्जिन व नकारात्मक मार्जिन की अनदेखी करने की प्राधिकारी की कार्रवाई का कोई वैधानिक या कानूनी आधार नहीं है।

आगे यह दलील दी गई है कि प्राधिकारी की जीरो और निगेटिव डम्पिंग मार्जिन की उपेक्षा की कार्रवाई यूरोपीय संघ में अनुसरण की गई पद्धति से प्रभावित हुई लगती है। इच्छुक पार्टी (पार्टियों) ने दलील दी है कि फिर भी प्राधिकारी ने जांच के दौरान इस वर्ग के सभी सौदों में सीआईएफ निर्यात कीमतों को ध्यान में रखने की यूरोपीय संघ की पुरानी पद्धति का अनुसरण नहीं किया है। अतः यह मानते हुए कि निगेटिव मार्जिन की जीरो मार्जिन पर गणना करनी है, डम्पिंग मार्जिन निकालते समय सभी महीनों के सौदों के सी आईएफ निर्यात कीमत को ध्यान में रखना है।

प्राधिकारी का विचार :

इच्छुक पार्टियों द्वारा यह विवाद उठाया गया कि निगेटिव डम्पिंग मार्जिन को पॉजिटिव डम्पिंग मार्जिन पर आवश्यक रूप से समायोजित किया जाता है जो बिना किसी वैधानिक या कानूनी आधार पर है। ऐसे निगेटिव मार्जिन के प्रति प्राधिकारी की उपेक्षा की कार्रवाई कानून के अनुसार है। कानून निम्नलिखित आधार पर सामान्य मूल्य की निर्यात मूल्य से तुलना का प्रावधान करता है :—

- * भारत औसत सामान्य मूल्य से भारत औसत निर्यात मूल्य;
- * सौदे से सौदे के आधार पर सामान्य मूल्य से निर्यात मूल्य;
- * अगल-अलग निर्यात सौदों के साथ भारत औसत सामान्य मूल्य।

यदि निगेटिव मार्जिन की अनदेखी नहीं की जाती है तो उपरोक्त किसी भी विधि के प्रयोग से प्राप्त परिणाम समान होंगे। कानून में प्रदत्त उपरोक्त तीनों प्रकार की तुलना की दृष्टि से यह सुस्पष्ट है कि कानून में तीनों प्रकार की तुलना के लिए प्रावधान के रूप में निगेटिव डम्पिंग मार्जिन के लिए वही निर्धारण अनावश्यक हो जाता है। यह अच्छी तरह से मान्य है कि विधिकर्ता ने विधि (कानून) में कुछ प्रयोजन से हर शब्द के लिए जो प्रावधान रखा है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं कहा जा सकता। वास्तव में स्टोन कंसोलिडेटेड और एक्विटिबी ने भी संकेत दिया है कि प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया यूरोपीय संघ द्वारा अनुसरण की गई पद्धति के अनुरूप है। जहां तक औसत डम्पिंग मार्जिन निर्धारण के लिए सभी निर्यात मात्राओं के मुद्दे पर विचार का संबंध है, प्राधिकारी ने इस वर्ग में सभी निर्यात मात्राओं पर विचार करते हुए औसत डम्पिंग मार्जिन भी निर्धारित किया है।

(ग) माह से माह के आधार पर तुलना :

अनेक इच्छुक पार्टियों ने दलील दी है कि प्राधिकारी द्वारा प्रारम्भिक निष्कर्षों में अब तक डम्पिंग मार्जिन का जो निर्धारण किया है वह गलत है क्योंकि प्राधिकारी ने सामान्य मूल्यों और निर्यात कीमतों के मासिक आधार पर सामान्य मूल्य की तुलना निर्यात कीमत से की है। इच्छुक पार्टियों ने दलील दी है कि विश्व भर में डम्पिंग-मार्जिन केवल भारत औसत के आधार पर निर्धारित किया जाता है और अब तक सभी मामलों में प्राधिकारी द्वारा यही किया गया है। पार्टियों ने दलील दी है कि यू एस और ई यू में केवल असामान्य परिस्थितियों में ही सौदे से सौदे की पद्धति काम में ली जाती है, जैसे जब माल की बिक्री कम हो। चूंकि घरेलू बाजार में बिक्री की मात्रा भारत को किए गए निर्यातों की मात्रा से दुगुनी थी इसलिए विधान प्राधिकारी को जांच-अवधि के लिए केवल भारत औसत सामान्य मूल्य और भारत औसत निर्यात कीमत के आधार पर ही डम्पिंग मार्जिन के निर्धारण की अनुमति देता है, ऐसी स्टोन कंसोलिडेटेड ने आगे दलील दी है। प्रारम्भिक निष्कर्षों में प्राधिकारी द्वारा तुलना के संबंध में निकाला गया निष्कर्ष प्राधिकारी द्वारा की गई इस टिप्पणी से नहीं निकलता कि घरेलू बाजार में और भारत को निर्यात की कीमतें घट रही थीं। स्टोन कंसोलिडेटेड ने तर्क दिया है कि ऐसे मामलों में, जहां दोनों बाजारों में कीमतों साथ-साथ बढ़-घट रही हों वहां भारत औसत ऐसे उतार-चढ़ावों के समायोजन के लिए बनाया गया है। इसके अतिरिक्त माह भारत औसत के माह के आधार पर डम्पिंग मार्जिन का निर्धारण करना कानून द्वारा प्रमाणित नहीं है।

अपने निवेदन के प्रतिपूर्वाग्रह के बिना स्टोन कंसोलिडेटेड ने आगे दलील दी है कि सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य के आधार पर तुलना की जानी चाहिए क्योंकि स्टोन कंसोलिडेटेड अपने निर्यात सौदों में तिमाही मूल्य अंकन की पद्धति का अनुसरण करती है इसलिए भारत औसत की उपयुक्त अवधि का निर्धारण किसी भी तरह सिर्फ तिमाही के आधार पर ही हो सकता है।

प्राधिकारी का विचार :

तुलना के संबंध में उपरोक्त तर्क वास्तविक रूप से, वैचारिक रूप से और कानूनी तौर पर गलत हैं। प्राधिकारी ने "भारत औसत आधार" पर भी डम्पिंग मार्जिन निर्धारित किया है। परन्तु जांच-अवधि में प्रत्येक माह का भारत औसत सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य निकाला गया है। प्राधिकारी ने जांच-अवधि के दौरान सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य दोनों में महत्वपूर्ण गिरावट की दृष्टि के आधार पर तुलना की है। प्राधिकारी ने यह बात नोट की कि कुछ महीनों में बहुत भारी मात्रा में बिक्री हुई थी जबकि कुछ अन्य महीनों में भारत को कोई निर्यात नहीं हुआ था। उदाहरण के लिए स्टोन कंसोलिडेटेड ने अप्रैल और अक्टूबर, 1996 के दौरान भारत को निर्यात नहीं किया। इस मामले की पूरी जांच-अवधि के लिए भारत औसत सामान्य मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण और इसकी निर्यात मूल्य से तुलना (जो केवल सात में से पांच माह में की गई बिक्री के लिए निर्यात मूल्य का निरूपण करती है) करना अपर्याप्त और अनुचित होगा और यहां तक कि भ्रामक भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में जहां जांच-अवधि में केवल एक माह में माना कि अक्टूबर, 1996 में भारत को निर्यात

हुए हों और जांच-अवधि में कीमतों में कमी हुई हो, जैसा कि मौजूदा मामले में, वहां तुलना के लिए भारत औसत के आधार पर निकाले गए परिणाम एकदम भ्रामक और डम्पिंग को दर्शाने वाले हो सकते हैं, जबकि हो सकता है निर्यातक द्वारा किसी डम्पिंग का सहारा नहीं लिया गया हो। बात सही भी है। चूंकि जांच-अवधि के कुछ महीनों में स्टोन कंसोलिडेटिड और एविनोर के मामले में भारत को कोई निर्यात नहीं हुए इसलिए माह-वार औसतों के आधार पर तुलना करना समूची जांच-अवधि के लिए एकल औसत की अपेक्षा अधिक उपयुक्त है। भिन्न-भिन्न निर्यातकों के लिए तुलना की भिन्न विधियों को अपनाना भी अनुपयुक्त होगा। इसके अतिरिक्त, किसी भी इच्छुक पार्टी (पार्टियों) ने यह प्रदर्शित नहीं किया है कि माह से माह के आधार पर सामान्य मूल्य की निर्यात मूल्य से तुलना करने के परिणाम तुलना में विकृतियां, यदि कोई हो, कैसे आई हैं।

अलग-अलग निर्यातकों के मामले में पाटन सीमा निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या निर्यातक का नाम	पाटन सीमा (निर्यात कीमत का प्रतिशत)
1. कनाडा के मामले में (क) ए बी टी बी (ख) स्टोन कंसोलिडेटिड (ग) एवनर मेरीटाइम्स	
2. यू एस ए के मामले में ए बी टी बी	
3. रूस के मामले में (क) बालाखाना (ख) कोंडोपोंगा (ग) सोलीकाम्स	

छ. क्षति

विभिन्न इच्छुक पार्टियों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बारे में व्यक्त किए गए विचार और प्राधिकारी की टिप्पणियां निम्नानुसार हैं:-

दिए गए तर्क :

जांच अवधि के दौरान संदर्भाधीन देशों से आयात कीमतों की तुलना में भारतीय उद्योग की भारत में अखबारी कागज की कीमतें ज्यादा थीं। इन परिस्थितियों में क्षति का कोई भी प्रश्न नहीं हो सकता है।

प्राधिकारी का मन्तव्य:

यह तर्क वैधानिक रूप से और कानूनी रूप से गैर तर्क संगत है चूंकि आयातकों के दावे ही घरेलू उद्योग के तर्क की पुष्टि करते हैं कि संदर्भाधीन देशों से उपलब्ध ज्यादा सस्ते आयातों के कारण से अपनी कीमतें कम करने पर मजबूर होना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय बाजार में कम कीमत मांगने की स्थिति पैदा हुई। इससे यह भी प्रमाणित होता है कि घरेलू उद्योग को पाटन के कारण क्षति हुई।

दिए गए तर्क:

घरेलू उद्योग को कोई वास्तविक क्षति नहीं होगी अगर इसने लाभ कमाए हैं और अगर यह देश में अखबारी कागज की मांग के बराबर अखबारी कागज का उत्पादन नहीं करता है।

प्राधिकारी का मन्तव्य :

उपयुक्त तर्क का कानून समर्थन नहीं करता है। अनुच्छेद 2 के पैरा 4 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि लाभ में गिरावट भी क्षति का संकेत देता है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग को उस स्थिति में भी क्षति हो सकती है, जबकि घरेलू उद्योग को लाभ हुआ है। किन्तु, इस तात्कालिक मामले में घरेलू उद्योग की जांच-अवधि के पहले वाली स्थिति की तुलना में जांच अवधि में क्षति हुई है जैसा कि प्राधिकारी ने प्रारम्भिक जांच परिणाम में स्पष्ट किया है। इसके साथ-साथ ऐसा सुझाव देने का कोई प्रावधान नहीं है कि घरेलू उद्योग को कानून के अन्तर्गत किसी सहायता की मांग करने से पहले देश की मांग को पूरा करने की स्थिति में होना चाहिए। याचिका दायर करने के बारे में याचिकाकर्ता की योग्यता के संबंध में शर्तों को नियमों के अन्तर्गत अच्छी तरह से निर्धारित किया गया है। जहां तक मांग आपूर्ति की स्थिति का संबंध है, घरेलू उत्पादक की क्षमता मांग से ज्यादा या कम हो सकती है। यह तर्क न्याय-संगत नहीं है कि उस आयातित मात्रा पर कोई शुल्क नहीं लगाया जा सकता है जो कि देश में उत्पादित अखबारी कागज से ज्यादा है, क्योंकि प्रतिपाटन का उद्देश्य कोई कात्रात्मक प्रतिबंध लगाना नहीं है, बल्कि केवल कीमतों के बारे में उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति सुनिश्चित करना है।

दिए गए तर्क :

एक्सप्रेस पब्लिकेशन का यह तर्क प्रमाणित नहीं होता है कि भारतीय उत्पादकों ने कीमतों में वृद्धि आयात कीमतों के अनुसार की और कीमतों में कमी नहीं की जब अंतर्राष्ट्रीय कीमतें गिर गईं। वह कंपनी ने आयातित अखबारी कागज की कीमत सी एंड एफ भारतीय बंदरगाह तथा भारतीय मिलों के द्वार पर कीमत की तुलना की, जो कि इसके तर्क की पुष्टि करने के लिए निम्नानुसार दर्शाया गया है :

अवधि		कनाडियन कीमतें सी एंड एफ	भारतीय उत्पादकों द्वारा मांगी गई कीमत		
			एच एन एल	टी एन पी एल	एम पी एम
अप्रैल-जून	1995	27606	27000	27925	27875
जुलाई-सितम्बर	1995	31496	27000	27925	27875
अक्टूबर-दिसंबर	1995	34342	27000	27925	27925
जनवरी-मार्च	1996	30915	27000	27925	27875
अप्रैल-जून	1996	24535	27000	27925	27875
जुलाई-सितम्बर	1996	20735	23000	24210	23000
अक्टूबर-दिसंबर	1996	17208	21000	21820	21800

उपर्युक्त के आधार पर प्राधिकारी की टिप्पणी यह है कि इच्छुक पार्टियों का यह तर्क प्रमाणित नहीं है कि भारतीय उत्पादकों ने आयात कीमतों के अनुसार कीमतें बढ़ाई और कीमतें नहीं घटाई। बल्कि इससे यह प्रमाणित होता है कि घटती हुई आयात कीमतों के कारण घरेलू उद्योग को अपनी उचित बिक्री कीमत की तुलना में अपनी कीमतों काफी कम करनी पड़ी, जिसके कारण भारतीय बाजार में कम दाम मांगने की स्थिति आ गई। इस सारणी से यह भी पता चलता है कि अप्रैल, 1995—जून, 1996 की अवधि के दौरान भारतीय कीमतों के स्थिर रहने पर भी कनाडियन कीमतें घट रही थीं।

दिए गए तर्क :

अखबारी कागज के उत्पादन के लिए बांस, यूकलिप्टस की लकड़ी और सलाई की लकड़ी की जरूरत होती है। बांस को छोड़कर किसी भी प्रकार की लकड़ी काटने पर 12-12-1996 से प्रतिबंध है। इसे देखते हुए प्राधिकारी को यह जांच करनी चाहिए कि घरेलू उद्योग कच्चे माल की अपनी आवश्यकता का प्रबंध कैसे करेगा।

प्राधिकारी का मतलब :

भारतीय के अन्तर्गत प्रतिपाटन प्रविधानों के लिए यह आवश्यक है कि शुल्क को उसी राशि तक ही प्रतिबंधित किया जाएगा जो कि घरेलू उद्योग की क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त माना जाता है। पाटन के अतिरिक्त अन्य कारणों के क्षति (कच्चे माल की उपलब्धता नहीं होने के कारण उत्पादन लागत में वृद्धि को शामिल करके) पर प्रतिपाटन शुल्कों की मात्रा के निर्धारण हेतु विचार नहीं किया जाता है। इसके साथ-साथ, कोई इच्छुक पक्ष समीक्षा के लिए प्राधिकारी के पास जा सकता है अगर यह दिखाया जाता है कि जांच की अवधि के बाद परिस्थितियों में काफी परिवर्तन हो गया है।

दिए गए तर्क :

प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा वसूली गई कीमतों की औचित्यता पर ध्यान दिए बिना पाटन अवधि के पहले भारतीय मिलों द्वारा लाभ या हानि में गिरावट पर ध्यान दिया।

प्राधिकारी ने निर्यातकों द्वारा भारत के लिए और अन्य विश्व बाजार के लिए उधृत की गई कीमतों की तुलना नहीं की है। बिना ऐसी तुलना के यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है कि निर्यातकों की कीमत से भारतीय अखबारी कागज उद्योग को क्षति हुई।

प्राधिकारी का मतलब :

यह न तो प्रति पाटन कानूनों के कानूनी ढांचे के अन्तर्गत है न ही घरेलू उद्योग द्वारा जांच अवधि से पहले वसूली गई कीमतों की न्यायोचितता की जांच करना वर्तमान जांच का उद्देश्य है।

दिया गया तर्क :

प्रारम्भिक जांच परिणाम में यह नहीं बताया गया है कि भारतीय बाजार बढ़ रहा है या घट रहा है या स्थिर बना हुआ है। बढ़ते बाजार में आयात की बढ़ी हुई मांग को आयातों से घरेलू उद्योग द्वारा को हो रही क्षति का संकेत नहीं माना जा सकता।

घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों में गिरावट उच्चतम कीमतों के कारण है न कि सामान्य कीमतों के कारण।

याचिकाकर्ता का एक गैर प्रमाणित कथन यह है कि भारत में कुछ मिलों ने पाटन के कारण उत्पादन रोक दिया है और सूचना और विश्लेषण के बिना इसे पाटन से जोड़ना संभव नहीं है।

क्रेता अपनी आपूर्ति के स्रोत के लिए भारतीय मिलों पर निर्भर नहीं करते थे और निर्यातकों का विश्वसनीयता को देखते हुए उन्होंने विदेशी

विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता से आयात करना पसंद किया।

प्राधिकारी का मतव्य

प्रतिपाटन शुल्कों का उद्देश्य आयातों को किसी एक विशेष स्रोत तक प्रतिबंधित करना नहीं है। उपभोक्ता अभी भी अपनी आपूर्तियों का स्रोत चुनने को स्वतंत्र हैं। अखबारी कागज की बढ़ी हुई मांग के बारे में दिए गए तर्क में भी कोई दम नहीं है कि थूँक प्राधिकारी ने अपने आंच परिणाम बाजार हिस्से में परिवर्तनों के संबंध में दिया है।

दिए गए तर्क :

यधिकारकर्ता के इस विचार को देखते हुए कि घरेलू उद्योग द्वारा बिक्री की कीमतों में कमी के बावजूद आयातों के कारण बिक्री कम होती जा रही थी, पाटन के अतिरिक्त अन्य कारणों से क्षति होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे कारणों के उदाहरणों में गुणवत्ता, अंतर, विश्वसनीयता, समयपरकता और आपूर्ति की निर्भरता शामिल है।

प्राधिकारी का मतव्य :

यह तर्क अनुमानित है जैसा इन आंच परिणामों में बाद में स्पष्ट किया गया, ऐसे संकेत देने का पर्याप्त प्रमाण है कि संदर्भाधीन देशों से आयातित अखबारी कागज को तरजीह देना कीमत के कारण था न कि अन्य कारणों से।

घरेलू उद्योग की क्षति पर प्राधिकारी का निष्कर्ष :

22. घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बारे में प्राधिकारी का जांच परिणाम : घरेलू उद्योग को क्षति के बारे में प्रारम्भिक जांच परिणामों में अधिकारी द्वारा बताई गई तथ्यात्मक सूचना और घरेलू उद्योग को प्रभावित करने वाले विभिन्न आर्थिक संकेतकों के बारे में किसी भी पार्टी ने विवाद नहीं किया है। अनेक इच्छुक पार्टियों ने आयात, बाजार हिस्से और घरेलू उद्योग को प्रभावित करने वाले कारणों से संबंधित मानदंडों में परिवर्तन को उचित ठहराने वाले तर्क दिए हैं। प्राधिकारी का विचार यह है कि प्रति-पाटन प्रावधानों के ढांचे के अन्तर्गत विश्लेषण किया जाना है। नियमों के अनुच्छेद 11 में निम्नानुसार कहा गया है :

“क्षति के निर्धारण में (क) पाटित आयातों की मात्रा तथा समान वस्तु के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों का प्रभाव एवं (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों का इसके परिणामस्वरूप पड़ने वाला प्रभाव दोनों की ही निष्पक्ष जांच शामिल होगी”

नियमों में और व्यवस्था यह है कि :

“संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उन सभी संबद्ध आर्थिक कारणों और संकेतकों का मूल्यांकन शामिल होगा जिसका प्रभाव उद्योग पर पड़ता है, जिसमें शामिल है.....”

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है या नहीं, उसे प्रमाणित करने के लिए ऐसे व्यवहार के कारणों की जांच करनी होगी। प्राधिकारी आगे यह नोट करते हैं कि प्राधिकारी को सभी कारणों की जांच करनी होती है जिन्हें संबद्ध माना जाता है, और इस प्रकार जो कारण संबद्ध नहीं माना जाता उस पर ध्यान नहीं दिया जा सकता है।

23. उपर्युक्त को देखते हुए इन अंतिम जांच परिणामों के लिए प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की क्षति का विश्लेषण किया। विस्तृत विवरण के साथ-साथ प्रारम्भिक जांच परिणामों में स्पष्ट किए गए विस्तृत विवरण पर यह निर्णय लेने के लिए विश्वास किया जा रहा है कि घरेलू उद्योग की वास्तविक क्षति की गई है।

बाजार हिस्सा : कुल आयातों में संदर्भाधीन देशों से आयातों का बाजार हिस्सा और उसकी तुलना में भारत में खपत निम्नानुसार है :

(i) **कुल आयातों में बाजार हिस्सा :** भारत में अखबारी कागज के कुल आयात की तुलना में संदर्भाधीन देशों से अखबारी कागज के आयात का बाजार हिस्सा निम्नानुसार है :

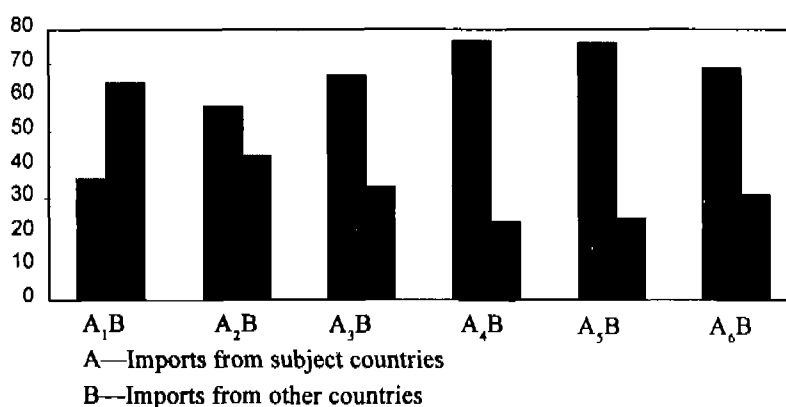


Figure 1 : Trend of share of subject countries in total imports

आंकड़ा 2 : कुल आयातों में संदर्भाधीन देशों के हिस्से का रुख प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि भारत में अखबारी कागज के कुल आयात में संदर्भाधीन देशों से आयातों के बाजार हिस्से में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। ऐसे संकेत देने के स्पष्ट प्रमाण हैं कि आयातकों ने इन देशों की ओर रुख किया।

(ii) कुल मांग में बाजार हिस्सा : भारत में अखबारी कागज की खपत की तुलना में संदर्भाधीन देशों से अखबारी कागज के आयात का बाजार हिस्सा निम्नानुसार रहा है :

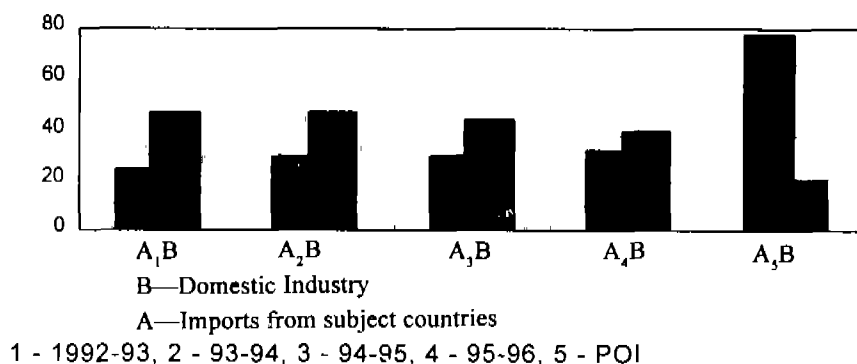


Figure 2 - Trend of market share of domestic industry and subject countries

आंकड़ा 4 : घरेलू उद्योग और संदर्भाधीन देशों के बाजार हिस्सा का रुख (अंतिम अधिसूचना में ग्राफ आना है और सारणी हटाई जाती है) प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कुल आयात में संदर्भाधीन देशों का बाजार हिस्सा और भारत में कुल खपत में रूस से आयातों के मामले में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

24. इच्छुक पक्षों का यह तर्क गैर-प्रासंगिक है कि अखबारी कागज की मांग में वृद्धि दर्ज हुई है तथा यही भारत में आयातों में वृद्धि का कारण है, चूंकि प्राधिकारी ने सकल रूप में और भारत में अखबारी कागज के उत्पादन/खपत के संबंध में संदर्भाधीन देशों के आयातों का विश्लेषण किया है। इस बात की भी प्रशंसा की जा सकती है कि घरेलू उद्योग को प्रभावित करने वाले किसी भी एक मानदंड के घरेलू उद्योग को क्षति या क्षति का न होना प्रमाणित नहीं होता।
25. घरेलू उद्योग की क्षति का विश्लेषण करते हुए अधिकारी को संकेतकों में परिवर्तनों के कारणों का आकलन करने की जरूरत नहीं है। पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध को प्रमाणित करते वक्त परिवर्तनों के कारणों पर ध्यान दिया जाना है। समग्र रूप से उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री के बारे में इच्छुक पक्षों द्वारा दिए गए तर्क संकेतकों में वृद्धि या गिरावट के कारणों से संबंधित हैं। किन्तु, किसी भी इच्छुक पक्ष ने प्रारम्भिक जांच परिणामों पर विवाद नहीं किया है जहां तक इन संकेतकों पर प्राधिकारी की टिप्पणी का संबंध है। इस प्रकार समग्र रूप से उत्पादन क्षमता उपयोग और बिक्री के बारे में प्रारम्भिक जांच परिणाम की पुष्टि होती है।
26. कम कीमत भांगना तथा कीमत को दबाना :
- तीन देशों की औसत निर्यात कीमतों की तुलना और घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति (नेपा को छोड़कर) निम्नानुसार दिखती है :—

अवधि	औसत उतराई कीमत (रु. प्र.मी.ट.)	निवल बिक्री वसूली (रु. प्र.मी.ट.)	अंतर (रु. प्र.मी.ट.)
	(क)	(ख)	(ग)
1994-95	15615	20119	4504
1995-96	28709	27556	-1153
1996-97			
अप्रैल, 96	28740	27906	-803
मई, 96	26207	27722	1515
जून, 96	23984	27559	3575
जुलाई, 96	24629	25817	1188
अगस्त, 96	21945	22192	247
सितम्बर, 96	21758	21955	197
अक्तूबर, 96	21458	21137	-321
औसत	23685	25132	1447

** नेपा पर बिना विचार किए हुए, अर्थात् केवल टी एन पी, एल एच एन एल और एम पी एम की बिक्री से प्राप्ति।

27. ऊपर दर्शाए गए तीनों देशों की औसत निर्यात कीमतों की तुलना और घरेलू उद्योग (नेपा को छोड़कर) की निवल बिक्री प्राप्ति से यह पता चलता है कि बिक्री कीमतों के उपर्युक्त विश्लेषण से संदर्भाधीन देशों के निर्यातों से घरेलू उद्योग की कीमतों को 6.11% तक कम दाम मिलता था तथा इससे भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों पर और ज्यादा दबाव पड़ता था।
28. उपर्युक्त को देखते हुए प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संदर्भाधीन देशों से निर्यातों के परिणामस्वरूप जांच अवधि के अन्त तक कम दाम मिलने और कीमत दबाव की ऐसी स्थिति आ गई कि निर्यातकों ने अपनी लागत कीमत से कम कीमत पर भारत में अखबारी कागज का निर्यात करना आरम्भ कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें घाटा हुआ। इसके साथ-साथ घरेलू उद्योग में कीमत की मंदी की ऐसी स्थिति आई कि इसे अपनी उत्पादन लागत से काफी कम कीमतों पर अखबारी कागज बेचने के लिए बाध्य होना पड़ा। जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय हानि हुई। प्राधिकारी आगे यह नोट करते हैं कि संदर्भाधीन देशों से आयातों के परिणामस्वरूप कम कीमत मांगने और कीमत की मंदी की ऐसी स्थिति हो गई कि कनाडा के कुछ निर्यातकों ने भारत में उत्पादन लागत से कम कीमत पर निर्यात करना आरम्भ किया जिसके परिणामस्वरूप उन्हें चौथी तिमाही, 1996 में वित्तीय हानि हुई।
29. नेपा द्वारा उत्पादित अखबारी कागज की गुणवत्ता के बारे में तर्क दिए गए हैं किन्तु, किसी भी इच्छुक पक्ष ने नेपा द्वारा उत्पादित अखबारी कागज की गुणवत्ता के प्रभाव को नहीं दर्शाया है और किसी भी इच्छुक पक्ष द्वारा किसी भी तरह का कीमत समायोजन नहीं किया गया है। किन्तु यह पाया गया कि नेपा की बिक्री अधिप्राप्ति बाकी बची तीनों कंपनियों जिनमें घरेलू उद्योग शामिल है, की बिक्री अधिप्राप्ति से काफी कम है। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि नेपा की बिक्री अवधि प्राप्ति को प्रभावित करने वाले अन्य कारक भी हैं। इस प्रकार, घरेलू उद्योग की उचित बिक्री कीमत निकालने के लिए प्राधिकारी ने नेपा की उत्पादन लागत पर ध्यान नहीं दिया।
30. वर्ष 1990-96 के बीच एक्सप्रेस प्रकाशन के वितरण आंकड़े के विश्लेषण से निम्नांकित का पता चलता है :—

वर्ष	अखबारी कागज की कीमत	प्रतियां (संख्या)	कीमत रु.	कमीशन के बाद निवल कीमत (रु.)
अप्रैल-जून, 95	27606	267137	2.25	1.74
जुलाई-सितम्बर, 95	31496	263054	2.25	1.74
अक्टूबर-दिस., 95	34342	263054		
अप्रैल-जून, 96	24535	274011	2.25	1.74
जुलाई-सितम्बर, 96	20735	274011	2.25	1.74
अक्टू.-दिस., 96	17208	284112	2.25	1.74
			(1.50 बंगलोर)	1.16

प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि अखबारी कागज की कीमत की तुलना में अखबारों की कीमतें अलोचशील हैं, चूंकि वह 2.25% रु. प्रत्येक प्रति पर बना रहा जबकि आयातित अखबारी कागज की कीमत 34342 रु. पी.एम.टी. से 17208 रु. पी.एम.टी. के बीच थी। प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि संदर्भाधीन देशों के निर्यातों पर प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना, जो कि घरेलू उद्योग की क्षति को रोकने के लिए आवश्यक है; से अखबारों पर कोई गम्भीर परिणाम नहीं पड़ेगा विशेषकर तब जबकि इन उपायों से अन्य देशों से आयात, भारतीय उत्पादकों की आपूर्ति और संदर्भाधीन देशों से उचित कीमत पर आयात को प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव नहीं है।

छ. कारणात्मक संबंध :

28. विभिन्न इच्छुक पक्षों द्वारा व्यक्त किए गए विचार और प्राधिकारी की टिप्पणियां निम्नानुसार हैं :—

दिए गए तर्क

(क) प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को 2 : 1 के कोटा प्रतिबंध को हटाने के परिणामस्वरूप होने वाली क्षति को अलग नहीं किया है तथा इस प्रकार, पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध औपचारिक रहे हैं।

प्राधिकारी का तंतव्य :

प्राधिकारी इसकी प्रशंसा करते हैं कि 2 : 1 के कोटा प्रतिबंध को हटाने के परिणामस्वरूप सकल रूप में आयात में वृद्धि हो सकती थी। किन्तु, घरेलू उद्योग को क्षति एवं पाटन से उसके कारणात्मक संबंध के बारे में प्राधिकारी के जांच परिणाम सकल रूप में आयातों में वृद्धि पर आधारित नहीं हैं। जैसा कि क्षति से संबंधित पैरा में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है, कि भारत में अखबारी कागज के कुल आयात की तुलना में संदर्भाधीन देशों से आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई। आगे, कारणात्मक संबंधों का जांच परिणाम, भारतीय बाजार में अखबारी कागज की कीमतों पर इन आयातों के प्रभाव पर आधारित है।

कीमत वसूली और कम कीमत मांगने के बारे में प्राधिकारी के जांच परिणामों पर यह मानते हुए विश्वास किया जाता है कि पाटित आयातों द्वारा घरेलू उद्योग को हानि पहुंचाई गई है।

दिए गए तर्क :

(ख) जांच की प्रारम्भिक कार्यवाई से संबंधित नियम 5(2) में कहा गया है कि आवेदन में पाटन क्षति और कारणात्मक संबंध के प्रमाण शालि होंगे। नियम में आगे यह कहा गया है कि आवेदन में क्षति और कारणात्मक संबंध “जहां लागू है” के परिणाम शामिल होंगे।

प्राधिकारी का तंतव्य :

प्राधिकारी को विशेषीकृत देश से आयात के मामले में घरेलू उद्योग को क्षति तथा पाटन और क्षति के बीच संबंध के बारे में जांच परिणाम देना होता है। तदनुसार, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति एवं पाटन तथा क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में अपने जांच परिणाम दिए हैं।

(ग) खुद याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि “अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट के साथ-साथ अखबारी कागज के पाथन से भारतीय उद्योग को क्षति हुई है।” इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि केवल पाटन से उद्योग को क्षति नहीं हुई है। अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट से क्षति हुई है। प्रति-पाटन शुल्क लगाने से विदेशी आपूर्तिकर्ता भारतीय बाजार में बेचने से आशंकित रहेंगे। वे कृत्रिम रूप से कीमतें बढ़ा देंगे। अतः इसे लगाया जाना जनहित में नहीं होगा।

प्रारम्भिक जांच परिणाम में ऐसे कोई प्रमाण नहीं हैं जो कि बिक्री में हुई क्षति को सीधे ही संदर्भाधीन देशों के निर्यातों से जोड़ती है। पाटित आयातों की मात्रा के बारे में, अधिसूचना में बताए गए प्रत्येक देश में से अलग-अलग आयात स्तर की पहचान नहीं की गई है। पाटित आयातों की न्यूनतम मात्रा के मापदंडों को देखते हुए प्राधिकारी को कनाडा से आयात के स्तर का निर्धारण करना चाहिए और अगर यह 3% से कम पाया जाता है तब प्राधिकारी का डब्ल्यू टी ओ के अन्तर्गत दायित्व है कि वह कनाडा के विरुद्ध जांच खत्म कर दें।

प्राधिकारी का मतव्य :

पाटित आयातों की मात्रा के बारे में, वह न्यूनतम स्तर से ज्यादा है, जैसा कि क्षति से संबंधित पैरा में दिया गया है। पाटन के अतिरिक्त घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाले अन्य कारकों के बारे में प्राधिकारी का विचार है कि घरेलू उद्योग की क्षति को उत्पादन लागत के अधिकतम स्तर पर विचार करके तथा उस पर उचित लाभ की अनुमति देकर प्रतिबंधित कर दी गई है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि भारतीय कानून में पहले से कम शुल्क प्रावधान (जिसके द्वारा घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त समझे जाने पर पाटन सीमा की तुलना में कम शुल्क का सुझाव देने का प्राधिकारी का दायित्व है तथा जो कुछ देशों में न तो गाट समझौते में नहीं या प्रतिपाटन कानूनों में ही एक दायित्व है) में घरेलू उद्योग द्वारा झेली जा रही अन्य समस्याओं का ध्यान रखा गया है। जहां तक नेपा की क्षति, जो कि घरेलू उद्योग के अन्य घटकों की कोमल रही कीमत प्राप्त करने में इसकी असमर्थता का संबंध है, प्राधिकारी ने उत्पादन लागत और उचित बिक्री कीमत पर पहुंचने के लिए नेपा की उत्पादन लागत को शामिल नहीं किया है। इस प्रकार, अन्य कारणों से नेपा को हुई क्षति पर विचार नहीं किया जाता है।

झ. अन्तिम जांच-परिणाम

29. उपर्युक्त पर विचार करने के बाद प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं।

(क) यू. एस. ए. कनाडा और रूस के उद्गम वाले या वहां से निर्यातित अखबारी कागज का भारत में निर्यात इसके सामान्य मूल्य से कम पर किया गया है ;

(ख) घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है ;

(ग) यू. एस. ए. कनाडा और रूस के उद्गम वाले या वहां से निर्यातित के कारण वे घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।

30. प्राधिकारी प्रतिपाटन शुल्क लागू करने के बारे में प्रारम्भिक जांच परिणाम की पुष्टि करते हैं और संदर्भाधीन देशों के उद्गम वाले या वहां से निर्यातित अखबारी कागज के सभी आयातों पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाने का सुझाव देते हैं। यह शुल्क, कौंडोपोंगा और सोलो कामस्की के मामले को छोड़कर, कालम 2 में बनाई गई राशियों एवं आयातों के उत्तराई मूल्य के बीच का अन्तर होगा। किन्तु कौंडोपोंगा और सोलो कामस्की के मामले में कोई भी प्रतिपाटन शुल्क वसूल नहीं होगा चूंकि प्राधिकारी ने नियम 14 के अनुसार इन निर्यातकों के कीमत वचनबद्धता स्वीकार करती है किन्तु, ऐसे मामले में जहां उक्त निर्यातकों द्वारा किया गया निर्यात पाटन से संबंधित ऊपर के पैरा में दर्शाई गई कीमतों से कम कीमत पर किया जाता है, तब क्रम सं. 3 ख (कालम 2 कोई भी निर्यातक) में बताए गए अनुसार प्रतिपाटन शुल्क देय होगा। इस उद्देश्य से आयातों का उत्तराई मूल्य वह आकलन योग्य मूल्य होगा जिसका निर्धारण सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के तहत सीमा शुल्क विभाग और मूल सीमा शुल्क के प्रचलित आधार द्वारा उस कीमत पर किया जाएगा।

क्र. सं. निर्यातक का नाम

संदर्भ राशि रु.

(प्रति मै. ट.)

1	2
1. कनाडा से निर्यात	
क. स्टोन कंसोलिडेटेड	29696
ख. एबीटीबी प्राइस इंक	25786
ए बी टी बी कंसोलिडेटेड इंक	26696
एवनर मेरीटाइम इंक	26642
कोई और निर्यातक	26696
2. यू. एस. ए. से निर्यात	
एबीटीबी प्राइस इंक	26696
कोई और निर्यातक	26696
3. रूस से निर्यात	
क. जे एस सी “बोलगा” बालाखाना पेपर मिल्स	22958
ख. कोई और निर्यातक	22858

41. उपर्युक्त के अधीन, प्राधिकारी दिनांक 14-6-1996 को प्रारंभिक जांच परिणामों की पुष्टि करते हैं।

42. उपरोक्त अधिनियम के अनुसार, इस आदेश के खिलाफ एक अपील सीमा शुल्क, आबकारी और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय ट्रिब्युनल के पास की जा सकती है।

रति विनय झा, निर्दिष्ट प्राधिकारी

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th March, 1998

FINAL FINDINGS

Subject: Anti dumping Investigations concerning Imports of newsprint from USA, Canada and Russia - Final Findings

21/ADD/96 — Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, thereof:

A. PROCEDURE

1. The procedure described below has been followed:
 - i) The Designated Authority notified Preliminary Findings vide Notification no 21/ADD/IW dated the 11th June, 1997 and requested the interested parties to make their views known in writing within forty days from the date of its publication;
 - ii) The Authority forwarded a copy of the preliminary findings to known interested parties, who were requested to furnish their views, if any, on the preliminary findings within forty days of the date of the letter;
 - iii) The Authority also forwarded a copy of the preliminary findings to the Embassy of the United States of America, and Russia and High Commission of Canada in New Delhi with a request that the exporters and other interested parties may be advised to furnish their views on the preliminary findings;

A number of interested parties requested for extension of time to file comments on the preliminary findings, which was, in case the request for extension was made in time, allowed upto 25.7.1997;

- iv) The Authority provided an opportunity to all interested parties to present their views orally on 7th Aug., 1997. The following parties attended the oral hearing:
 - Ananda Bazar Patrika
 - Dalshowa Sales Ltd.
 - Dalshowa Inc.
 - The Tribune Trust
 - General Trading & Sales Corpn.
 - Hindustan Times
 - Valia Bros (P) Ltd.
 - Manipal Printers and Publishers
 - Kasturi & Sons
 - Amarchand & Mangaldas
 - Indian Newsprint Manufacturers Association
 - Newsprint Sales Corporation

- Newsprint Trading and Sales Corpn.
- Indian Agro Paper Mills Association
- Overseas Trading
- Indian Paper
- Mysore Paper Mills
- IAPMA
- AISPMA(All India Small Paper Mills Association)
- The Sandesh Ltd.
- Parikh Paper Agencies (P) Ltd.
- Mekor Int. Consortium Moscow
- Russian Trade Representation
- Ushodaya Publication
- Canadian High Commission
- Indian Express
- Irinco Exports
- Ushodaya Enterprises
- Malayala Manorama
- Times of India
- Rajinder Narayan and Company.
- Indian Newspaper Society
- Aaj
- J. Sagar and Associates
- Express Publication (Madurai) Ltd.

All parties presenting the views orally were requested to file written submissions of the views expressed orally. The parties were advised to collect copies of the views expressed by the opposing parties and were requested to offer their rebuttals, if any. The Authority allowed a number of interested parties, upon request, to present their views orally after 7th Aug., 1997 also;

- v) In accordance with Rule 16 of the Rules supra, the essential facts/basis considered for these findings were disclosed to known interested parties and were allowed to offer their comments, if any. Comments received on the same have also been considered in these findings;
- vi) A number of parties requested for inspection of the public file maintained by the Authority. All parties who made request for inspection, in writing, were allowed to inspect the non-confidential version of the evidence submitted to the Authority by various interested parties;
- vii) A number of interested parties requested for copies of the evidence submitted by various interested parties. All parties who made request for specific documents were supplied the same,
- viii) Abitibi Consolidated Inc. requested that the confidential information furnished by them to the Authority should not be divulged to any party in the Government of India, including Ministry of Finance and it should be used only for the purpose of determination of normal value, export price and dumping margin by the Authority;
- ix) The Authority made available only the non-confidential version of the evidence presented by one interested party to the other interested parties. Information furnished on confidential basis by one interested party has not been made available to any other interested party(ies).

- x) Subsequent to the appointment of new Designated Authority by the Central Government on 17th Dec., 1997, all interested parties were advised to indicate if they would like to explain orally the submissions made by them, which were already on record, in accordance with Rule 6(6). The interested parties were informed that they could appear before the Authority on 12th Feb., 1998, if so desired to explain their case orally. The disclosure made by the then Designated Authority vide its letter dated 6.11.97, was examined independently by the new Designated Authority, who concluded that the essential facts disclosed in the communication dated 6.11.97 will form the basis of her final findings also. No further disclosure of essential facts was, therefore, considered necessary.
- xi) The Authority held an oral hearing on 12th Feb., 1998. It was clarified that no new issues could be brought up and that the arguments should be limited to issues already presented before the previous Authority. No written statements were taken on record.
- xii) The investigations have been concluded within the time limit extended by the Central Government, i.e., 19th March, 1998.
- xiii) Confidential information has been suppressed in this public version of the order and the same has been shown as "*****" or "*****"
- xiv) The arguments made by various interested parties have, to the extent possible, been brought out at respective places in these findings, alongwith the examination of the same by the Authority. Other arguments and the arguments raised by the petitioner have been brought out separately in these findings, alongwith the examination of the same by the Authority. The arguments raised by the interested parties have been brought out as "arguments raised" and the examination thereof by the Authority has been shown as "Authority's position"
- xv) The information furnished by the petitioner and co-operative exporters were verified by the Authority, to the extent deemed necessary, in accordance with the Rules. Information furnished by Abitibi, Stone Consolidated, Avenor, Kondoponga, Balakhana, Solikams, MPM, TNPL, HNL and Nepa was, in particular, verified by the Authority;
- xvi) GATT/WTO agreement referred to in these findings refers to the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade, 1994;
- xvii) Abbreviations: The following abbreviations have been used in these findings:

<u>Word</u>	<u>Used for</u>
Abitibi	Abitibi-Price Inc.
Avenor	Avenor Inc.
Authority	Designated Authority
Balakhana	JSC Volga (Balakhana Paper Mills)
Solikamsk	JSC Solikamskprom
Kondoponga	Kondoponga Pulp and Paper Mill
Rules	The Rules made under Customs Tariff Act supra
INS	Indian Newspaper Society
INMA/petitioner	Indian Newsprint Manufacturers Association
HNL	Hindustan Newsprint Ltd.
TNPL	Tamil Nadu Newsprint Ltd.
Nepa	Nepa Ltd
MPM	Mysore Paper Mills Ltd.
Universal	Universal Paper Export Co

SGA
Express Publications

Selling, general and administrative expenses
Express Publications (Madurai) Ltd.

B. VIEWS EXPRESSED BY THE PETITIONER:

2. The views expressed by the petitioner i.e. INMA on various issues are as under:
- a) The investigation period fixed by the Authority is 6 months prior to the filing of complete petition and is in accordance with standard international and domestic practice where investigation period range from six months to one year.
 - b) The petitioner satisfies the standing with regard to filing of petition, as various manufacturers of newsprint in India are its members. Four of the largest manufacturers are also petitioners before the Authority. Petition is neither motivated nor for the benefit of a handful of persons wanting protection. The Rules contains adequate safeguards in this regard, as there are several threshold hurdles that have to be crossed before a petition is entertained by the Authority.
 - c) The newsprint produced by the domestic industry and imported from the subject countries is being used interchangeably. The two are like articles within the meaning of the Rules even though there may be variation in the quality of domestic newsprint and imported newsprint. The definition of like article is wide enough.
 - d) Normal value: Though the petitioner claimed normal value based on copies of invoices/quotations in the domestic market, the Authority has determined normal value on the basis of the information furnished by the exporters, ignoring the data supplied by INMA.
 - e) Export Price: Export price was claimed on the basis of quotations/ invoices, but the Authority adopted the data furnished by the exporters.
 - f) International prices have no relevance for the purpose of deciding dumping and these investigations.
 - g) Injury: The domestic industry has suffered and is suffering injury as a result of dumping and the findings of the Authority in this regard are reiterated and referred to.
 - h) Real revenue of the newspapers is from the advertisements. In January, 1996, when the price of import was US \$ 750 pmt, the advertisement rate per column per cm. in a leading newspaper was Rs. 2150/-. When the import price declined to US \$ 430 pmt, the advertisement rates increased to Rs. 2400/-. No injury would be suffered by the newspaper industry if anti-dumping duty is imposed. Imposition of anti-dumping duty would only give a level playing field to the domestic manufacturers. The lower duty principle adopted by the Authority takes care of inefficiencies of the domestic industry, if any. The importers are thus not made to pay for inefficiency of the domestic manufacturers.
 - i) With regard to long term contracts referred to by the importers, It is pointed out that the long term contracts are not fixed price contracts, and there can be dumping even in case of long term contracts, so long as the export price is lower than the normal value.
 - j) With regard to increase in export price after the investigation period, it is well settled that what is relevant for the purpose of the present investigations are the factors during the investigation period. The question with regard to increase in sales prices subsequent to the investigation period was raised before the European commission also in the Ball Bearing case wherein the Commission observed that the price increase had occurred

after the investigation period and, therefore, had to be ignored. To hold otherwise would "--- allow exporters to manipulate the results by short-lived price increases", the Commission observed. In *Nippon Seiko and Toyo Bearing case* the Court in EU upheld this reasoning (of Commission) by ruling that it is essential that the investigation period is a limited and a specified duration, and that it was impossible to accept the argument that the proceedings must be terminated or duties not levied merely because the companies which were subject to duties have made price increases after the investigation period.

- k) Even Germany with its fully matured economy has deemed fit and proper to impose a total ban on import of Canadian newsprint. EU has restricted the import of newsprint from Canada to 50,000 MT per month by imposing a tariff on any quantity imported beyond this limit. Even the WTO allows a tariff upto 25% to counter inequalities in conditions and obtaining circumstances.
- l) The newspapers have comfortably survived when international prices ruled around US \$ 1000 pmt. There is, therefore, no reason why the newspaper industry should be affected by imposition of anti-dumping duty.
- m) All the newsprint mills are incurring heavy losses whereas newspapers are reaping windfall profits.
- n) Liberalisation of import of newsprint has benefited only 5-6 major newspapers. Small newspapers are at a disadvantage.
- o) The future of entire newsprint and paper industry is at stake, affecting direct employment of 2,00,000 people and indirect employment of over 10,00,000 people.
- p) Continued dependence on imports for the consumers will result in paying much higher prices in the long run and the newsprint industry will become sick.

B. VIEWS EXPRESSED BY THE INTERESTED PARTIES AND EXAMINATION BY AUTHORITY:

- 3. The views expressed by various interested parties, opposing imposition of anti-dumping duties, on scope of investigations, like article, domestic industry, dumping, injury and causal link have been discussed at appropriate places in these findings alongwith examination of the same by the Authority.
- 4. The views expressed by the interested parties on other issues are as follows:
 - l) On justification of duties on newsprint in the light of the Supreme Court decision:
Arguments raised:
 - a) The attention of the Authority is drawn to paras 63, 66, 67, 68, 80, 82, 83, 87, 88 and 101 of the Supreme Court judgement in the *Indian Express Newspapers vs. Union of India case*. The propositions which emerge from this judgement are as follows:
 - ♦ The executive notification levying custom duty has to be issued after taking into consideration all relevant factors on the reasonableness of levy on newsprint.
 - ♦ The Government should strike a just and reasonable balance between the need for ensuring the right to freedom of expression and need to impose social control on the business of a newspaper.

- ♦ The Government should be cautious of the fact that it is dealing with an activity protected by Article 19(1)(a) of the Constitution of India.
- ♦ In deciding the reasonableness of the restrictions imposed, the Govt. should take into account the following:
 - The nature of the right alleged to have been infringed;
 - The underlying purpose of the restrictions imposed;
 - The disproportion of the imposition;
 - The prevailing conditions at the relevant time.
- ♦ A duty on newsprint is regarded as a restriction on the right of newspaper.
- ♦ The effects of any measure which force the newspaper to cut down the pages or increase the prices would be violative of Article 19(1)(a).
- ♦ A tax on newsprint should be capable of being justified as a reasonable levy. The Authority has not determined the impact of its recommendations on the newspapers which import the newsprint. While in every other case the investigation may be limited to be impact of the import, in case of newsprint, the impact of the recommendations on the newspapers ought to be considered in making the recommendations. The recommendations of the Authority will have a direct bearing on the cost of newsprint, which will have direct impact on the freedom of newspapers protected under Article 19(1)(a) of the Constitution of India. The anti-dumping duty is effectuated by Notification U/S 25 of the Customs Act in public interest. While it is indisputable that the newspaper industry should also bear its due share of the total burden of taxation alongwith the rest of the Community, when any taxes specially imposed on newspaper industry, it should be capable of being justified as a reasonable levy.

Authority's position:

The Authority notes that the concept of anti-dumping duty needs to be appreciated in its proper perspective. It appears that the anti-dumping duties are being considered as custom duties by the interested parties. The Authority observes that while anti-dumping duties are collected as duties of customs, the purpose of anti-dumping duties is to ensure that goods are not imported into the Country below their normal values unlike of duties of customs which provide a general protection to the domestic industry. In other words, the nature of anti-dumping duty is to deal with an unfair trade practice and offset the injurious effect of price discrimination resorted to by exporters. Further, it is important to emphasise that anti-dumping duties are not in the nature of tax in as much as the Authority is also empowered to suspend these duties in case of an exporter offering a price undertaking. Anti-dumping duties are exporter specific or country specific and cannot be linked or compared with custom duties either under the law or in the economic sense. There are several safeguards to ensure that interests of an interested party(ies) are not affected in case dumping has ceased or the position has materially changed.

An analysis of circulation figures of Express Publications between April, 1995-Dec., 1996 shows the following:

Year	Newsprint Price	Copies (Nos.)	Price Rs.	Net price after commission (Rs.)
Apr-June, 95	27606	267137	2.25	1.74
Jul-Sep., 95	31496	263054	2.25	1.74
Oct-Dec, 95	34342	263054	2.25	1.74
Apr-June, 96	24535	274011	2.25	1.74
Jul-Sept, 96	20735	274011	2.25	1.74
Oct-Dec., 96	17208	284112	2.25	1.74
			(1.50 Bangalore)	1.16

The Authority notes that the newspaper prices are inelastic to the cost of newsprint, as the same remained at Rs. 2.25 per copy even when the price of the imported newsprint ranged from Rs. 34342 pmt to Rs. 17208 pmt. The Authority concludes that imposition of anti-dumping duties, which is necessary to prevent injury to the domestic industry, on exports from the subject countries will not result in serious implications on the newspapers, particularly when imports from other countries, supplies from Indian producers and imports from the subject countries at fair prices are not proposed to be restricted by these measures.

The Authority holds that the anti-dumping duty being recommended is appropriate, justified, reasonable and consistent with the decision of the Hon'ble Supreme Court referred to above.

Arguments raised:

- b) The Authority should consider the impact of the levy on the newspaper. The Express Publications (Madurai) Ltd. referred to its profit/loss in this regard, which are as follows.

<u>Year</u>	<u>Profit/loss (Rs. in lacs)</u>
1993-94	343.94
1994-95	352.06
1995-96	877.00 (Loss)
1996-97	486.00 (Loss)
(First half year)	

INS also furnished two statements to show the impact of the recommendations made by the Authority on the newspapers. A scrutiny of the statements reveals that INS has furnished loss suffered/fall in profits and likely financial burden on account of the anti-dumping duty recommended and its impact on the profits of the newspaper establishment.

Authority's position.

The Authority notes that no correlation has been established by Express Publications between loss incurred and the customs duty of ten percent as the said duty was levied only on 27th Oct., 1996 while the loss in 1996-97 is lesser than the loss indicated in 1995-96. No impact of duty on Express Publications can, therefore, be established. With regard to argument raised by INS, the Authority notes that INS has apparently furnished as to how much its members will have to pay extra, considering that its members continue to buy from the same source and the same volume. It also appears that some of the INS members have considered the impact of ten percent duty also in these statements. INS has, however, not revealed the impact of this assumed extra burden on overall profitability of the publishers, nor has INS or any other interested party(ies) established that the proposed levy would result in an unreasonable restriction

On the contrary, the Authority is of the opinion that the imposition of the proposed anti-dumping duty would be in the longer and larger interests of the Indian newspaper industry, as brought out in the preliminary findings also. Such duties are also relevant and is required to be imposed to ensure that the Indian newsprint consumers are provided a long term source for their requirement of newsprint.

II) On the petition filed by INMA:

Arguments raised:

- a) The petition is silent as to the exact figures and details of dumping with regard to individual exporters and confines itself to estimates and averages of dumping, though five Canadian and eight Russian exporters have been named therein. The Authority has fallen into error in entertaining such a petition and arrived at preliminary findings on the basis of the figures mentioned therein.
- b) The petition is replete with assumptions and presumptions, for instance, with regard to extra expenditure allegedly incurred by the exporters towards ocean freight and insurance, agents commission, clearing, handling and landing charges etc.
- c) The petitioner has relied upon a number of letters to establish dumping. None of these letters constitutes authentic material on which any arguments or facts can be founded.
- d) The reliance placed on pulp and paper week is erroneous in view of the footnote on it.
- e) Quotations can provide no assistance in so far as evaluation of dumping and its extent are concerned. What is relevant are the actual sales figures. The petitioner has relied upon freight rate quotations of continuous shipments from American President lines whereas newsprint is shipped from Russia in break bulk only.

Authority's position:

The Authority has made preliminary determination of dumping on the basis of the information furnished by the exporters and other information available with the Authority, in case of exports from USA and Canada. In case of exports from Russia, the Authority had to determine normal value on the basis of the best available information in view of non-co-operation by the producers from Russia. The argument that the Authority has relied only on the information furnished by petitioner on dumping is not correct as the Authority has based its findings on the information provided by the co-operating exporters from the said countries.

III) On procedure adopted for preliminary determination:

Arguments raised:

- a) Indian Express, Mumbai wrote that it had not received a copy of the preliminary findings.

Authority's position:

The Authority had forwarded a copy to the company and the findings were published in the Gazette of India, extraordinary. The argument of the interested party(ies) on this account is, therefore, without merit.

- b) Some of the members came to know about the initiation much later and hence asked for extension of time for filing the response. The Authority, however, did not accept extension beyond 28.2.97.

Authority's position:

As brought out in the preliminary findings also, the notice of initiation was published in the Gazette of India, extraordinary on the day the investigations were initiated, and therefore, argument of the interested party(ies) is without merit.

- c) The preliminary findings notified will have the effect of retrospective application of anti-dumping duties, as the investigation period was April-October 1996. This is not permitted under law.

Authority's position:

The argument is factually and conceptually incorrect. The investigation period is chosen to investigate the allegation and no duty would be payable for the period of investigation, unless otherwise specified. The anti-dumping duties in this case are not proposed on retrospective basis. The Authority has not recommended imposition of duty on retrospective basis and, therefore, the contention of the party is factually incorrect.

- d) Prices charged by different foreign suppliers were the same at given point of time. It is further presumed that in free market conditions prevailing in the western countries selling prices there too would have tended to be more or less the same at the given point of time. That being so, it seems anomalous that dumping margin for different suppliers should be so different as worked out by the Authority in its preliminary findings. The significantly different levels of anti-dumping duties recommended by the Authority on Canadian exporters are not justified.

Authority's position:

The Authority has determined actual level of dumping margin and injury margin for individual exporters. Normal values and export prices of individual exporters need not be the same. The argument of the interested party(ies) about normal values and export prices of different exporters is full of presumptions. Information furnished by different exporters reveal that the export price of different exporters at the same point of time were different and not all the parties exported in the whole of the investigation period, resulting in different level of duties.

- e) Based on selective data and information made available by the petitioner and others, the Authority has passed the preliminary findings.

Authority's position:

The argument is factually incorrect. The preliminary findings, as brought therein, are based on the information furnished by the interested parties.

- f) The preliminary findings of the Authority recommending imposition of Anti-dumping duties, provisionally, would result in a serious crisis, more so in view of the following
- Newsprint is a primary and critical raw material that accounts for 50/60% of the total costs of publishing a newspaper;

While levying a ten percent customs duty, the Govt. set a trigger price of US \$ 575 pmt, at which point of time, even the ten percent custom duty should be withdrawn. The Govt. thus made it clear that US \$ 575 is a fair selling price at which the domestic industry is expected to compete and retain its market share. Since the international prices have almost reached this level, the ten percent customs duty should also be withdrawn.

- Suddenly and quite inexplicably, the Authority issued the notification, recommending imposition of Anti-dumping duty of over US \$ 140 pmt.
- The preliminary findings are one-sided, unfair, against principles of natural justice and have been made without giving a hearing inspite of written requests.
- No category of newspaper, especially the small and medium ones will be able to bear the burden of Anti-dumping duty.

Authority's position:

The above arguments are presumptive with regard to reasonableness of the levy. A large number of interested parties, including INS, were aware of the investigations being conducted by the Authority. The Authority initiated investigations on 20.12.1996 and a number of interested parties submitted information and/ or their views, which have been considered by the Authority before arriving at these findings, in accordance with the law. The findings are, therefore, not one-sided, unfair or against the principles of natural justice. The Rules provide for review of anti-dumping duty being recommended in case the circumstances in the post-investigation period have materially changed. The arguments are, therefore, rejected being devoid of merits.

- g) By making the recommendations, the Authority has attempted to give a go-by to the age old principles of demand and supply which governs the price of a commodity, has curtailed the right of the consumers to choose its source of supplies and will render the readers of the papers to suffer the extra levy imposed.

Authority's position:

The recommendations are in accordance with the law, and the above argument of the interested parties is without merit.

- h) The Authority while following the procedure laid down in the law has completely ignored the aspect of being fair to all interested parties and being seen to be fair to all. This is borne by the following facts:
- ♦ Many Interested parties have not been given extension despite delayed communication;
 - ♦ Responses filed by many users have not been considered by the Authority while announcing preliminary findings;
 - ♦ The preliminary findings were received by many interested parties only in the last week of June and therefore these parties could not reply in time;
 - ♦ The preliminary findings is published after almost three and a half months after the last date for submissions.

Authority's position:

The above arguments are without merit and/or are factually incorrect in view of the following:

- i) The preliminary findings were sent by Speed Post to a large number of interested parties, including INS. The preliminary findings were published in the Gazette of India, extraordinary immediately on the day of the findings. A number of leading newspaper carried information about the recommendations. INS even took up the matter appropriately immediately upon the recommendations.

ii) Those interested parties who requested extension with reasonable cause before the due date were given extension.

iii) There is no time limit for completing the preliminary and/or final determination after receipt of information (except for the time limit for completing the investigations), nor does the time gap between the receipt of information and publishing of findings confer any right on an interested party(ies) to file information at a subsequent date. The Authority is required to collate the voluminous data before carrying out the analysis and examination of the information. It would not be feasible to accept the information after the prescribed date as it would make the process an on going exercise which may delay the final findings. It may, however, be added that all submissions have been taken into account for these final findings.

- i) Imposition of anti-dumping duty may result in retaliation by the subject countries in other directions.

Authority's position:

The argument is presumptive. Under the GATT agreement, no country is allowed to take any retaliatory action against any member country which proposes anti-dumping action. The interests of Government of India are adequately safeguarded in this regard.

- j) On oral hearing: The procedure with regard to oral hearing adopted by the Authority is not in consonance with the settled and well established principles of fair play and natural justice. The interested parties were not provided an opportunity of full and proper representation and copies of the representation were not provided before the parties were heard. The order of the Authority that oral hearing would precede the exchange of pleadings and filing of rejoinders also requires re-consideration.

Authority's position:

Under Rule 6(6), the Authority may allow an interested party to present the information orally, but such oral information can be taken into account by the Authority only when it is subsequently reproduced in writing. The Authority notes it is not obligatory on its part to allow any interested party(ies) to present information orally before the preliminary findings. The oral hearing may be given anytime during the course of the investigations.

The contention of the interested parties with regard to the process of conducting oral hearing is also untenable in view of the Rule referred to above, which very clearly provides that the Authority may allow an interested party to present the information orally. The Authority is not obliged to provide copies of documents to all interested parties save as provided in the Rules. Moreover, the interested parties also had the opportunity to inspect the public files as per their convenience. Therefore, the argument that the interested parties did not have opportunity to inspect the documents is not correct. The fact is that hardly any interested party inspected the public file, before preliminary findings. The Authority, therefore, at its own discretion, allowed opportunity to all those interested parties present in the first oral hearing to inspect the public file and request another oral hearing before expiry of time limits for filing written submissions, if considered necessary. A large number of interested parties inspected the public files, made written submissions and were heard orally. Even during the course of these hearings, these interested parties were allowed to file written submission of the views expressed by them at the time of second hearing before the last date for filing written submissions announced on 7 8 1997. Some of the interested parties filed another set of written submissions before the due date, which were duly exchanged by the Authority and have been considered while arriving at these findings. Subsequent to the appointment of new Designated Authority by the Central Government on 17th Dec ,

1997, all interested parties were advised to indicate if they would like to explain orally the submissions made by them before the previous Authority, which were already on record, in accordance with Rule 6(6). The interested parties were informed that they could appear before the Authority on 12th Feb., 1998, if so desired to explain their case orally. The Authority held another hearing on 12th Feb., 1998. It, therefore, cannot be said that any interested party did not have opportunity to present its views orally.

- k) On confidentiality: Any interested party claiming confidentiality has to claim the same based upon articulate and cogent reasons. The basis for confidentiality can only be overwhelming public interest, e.g. public interest affecting paramount national interest like interest in the field of national defence, national security, communal harmony, etc. The Authority is under a statutory obligation to examine the reasons, if any, given by a party claiming confidentiality and allow the claim only if the Authority is satisfied. In any event a complainant cannot claim confidentiality because it is the complainant's case which has to be met by the interested parties opposing the imposition. Unless the facts and figures relied upon by the petitioner and the source is made available to the interested party(ies) opposing the levy, it is impossible for any interested party to rebut the case of the petitioner. In the absence of transparency and availability of pleadings and data the fundamental principle of rule of law that justice should not only be done but seem to be done would be compromised. Frivolous claims of confidentiality will result in every party claiming confidentiality, a situation which is present in the present case wherein the exporters, the Indian agents of the exporters, newspapers and the petitioner claim confidentiality. The Authority should, therefore, formulate clear and cogent guidelines to deal with the issue of confidentiality. Kasturi & Sons contended at the time of hearing on 12.2.1998 that Indian Express was in possession of the confidential documents filed by the petitioner, viz. INMA.

Authority's position:

The above contention of the interested parties with regard to confidentiality is liable to be rejected in view of the following:

- The Authority has a well formulated policy and guideline to allow confidentiality, which is in conformity with the GATT agreement.
- Though the Indian rules are not specific with regard to the nature of information which can be claimed and accepted as confidential, the same has been clearly mentioned in the GATT agreement. Article 6.5 clearly provides that any information which is by nature confidential, for example, because its disclosure would be of significant competitive advantage to a competitor or because its disclosure would have a significantly adverse effect upon a person supplying the information or upon a person from whom the person acquired the information, or which is provided on confidential basis by parties to an investigation shall be treated as such by the Authority. It is also noted that the type of information which can be claimed confidential listed in the GATT agreement is not of exhaustive type but is of an indicative type.
- The Authority understands that non-disclosure of confidential information by the Authority is a practice being followed largely by a number of investigating authorities world-over. In fact, the Authority finds that the investigating authorities in USA in some case relating to injury determination suppressed even the name of the country who was also found to be exporting the goods to USA.
- The Authority has not disclosed any confidential information to any party. The parties are, however, free to share information relating to them with any other party

- i) The Authority has left a number of vital statistics blank in the preliminary findings. Without this vital information being clearly mentioned in the Order, the Authority could not come to any conclusion on the merits of the matter.

Authority's position:

The Authority has passed a detailed order and only the information which is accepted as confidential, or analysis and findings based on such confidential information, has not been mentioned in the order. The Authority is required to maintain confidentiality, as granted to the interested parties under the law. The Authority further notes that there is sufficient disclosure made in the preliminary findings with regard to the information which is considered confidential. Mere non-disclosure of such confidential information has, in no way, curtailed the rights of an interested party(ies) to defend its interests by providing its own case with all relevant information and arguments.

IV) On disclosure of essential facts:

Arguments raised:

The information sought to be furnished under Rule 16 by the Authority does not disclose the essential facts which form the basis of the decision. The various contentions made by them have not been considered by the Authority in the disclosure made. The disclosure does not disclose any facts.

Authority's position:

The contentions which the interested parties have argued as not having been considered in the disclosure statement are in the nature of arguments raised to establish (or disprove) a fact. The interested parties have failed to distinguish between arguments and facts. Facts are different from arguments and since Rule 16 covers disclosure of essential facts (and not of essential arguments), the Authority has disclose only the essential facts. Further, the purpose of Rule 16 is to provide an opportunity to the interested parties to confirm the facts claimed by them and which the Authority proposes to consider to arrive at a just and fair decision. Neither the Authority is required to make up its mind about acceptance or rejection of the facts claimed before receiving comments on the disclosure, nor disclosure of these facts should construe as an acceptance of the claims by the Authority or the methodology to be adopted by the Authority for arriving at a decision.

V) AUTHORITY'S POSITION ABOUT THE INVESTIGATION PROCEDURE ADOPTED:

The Authority has followed due-process of law under the Act and the Rules. All provisions of Rule 6 have been duly complied with. The Authority notes that:

- a) Under Rule 6(2), the Authority is required to forward a copy of the public notice to the known exporters and the Governments of the exporting countries. This has been complied with.
- b) Under Rule 6(3), the Authority is required to provide a copy of the petition to the known exporters and the Governments of the exporting countries. This has been complied with.
- c) The Authority is required to make available a copy of the petition to any other interested party who makes a request thereof in writing. The Authority is, therefore, not bound to suo motto forward a copy to all interested parties. The Authority provided a copy of the petition to those interested parties who made a request in writing.

- d) Under Rule 6(4), the Authority may call for information from the exporters, foreign producers and other interested parties and the same is required to be furnished within 30 days from the receipt of the notice. It is not obligatory on the part of the Authority to call for information from all interested parties, nor is the Authority required to await responses from all those parties who are interested in offering information and/or comments. The Authority is required to give its final recommendations within one year from the date of initiation of the investigations and, therefore, entire investigations have to be completed in a time-bound manner.
- e) Under Rule 6(5), the Authority is required to provide opportunity to the industrial users to furnish information. This has also been complied with.
- f) Under Rule 6(6), the Authority may allow an interested party(ies) to present information orally. This has also been complied with, as brought out above in detail.
- g) Under Rule 6(7), the Authority is required to make available the evidence available with it to all interested parties. Authority maintained a public file, which was kept open for inspection and the same was inspected by a number of parties. The Authority understands that the maintenance of the public file is not a unique practice by the investigating authorities in India. The practice is being followed by a large number of investigating authorities world over. In any case, all interested parties participating in the investigations and who showed their desire to inspect the documents were duly allowed to do so even after the preliminary findings.
- h) The Authority has not passed the preliminary and/or the final order without considering the information furnished on confidential basis. Confidential information has merely been suppressed from the public version of the order passed by the Authority. The confidential version of the order passed by the Authority contains all confidential information. Arguments of the interested party(ies) on this account are factually incorrect. Rule 12(2) and 17(4) provide that the Authority shall issue a public notice recording its preliminary findings and/or final findings. It is this public notice, which has been circulated to all the interested parties and which does not contain the information furnished on confidential basis.
- i) Arguments that some of the interested parties were not even aware of the investigation being carried out by the Authority or there was a considerable delay in getting a copy of preliminary findings deserves to be ignored. There is ample evidence on record to show that the user industry association and a large number of other interested parties were fully aware of the investigations being conducted. Moreover, a public notice was issued in the Gazette of India, Extraordinary, notifying the initiation of the investigations. Some of the newspapers also carried stories on the initiation by the Authority immediately after the initiation. In view of above, the claim of the publishers that they were not even aware of the investigations being conducted can not be appreciated.

With regard to non-receipt of the preliminary findings and request for extension of time to file comments, the preliminary findings were published in the Gazette of India Extraordinary and were simultaneously dispatched by Speed Post to the known interested parties.

Under Rule 6(4) the Authority is required to allow thirty days time to respond to the notification and the letters are deemed to have been delivered within seven days of the date of despatch. Since the Authority allowed forty days time to respond to the initiation notification and/or preliminary findings, it is incorrect to say that sufficient time was not allowed to any interested party(ies). Further, the Authority allowed time upto

27.2 1997 (more than nine weeks, as against about five weeks allowed under the law) for responding to the notice of initiation. Extension was also allowed to respond to the preliminary findings in cases where requests were received before the due date

VI) On investigation period.

Arguments raised:

- a) The investigation period is usually taken as 12 month preceding the month in which Investigations commence. Analysis of normal value and export price for a short period of 7 months is likely to give distorted pictures. If the longer period of 1991-92 to October 96 could be taken to determine the injury, that longer period could well be taken as the period of investigation.
- b) The Authority has looked into the figures of import volumes, market share, production and capacity utilisation from 1991-92 upto October 96. Having taken this period into consideration, the Authority could not restrict this investigation to a limited period of 7 months

Authority's position:

It is a well settled practice that the dumping investigations are based on the detailed analysis and investigation for a well defined period and cannot be left open-ended. Further, the Authority is required to determine injury objectively, as per the principles laid down in Annexure II to the Rules. The determination of injury under these principles involve assessment over a period of time

C. SCOPE OF INVESTIGATIONS:

5. The product considered in the present investigation is newsprint, other than glazed newsprint, originating in or exported from USA, Canada and Russia. Newsprint having ash content above 8%, commonly known as glazed newsprint, is not included in the scope of the present investigations. Newsprint is an uncoated paper of a kind used for the printing of newspaper, of which not less than 65% by weight of the total fibre content consists of wood fibre obtained by a mechanical or chemi-mechanical process, unsized or very lightly sized, having a surface roughness Parker Print Surt (1 Mpa) on each side exceeding 2.5 micro meter (micron), weighing not less than 40 gsm and not more than 65 gsm. Newsprint is classified under custom code 48.01 of Schedule I of the Customs Tariff Act, 1975.
6. The following arguments have been raised with regard to the scope of investigations:

The anti-dumping investigations being conducted by the Authority are discriminatory in as much as the investigations covers only Canada, USA, and Russia; and Scandinavians and Europeans, whose prices in some cases were even lower, have been excluded. To illustrate, Indian Express (Madurai) Ltd. imported newsprint from Sweden at price of Rs 19635 pmt., which was the lowest price at which newsprint was sourced by them during the entire investigation period. Some other parties have argued that newsprint has been sourced from Italy, Brazil, South Africa, Germany and Korea RP at prices much lower than the prices from the subject countries.

Authority's position:

The Authority notes that dumping occurs when the export price of an exporter is lower than normal value of the goods prevailing in the domestic market of the exporting country or territory. Mere lower prices from a country do not imply dumping. Neither the petitioner has furnished any information with regard to normal value of newsprint in these countries (countries other than Canada, Russia, and USA), nor made a complaint to the

Authority at the time of initiation of the investigations. The Authority is also not under an obligation to suo-motu examine dumping from other countries while deciding on initiation. It was, therefore, not even prime-facie established that imports from other sources were also at dumped prices at the time of initiation. Moreover, Rule 19 of the Rules regarding non-discrimination becomes operational only for imposition of anti-dumping duty "in case the products are found to be dumped from a number of sources" and the Central Govt decides to impose duties on some of these sources (leaving some sources without imposing duties). Since the Authority has not even investigated imports from other sources, it cannot be held that the Authority proceeded on a discriminatory basis.

E. LIKE ARTICLES, STANDING AND DOMESTIC INDUSTRY

7. Under Rule 2(d) "like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such an article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation.
8. The following arguments have been raised with regard to like article.
 - a) In the instant case, the Articles identified for comparison are Imported newsprint versus indigenously produced newsprint and, therefore, the first part of the definition of like article under the Rules applies, according to which the requirements is that the imported newsprint and domestically produced newsprint should be alike "in all respects". Inter-changeability of newsprint is one respect and not all respects. Quality, texture and durability are other essential characteristics which will determine likeness or dissimilarity.
 - b) The policy followed by US and EU is that if price adjustments on account of differences in the product exceeds 20% of the total cost of manufacture then the product will not be considered as a like product. The domestic newsprint differs from the imported in view of the following:
 - Reduction upto 20% in daily printing time in case of imported newsprint,
 - Difference in raw-material used for manufacture,
 - Durability in terms of texture and quality in the imported newsprint,
 - The Indian newsprint producers produce newsprint from agricultural waste, printed newspapers and other sub-standard raw material and not from wood pulp. It is believed that the newsprint produced by the private mills in India do not even conform to the ISI specifications. Use of different raw materials by the foreign producers and domestic producers affect the texture and durability of the produce.
 - c) The quality of newsprint produced by the Indian industry is not comparable with the newsprint imported from the subject countries.
 - d) As regards the grammage of the newsprint, the domestic paper mills always have inconsistency and the grammage is always on higher side of the tolerance allowed by the standards.
 - e) The preliminary findings do not provide any evidence to support that the petition has been made on behalf of the domestic industry. The Canadian High Commission requested the Authority to examine the issue of standing carefully and to ensure that the requirements of Article 5.4 of the Agreement have been met.

Authority's position:

The Authority notes that arguments have also been raised by some consumers that the quality of newsprint produced by some of the domestic producers, such as TNPL and HNL is acceptable. It has not, however, been disputed by any interested party(ies) that the articles produced by the domestic industry were substitutable by the articles imported from the subject countries -- both commercially and technically. The Authority further notes that the basic raw materials used by all the producers in the subject countries is not the same. For instance, newsprint is produced by the Canadian producers also using waste paper. Use of a particular type of raw material over other types has, however, not been considered as a critical factor, either by the producers or by the consumers.

- 9 In order to establish that the newsprint produced by the domestic industry is a like article to the newsprint exported from the subject countries, the Authority took into account such characteristics as physical characteristics (size, chemical composition, raw materials), manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution & marketing, and tariff classification of the goods with regards to the newsprint produced by the other producers. The Authority is required to compare the characteristics of the newsprint produced by the domestic industry, i.e., MPM, HNL, TNPL and Nepa and the characteristics of the newsprint produced and sold by other newsprint producers are irrelevant. The Authority notes that the newsprint produced and sold by the domestic industry has characteristics closely resembling to the newsprint exported from the subject countries, even though some of the factors may not be identical. The Authority, therefore, holds that the criteria prescribed in the definition under Rule 2(d) are adequately satisfied and newsprint produced by the domestic industry is a like article to the newsprint exported from the subject countries.
10. INMA satisfies the conditions laid down with regard to standing to file the petition. The petition has been filed by INMA, which is represented by the newsprint manufacturers in India. There is no opposition to the petition by any newsprint producer, and production of MPM, TNPL, HNL, Nepa constitutes a major proportion of the total domestic production of newsprint in India. MPM, TNPL, HNL, and Nepa have not only individually signed and endorsed the petition filed by INMA, but also furnished such further information as was requested by the Authority and offered themselves for any verification conducted by the Authority.
- 11 The Authority confirms the preliminary findings with regard to the standing of the petitioner to file the petition, status of domestic industry and confirms that newsprint produced by the domestic industry is a like article to the product under consideration i.e., newsprint exported to India, originating in or exported from the subject countries within the meaning of the rules supra.

F. DUMPING

12. Under Section 9A(1)(c), normal value in relation to an article means:
 - (i) the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or
 - (ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-

- (a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or
- (b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

- 13. The arguments raised by the parties opposing the recommendation and examination of the same by the Authority are as under:
 - a) When the Authority has referred to the figures prior to April 96 with regard to import volumes, market share, production and capacity utilisation, there is no reason why the international market prices and fluctuations therein for a period prior to April 96 should not be looked into.

Authority's position:

The Authority notes that dumping margin has been defined under the Rule, which states that the same is the difference between export price and normal value. Dumping margin, therefore, has to be worked out for the investigation period. Annexure-II relating to Injury to the domestic industry states that the Authority shall carry out an objective examination with regard to the volume of the dumped imports, effect thereof on prices in the domestic market for the like article and the consequent impact of these imports on the domestic producers of such products. The Rules provides that the Authority shall consider whether there has been a significant increase in dumped imports or the imports have resulted in a significant price undercutting or price suppression or depression in the Indian market. The Authority is further required to examine all relevant factors and indices having a bearing on the state of the domestic industry, including decline in sales, production, profits, capacity utilisation etc. As already discussed, injury to the domestic industry has to be assessed for the period of injury considered, which is larger than the dumping period.

- b) The dumping margin has to be determined with regard to every exporter and every importer as every transaction of import may or may not be uniform

Authority's position:

Arguments have also been raised that the Authority should not determine the normal value for individual exporter, and should determine only one normal value for one country. The Authority, however, notes that the normal value has been well defined under the law and has to be determined accordingly. Dumping is exporter specific and the Rules require that the Authority determine individual dumping margin for each known exporter. The Authority has, therefore, determined individual dumping margin for each co-operative exporter.

- c) The expectation in the USA was that the demand for newsprint would rise substantially, which did not materialise. The excess production planned by the mills in USA and

Canada could not be sold except in the Asian markets at prices determined by competitive forces.

Authority's position:

The Authority is not required to investigate the reasons for the lower export price. The Authority is required to investigate existence of dumping in accordance with the law. The argument of excess production resulting in lower export price does not alter the position regarding dumping.

- d) The Authority has based its findings, inter-alia, on the prices published in a journal in New York.

Authority's position:

The contention is incorrect and the factual position has been brought out in the preliminary findings as well as these findings. The Authority has determined normal value on the basis of claims made by the exporters and subsequently verified by the Authority.

- e) Domestic industry exported to Thailand in 1995-96 at FOB export price of US \$ 727 which was the prevailing international price. This establishes that irrespective of the domestic price within India, Indian newsprint producers had to export at or around the prevailing international prices. Same is true for imports in India in 1996-97 also.

Authority's position:

The price at which Indian industry exported to Thailand or the prices prevailing in Thailand are irrelevant to decide the existence of dumping.

- f) Mekor submitted that exports from Canada were more than 180,000 MT in 1996, which was 4-5 times of the volumes shipped by Solikamsk (who had shipped 40000 MT). Consequently, the exporter argued that the exporters from Canada defined the level of prices for imported newsprint in the Indian market. The exporter further stated that in view of existing differences in quality of paper produced by the company and the paper produced by the exporters from Canada and USA and the level of services provided, all attempts to increase the prices by the exporter were unsuccessful.

Authority's position:

The Authority notes that the fact of dumping and not the reasons thereof is the purpose of the present investigations.

- g) There was considerable decline in the prices for pulp and paper products, which resulted in the decline in the prices of newsprint.

Authority's position:

As brought out in preliminary findings and as mentioned above, the fact of dumping and not the reasons thereof is the purpose of the present investigations. Decline in the prices of pulp would affect the cost of production and would apply equally to both the markets, i.e., exports to India and sales in the home market.

- h) The anti-dumping duty is ordinarily on prospective basis except in the circumstances mentioned in Section 9A(3). It was neither the case of the petitioners nor the finding of the Authority that the fact and circumstances attracted provisions of Section 9A(3). In the circumstances the Authority could only record a finding as to the existence of dumping on the date when he gave his findings and not as to whether there was any dumping in

the past period. The change of circumstances has to be taken into account and cannot be ignored at the time of arriving at a finding.

Authority's position:

The argument is legally untenable. The Authority is required to give a finding with respect to existence of dumping during the investigation period. As brought out elsewhere in these findings, the factors subsequent to the investigation period are irrelevant to decide the existence of dumping and in case the factors in the post investigation period have materially changed, an interested party(ies) may request review in accordance with the law. The argument of the interested party(ies) is untenable even procedurally, conceptually and methodologically for giving finding of dumping "on the date" of recording the finding.

- i) In the present circumstances, comparable representative price of newsprint, when exported from the said countries or an appropriate third country or the cost of production has to be taken as the normal value. The price at which newsprint has been exported from the subject countries were at around the same price at which such imports have been made from other European countries. The present case is not a case where there are no sales or low volume of sales in the domestic market of the exporting country. It is a case where there is a peculiar market situation, and, therefore, domestic sales do not permit a proper comparison. The whole approach with regard to determination of normal value is erroneous and not in conformity with the Act.

Authority's position:

The argument is legally untenable. The price at which newsprint has been exported from third country(ies) is irrelevant to decide dumping from the subject countries. For dumping, only the normal value and export price of the exporter in the subject country(ies) are relevant. As regards the determination of normal value, it has not been brought out by the concerned interested parties as to why the definition of "normal value" under section 9A should not be accepted and why there is a case of "particular market situation".

- j) Consumption of newsprint in India is not more than 1.2% of world demand and there is no reason for any exporter to dump its material in India.

Authority's position:

Under the anti-dumping provisions, the effect of the volume of trade is to be viewed only in the context of the domestic market (including imports) of the importing country and the reference to consumption of newsprint as compared to the world demand is of no relevance.

- k) Imports from Abitibi were on the basis of (long term) contractual agreement which had definitive linkage with the US market transacted price. There is no question, therefore, of dumping by Abitibi.

Authority's position:

As brought out in the preliminary findings, the argument is irrelevant. Further, the claim that imports from Abitibi were on the basis of contractual agreement is also incorrect as Abitibi had exported to a number of parties, which were not under long term contracts.

- l) Domestic price of newsprint in Russia has never been more than in North America

Authority's position:

The argument is irrelevant to decide the present investigations. Price of newsprint in Russia and the price at which newsprint has been exported from Russia to India are the only relevant factors to decide dumping by Russia and the prices prevailing in North America are irrelevant.

- m) Overseas mill afford to sell at lower prices because of immaculate production planning, marketing, customer support.

Authority's position:

The evidence available with the Authority establish that the profitability of the exporters from Canada and USA declined sharply in the investigation period and some of the exporters in these countries were forced to sell at prices significantly below the cost of production in the Quarter 4, 1996, in both the markets, i.e., exports to India and sales in the home market. The argument of the interested party(ies) is, however, irrelevant to decide the present investigations, the only relevant factors being the normal value and export price.

DETERMINATION OF DUMPING:

14. The methodology adopted for determination of dumping margin and the claims allowed by the Authority with regard to individual exporters are as follows:

I STONE CONSOLIDATED:a) Export price:

- i) The exporter furnished, in response to the questionnaire sent by the Authority, a detailed month-wise statement of quantity of newsprint exported to India, alongwith the C&F price, commission, inland/ocean freight, and inland freight from mill to port. During the spot investigations the exporter furnished a statement of overseas sales for each of the month in the investigation period, indicating therein the grade of newsprint, exporter to whom exported, volume of newsprint shipped, unit price, freight, commission and net selling price.
- ii) While submitting response to the questionnaire through M/s. J. Sagar & Associates, Stone Consolidated had mentioned under Appendix 3A(2) that the amount of overseas freight was *****. Appendix 3A(2) relates to sales price structure for exports to India and requires the exporter to give the list price alongwith adjustments which they may like to claim to arrive at the ex-factory export price.
- iii) It is pertinent to note that the questionnaire sent by the Authority clearly indicates that the adjustments claimed from the export price should be based on the actual expenditure incurred by the exporter. Since no remark was adduced to the element of overseas freight under appendix 3A(2), it was presumed by the Authority that this amount is the actual amount incurred by the exporter on overseas freight. It was observed that the element of overseas freight mentioned in appendix 3A(2) did not tally with the statement of "customers by grade newsprint exported" by Stone Consolidated, furnished by the company at the time of verification. Nor was this disclosed in the verification report dated 29.10.97 furnished by the exporter subsequent to the visit to the investigating team. However, subsequent to the disclosure statement, J. Sagar & Associates furnished an explanation that the customers by grade exports statement submitted by Stone Consolidated indicated only the notional ocean freight. Notwithstanding the incorrect claim made by the exporter, the representatives of J. Sagar & Associates explained that the claim of freight is on account of lower ocean freight which Universal was "able to obtain" on some exports done through Universal. The contention of the exporter cannot be accepted, as the exporter did not furnish any evidence to establish the linkage of

supplies made to Universal for ultimate sale to the Indian importers. The photocopies of the four Bills of Lading show Universal as the shipper but crucial information regarding the weight of the consignment was not indicated either in the response or to the verification team. The exporter did not submit any evidence whatsoever to establish that the difference of about ***** was actually credited in the books of accounts of Stone Consolidated. No evidence is also shown to the verification team to establish their contention with regard to a saving of ***** on account of ocean freight element. The contention of J. Sagar & Associates in their response dated 13.11.97 that the issue of lower freight which Universal was able to obtain, was explained to the verification team at Montreal is misleading. On the contrary, the verification team had clearly indicated to the exporter as well as to the representatives of J. Sagar & Associates, Shri V. Laxminkumaran and Shri R. Parthasarthy, assisting the verification team that in order to claim the benefit of lower freight as an adjustment in the export price, it would be incumbent upon them to establish the saving in the books of accounts of Stone Consolidated. The accounting practice followed by the exporter is such that even additional discounts paid by him to the consumers (which are paid at the end of the period, after establishing the volume lifted by the consumer during the relevant period) are adjusted in the statements. Under these circumstances, the claim of the exporter that it accounted for the "notional" expenditure in the statement (and did not rectify the same, after the payment of ocean freight) is not appreciated. Since this evidence has not been submitted at any point until the point of verification or even thereafter, the Authority is constrained to reject this claim of the exporter as a mere statement not substantiated with an evidence.

- iv) Since the statement furnished by the exporter during the spot investigations represents the records maintained by the exporter with regard to its operations, the export price has been considered on the basis of this statement of overseas sales. Further, since the statement gives the mill net prices at ex-works, after adjusting for commission, freight and other charges, the same are proposed to be considered as the export price
- v) Commission: The exporter has, in the questionnaire response, argued that it pays commission to Universal, and all exports whether they are made directly or through Universal attract commission. For determination of normal value, the exporter claimed an adjustment on account of SGA from the selling prices in the home market. During spot investigations, it was, however, found that the claim of the exporter with regard to SGA is not based on the difference in the expenses incurred on these accounts in the two markets, i.e., home market and exports to India. The exporter, however, after the spot investigations, argued that the export price need not be adjusted for the commission paid to Universal in order to do a fair comparison between the normal value and the export price. On the basis of the facts on record, it is clear that Stone Consolidated had paid a commission on their exports to India, and, therefore, the export price is required to be arrived at after adjusting the element of commission.
- vi) The authority recognises that the exporter is entitled to claim expenses which are incurred solely on account of sales made in the domestic market as an adjustment to arrive at the normal value. The argument that the commission should not be deducted to arrive at the export price in view of the fact that no SGA expenses have been claimed as adjustments in the normal value is not acceptable, as the determination of export price and normal value is required to be done, for all factors affecting price comparability, independent of each other after making admissible adjustments in each one of them based on the evidence .

- vii) Credit Sales: Since the sales in the home market involves lower credit terms compared to exports to India, the Authority has made an adjustment on account of higher credit in case of exports on the basis of differential credit period.
- viii) The export price, as determined above has been considered as ex-works export price.
- b.) Normal value:
- i) The exporter furnished a statement of customer-wise sales made in the domestic market, alongwith a detailed invoice/transaction wise and customer wise sales statement, giving therein the grade of newsprint sold, order number, invoice no. and date, gross volume shipped, unit price, and amounts towards gross sales value, freight, discount, commission, other expenses and receivable amount. A detailed scrutiny of the statement for the month of July and August, 1996 revealed that the discount amounts claimed by the exporter in the questionnaire response did not tally with the discount amounts claimed by the exporter in the detailed sales statement furnished during the course of the spot investigations. The exporter revised its statement of Sale Price Structure for Domestic Sales, after the spot investigations, and clarified that the amounts of discount shown in the original questionnaire response included off-invoice discounts also. The exporter further clarified that the off-invoice discounts were offered to the large customers in Canada by credit notes later (i.e., after completing sale of goods) and availability of discounts was known (to the customer) at the time of purchase.
- ii) Volume discount: The exporter claimed that its exports to India were primarily to two customers, M/s. Bennett Coleman and a consortium of consumers in South India. Volume of sales made to these customers being very large, the exporter has claimed an adjustment on this account. The claim on this account has been made by the exporter after the preliminary findings. The exporter has, however, after the spot investigations and in response to the disclosure statement argued that the Authority may alternatively determine normal value based on the selling prices to the large customers only.
- iii) Scrutiny of the claim made by the exporter revealed that the exporter has identified its large and small customers in the home market. The exporter had one large and eight small customers in the home market in the investigation period. The exporter has worked out average selling price to these small customers and the same has been used to work out the difference in its selling price to the small and large customers. Considering the difference in the selling prices to the small and large customers, the exporter has claimed an adjustment of ***** towards the same.
- iv) The claim of the exporter with regard to volume discounts is not tenable as the Authority is required to determine normal value and export price on comparable levels. The Authority, however, recognises that the selling price to the large customers should be considered for determination of normal value in view of association of large export volumes. Though the exporter is inconsistent with regard to the methodology to be adopted for determination of selling prices in the home market and has argued varied claims, the Authority considers it appropriate to determine the selling prices on the basis of the prices to the large customers. The Authority has, therefore, determined the selling price on the basis of the selling prices to the large customers in the home market for each of the month in the investigation period and has ignored the sales made to the small customers, on the basis of the claims made by the exporter. Discounts have been allowed on the basis of actual discounts allowed at the time of invoicing. Additional discounts given by the exporter after sale, by way of credit notes, have not been allowed, as no evidence has been shown to indicate that either the incidence or the quantum were determinable at the time of sale.

- v) Freight: The exporter has claimed freight on the basis of the freight paid by the exporter on each sale made, details of which are given in the transaction wise sales statement. The freight claimed has been allowed.
- vi) Equalised freight: The exporter has claimed an adjustment on account of equalised freight, which represents expenses incurred by the exporter on account of warehousing of newsprint and freight paid on shipments from mill to warehouses. No evidence has been furnished by the exporter that the customers in Canada have been shipped from the warehouses maintained by the exporter, whereas there is sufficient evidence available to show that the customers in US have been shipped from these warehouses. Adjustment on account of storage cost (warehousing) cannot be allowed as the same is neither attributable to product costs, accounting for difference in prices, nor are they related to any function/activity which is carried exclusively in respect of sales in either of the two markets. The exporter has, further, not separated the expenses incurred (including freight) on sales made in Canada on this account. The adjustment on account of equalised freight has not, therefore, been allowed.
- vii) Selling, General and Administration Expenses: It was found during the spot investigations that the claim of the exporter on this account is based on SGA expenses incurred by the exporter on services which are either common to both the activities (exports to India and sales in the home market) or are not directly related to either of them. The exporter has not been able to substantiate that the SGA expenses, as claimed, were incurred exclusively on sales made in the home market. Since the exporter has not furnished details of expenses incurred exclusively on this account, even after the spot investigations, no adjustment on this account is feasible.
- viii) Continuous/batch production: The exporter had claimed an adjustment of ***** on account of batch production for sales in the home market as against continuous production in case of exports to India. The exporter has not offered any verification for the same, nor has exporter pressed for adjustment on this account after the preliminary findings (the Authority had disallowed this adjustment in the preliminary findings). In view of the above, the Authority has not considered any adjustment on this account in the final findings also.
- ix) The normal value, as determined above has been considered as ex-works normal value.
- II. ABITIBI-PRICE, CANADA:
- a.) Export price:
- i) The exporter furnished a detailed transaction-wise statement of exports made to India, "Off-shore Newsprint Net Sales", giving therein details of, inter-alia, volume of newsprint exported, unit price, total sales value, discount, and freight (inland and overseas). Each of these reports gave region-wise the export of newsprint from all the mills in Canada to different countries in the world. The all-mill report was supported by statements containing the sale of newsprint overseas by each mill. Exports to India were made from the Chandler and Grand Falls. Export price has been determined on the basis of this statement. Adjustments on account of commission and freight are also allowed on the basis of the actual expenses as shown in the statement of off-shore newsprint net sales.
- ii) Credit Sales: Since the sales in the home market involves lower credit terms compared to exports to India, the Authority has made an adjustment on account of higher credit in case of exports on the basis of differential credit period and interest rate.
- iii) The export price, as determined above has been considered as ex-works export price.

b.) Normal value:

- i) The selling price in the home market has been claimed by the exporter on the basis of a detailed statement of invoice wise listing, giving therein the amounts towards gross sales value, discounts, freight and the net sales value. The selling price has been determined after deducting discounts allowed at the time of sale and actual freight incurred for all the sales made in the home market.
- ii) Additional discounts: The exporter has given additional discounts by way of credit notes, after the sale of the goods, on completing certain conditions towards volume of newsprint purchased by the customers. Since the additional amounts were not known at the time of sale, either in terms of incidence or quantum, the Authority has not allowed claim of additional discounts.
- iii) Volume discounts: The exporter has contended that the exports to India were made in large volumes (15000 - 20000 MT). In case of sales in the home market, one large customer lifted 30000 MT as against small customers who averaged about 1000 MT. The exporter has, therefore, claimed adjustment of ***** on account of difference in the selling prices to small and large customers in the home market.
- iv) The Authority notes that the company was selling in the home market in substantial quantities and the same were at profit for the major period in the investigation period. The profitability of the company, however, declined in every quarter in 1996 to such an extent that the company incurred financial losses in quarter 4, 1996 from a situation of substantial profits in the quarter 1, 1996.
- v) The Authority would have determined the normal value in case of Abitibi also on the same basis as has been done in case of Stone Consolidated in so far as the issue of large customer is concerned. However, Abitibi has neither claimed determination on these lines, even after the disclosure (even though the response in case of Stone Consolidated and Abitibi has been filed by the same company, i.e., Abitibi Consolidated Inc.), nor the company disclosed the prices to the large customers in each of the month in the investigation period. Complete details of the month-wise sales made to the large customers have also not been furnished. The Authority is precluded from determining the selling prices on the basis of the sales made to the large customers. The Authority has, therefore, determined selling prices in the home market on the basis of the total sales made in the home market. The claim of the exporter with regard to the volume discounts has not been allowed as the selling price considered for determination of normal value is based on weighted average of the selling price to large as well as small customer, and therefore, is already adjusted towards the lower selling price to the large customers. The Authority notes that even the exporter has done calculation of dumping margin "without taking into account the volume discount".
- vi) Deduction on account of SG&A expenses: Abitibi has also claimed adjustment on account of selling, general and administration expenses on the same lines and reasoning as has been done by Stone Consolidated. The exporter has not been able to offer substantiate that the SGA expenses, as claimed, were incurred exclusively on sales made in the home market. Since the exporter has not furnished details of expenses incurred exclusively on this account in the two markets, even after the spot investigations, no adjustment on this account is feasible.
- vii) The normal value, as determined above has been considered as ex-works normal value.

III. Abitibi-Price, USA:

Abitibi indicated at the time of spot investigations in Canada that further information in respect of US mills of the company were not forthcoming and the company did not seem willing to co-operate further in the investigations. The Authority has, therefore, proceeded with the determination of normal value and export price on the same lines as has been done in the preliminary findings.

IV. Avenor Maritimes: In case of Avenor Maritimes, the exports to India have been made by Avenor Inc., whereas the newsprint was produced by Avenor Maritimes, which is a subsidiary of the former. Avenor Inc. has a number of mills producing newsprint. The company, however, claimed that Avenor Inc. and Avenor Maritimes are separate legal entities and activities of Avenor Inc. could not be linked to Avenor Maritimes.a.) Export price:

i) Avenor Maritimes furnished a detailed transaction-wise statement of newsprint shipped to India. It was explained by the exporter that the statement included shipment of standard newsprint including trim newsprint.

ii) An analysis of sales of trim and good newsprint to India reveals as under:

- Analysis of date-wise exports made to India reveals that the selling prices of trim and good newsprint are different at nearly same point of time. For instance, trim selling prices in the month of April 1996 were ***** as against ***** for good newsprint. However, the difference was ***** in the month of July, and ***** in the month of Sept. It is, therefore, concluded that though the selling price of trim and good newsprint differs, the difference was not uniform.
- An analysis of date wise exports made to India reveals that the selling prices of good newsprint declined sharply from ***** (Apr., '96) to ***** (Sept., '96). The selling prices in case of trim declined from ***** (Apr. '96) to ***** (Sept., '96).
- An analysis of customer-wise and date-wise exports made to India reveals that there is no correlation suggesting that a consumer in India has been sold good newsprint at a lower price because of association of sale of trim newsprint. The claim of the party is that specificity of the Indian market allowed the exporter to sell trim newsprint to its regular customers and derive substantial benefits. The exporter has sold good newsprint to some customer (say customer 1) and sold trim newsprint to another customer (say customer 2). The claim of the exporter is, therefore, that it has sold at lower prices to customer 1 because it has sold trim newsprint to customer 2 (and thus made up the lower realisation from customer 1).

iii) The exporter was requested to furnish the details of total production of newsprint bifurcated into trim and good. The exporter expressed its inability to furnish the same, pleading non-availability of such a system permitting separate recording and reporting. The exporter was, therefore, suggested to alternately furnish the details of total sales of newsprint bifurcated into good and trim. The exporter has furnished the statement, which reveals that the trim sales represents 3.4% of the total sale of the exporter. The sale of trim newsprint to India during the investigation period constituted 20.9% of the total sales of the exporter.

iv) In view of the above, trim newsprint exported to India has been identified in the transaction wise import statement and disregarded for the purpose of export price determination.

- v) Commission: The exporter has paid a commission in case of exports to India, which has been deducted from the export price.
- vi) Inland Freight: The exporter has sometimes incurred inland freight on exports made to India. Though the plant of the exporter is located near sea port, it has been explained by the exporter that sometimes it has to incur inland freight for loading newsprint on the ship.
- vii) Ocean Freight: The exporter has charged ocean freight on the basis of actual expenditure incurred by it and therefore, the same has been allowed.

b) Normal value:

- i) Avenor Inc. claimed that the sales made by it in the home market cannot be considered for determination of normal value for Avenor Maritimes, as the two are separate legal entities. Avenor Inc. has, therefore, not furnished details about sales made by Avenor Inc., even though the Authority suggested the same at the time of verification.
- ii) Sales Volumes: Volumes sold by Avenor Maritimes in various markets are as under:

Market	Volume	Percentage of	
		Total Sales	Exports to India
Home Market	194	0.15	2.25
Exports to India	8546	6.88	---
Exports to Other Countries	115490	92.97	1351

- iii) Avenor Inc. has contended that the sales of Avenor Maritimes in the home market cannot be considered for determination of normal value for the following two reasons:
- The sales are in negligible quantities (1.8% of exports to India) and, therefore, cannot form basis for determination of normal value in accordance with Article 2.2 of GATT.
 - The exporter has put up the plant at New Brunswick (in the name of Avenor Maritimes) only for the international market and does not sell in the Canadian market. Even the small volumes sold in the Canadian market represents new products testing.
- iv) It is found that Avenor Inc. has exported newsprint to India produced in Avenor Maritimes (which is a subsidiary company of Avenor). Avenor has a number of other plants producing newsprint, from which it has sold newsprint in its home market. Normal value has been defined under section 9A(1)(c)(i) to mean the comparable price for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory. Since the exporter has other plants in Canada, it could have claimed normal value based on the domestic prices for the sales made from other plants. The exporter has, however, not proposed determination of normal value based on plants of Avenor Inc. in Canada. Even the sales information in respect of other plants of Avenor Inc. has not been furnished by the exporter in spite of specific request by the Authority.
- v) From the details of exports made to third countries furnished by Avenor Inc., it is found that Avenor Maritimes has exported to a number of countries. The exporter had not furnished country-wise details of exports made by it in the response filed by it after the preliminary findings. During the spot investigations, the investigating team found that separate details with regard to volumes, prices and cost differentials for the exports made to various countries were available with the exporter. Avenor Inc. was, therefore,

requested to furnish details of exports made by Avenor Maritimes to various countries, including the volumes exported, the selling price and expenses incurred by Avenor Maritimes exclusively on exports made to various countries. Avenor Inc. has furnished the statement, month-wise, for the investigation period, scrutiny of which reveals that Avenor Maritimes has exported to the following countries:

Country
Bangladesh
Bermuda
Chile
Colombia
France
Hong Kong
India
Israel
Italy
Jamaica
Japan
Netherlands
Portugal
Puerto Rico
Singapore
Taiwan ROC
Thailand
UK
Total

- vi) Avenor Inc. has argued that export price of Avenor Maritimes to other countries cannot be relied upon for determination of normal value as Article 2.2 of WTO states that the use of third country prices requires a "comparison with a comparable price of the like product when exported to an appropriate third country provided that this price is representative". The exporter has, in view of the foregoing and para 9A(c)(ii)a of the Indian Rules, argued that the export price to third country cannot be relied upon for determination of normal value. The exporter has advanced the following reasons in support of its contention
- Grade/type: The exporter has contended that the countries, such as Japan, UK, Netherlands, Portugal, Singapore cannot be considered for determination of normal value, as the exporter has exported 45 gsm newsprint to these countries (exports to India are of 48.8 gsm newsprint).
 - Bermuda, Jamaica and Puerto Rico: The exporter has contended that export price to these countries cannot be considered for the following reasons:
 - ◆ There is no local production (in these countries);
 - ◆ The volume of sales involved is low;
 - ◆ The port of Bermuda has limited unloading facilities, resulting in higher ocean freight;
 - ◆ Avenor supplies only to one company in these countries making the price to these countries unrepresentative;

- ♦ In Puerto Rico, the market traditionally and historically pays a premium over the US market. Further, 54% of the exporter's shipments are destined to a customer where Avenor is the sole supplier. Traditionally, publishers using a sole supplier will pay a premium that in exchange will guarantee deliveries even when newsprint is in shortage.
 - ♦ The customer in Colombia has to pay premium in view of political risks in the country.
- Chile: Production of newsprint in Chile is four times than the consumption. The publishers import newsprint to protect themselves from being at the mercy of local producers, in exchange of which they have to pay premium over other markets. Sales to Chile is expensive and requires quarterly presence of technical and marketing staff. Further, Avenor serves only one customer in Chile, making the prices unrepresentative.
 - Bangladesh, Hong Kong, Taiwan and Thailand. Although the market conditions in Bangladesh, Hong Kong, Taiwan and Thailand are similar to the Indian market, shipments to these countries are made solely by containers, which represents a premium. Further, cumulative shipments from these countries were 1.3 % of the total sales of Avenor Maritimes.
- vii) Avenor Inc. has, in view of the foregoing, argued that its sales price to any other country cannot be considered as comparable and representative. Avenor Inc. has therefore, worked out normal value based on cost of production of Avenor Maritimes.
- viii) The claim of the exporter that its normal value cannot be determined on the basis of export price to third countries deserves to be rejected on the following grounds:
- Section 9A(1)(ii)(a) provides for determination of normal value on the basis of comparable representative price of like article when exported from the exporting country to an appropriate third country. Definition of like article covers, in its scope, not only identical goods, but also, in its absence, goods having characteristics closely resembling the product under consideration. Resorting to the basis of cost of production, pleading non availability of appropriate third country to whom "like article" has been exported, is not acceptable.
 - Annexure I to the Rules, dealing with the principles governing the determination of normal value, export price and dumping margin provides for due allowance for the differences which affect the price comparability, including differences in conditions and terms of sales, level of trade and any other differences which are demonstrated to affect price comparability.
 - It is recognised that no two markets are the same. In fact, no two customers may be the same and sales price to two customers even in the same market may vary in view of a number of factors. Avenor could have claimed, in view of its contentions of differences in terms and conditions of sales in exports to India and exports to other countries, price adjustment which account for the differences in the conditions and terms of sale. Avenor has, however, not claimed any such price adjustment and has instead claimed that the export price to any other country is not representative.
- ix) The argument of the exporter that the normal value cannot be determined on the basis of export price to third countries is not acceptable and deserves to be rejected. An analysis of the cost of production for exports made to India and exports made to third countries furnished by the company reveals as follows:

- a) The claim of the exporter is that its export price to India was higher than its cost of production and, therefore, there is no dumping;
- b) Avenor has claimed different raw materials cost for the newsprint sold to India and the newsprint exported to other countries. The exporter has claimed a higher raw materials cost in case of exports to other countries, which represents, according to Avenor, the difference in the material exported to India and Japan;
- c) The cost of production statement furnished by the exporter does not include interest costs, commission to Avenor Inc. paid by Avenor Maritimes and reasonable profit, which Avenor Maritimes is supposed to have made on the exports made to India;
- d) The claim of the exporter that it has exported to India above costs is after considering the trim sales made to India, cost of which has been considered as comprising of raw material cost only. Avenor has argued that trim is usually recycled within the paper machine as it is otherwise difficult to sell. In case of its exports to India, the exporter has argued that it has sold trim in substantial volumes. The exporter has argued that the cost of trim comprises of only variable cost in newsprint production, i.e., costs of fibres, pulp, power, chemicals and other misc. costs. The exporter has claimed that there are no costs involved with regard to the following in so far as the trim production is concerned:
 - Semi-variable costs - such as labour, maintenance, power and others;
 - Fixed costs - such as manufacturing administration, selling, administration, depreciation and others.

It is found that the exporter considers trim production as saleable production. In the cost sheet submitted by the exporter, the exporter has determined cost of production on the basis of total saleable production (i.e., including trim production). It can therefore be concluded that whereas the cost of production determined by the exporter is based on the total saleable production (including trim production), the exporter has argued that the cost of trim product comprises of only variable costs.

The break up of the cost of production of newsprint furnished by the exporter is as follows.

	Exports to India		Exports to third
	Good	Trim	Countries
	Newsprint		
Sales (MT)	****	****	****
Variable costs	****	****	****
Semi-variable costs	****	nil	****
Fixed costs	****	nil	****
Overheads costs	****	nil	****
Total costs	****	****	****
Less: Credit for Trim			
sold to India *	****		
Net cost of production	****		

* Based on total trim sale to India.

- x) The Authority observes that the exporter has claimed credit for trim sales on the basis of trim exports made to India during the investigation period. Since the exporter has exported trim production and good production to different consumers in India and/or at different point of time, the exporter has sought to get the benefit of significantly higher price realisation from sale of trim newsprint while determining profitability of good newsprint exported to India.
- xi) The Authority notes that normal value has to be determined as provided under Section 9A(1)c, as detailed above. The said section provides that the normal value shall be the comparable price for the like article when meant for consumption in the exporting country. In case sales of the exporter in the domestic market are not sufficient to determine the normal value, the same may be determined on the basis of selling prices (of other producers) in the domestic market of the exporter. In the instant case, where Avenor Inc. has several mills in Canada selling newsprint in the domestic market, normal value could have been claimed on the basis of selling prices of these mills. Further, the exporter could have claimed normal value based on the export price to third countries, after making adjustments towards the differences in the terms and conditions of sales. Even this has not been claimed by the exporter. Under the circumstances, the Authority considers it appropriate to determine normal value for Avenor Maritimes on the basis of monthly average selling price of other co-operative exporters from Canada, i.e. Stone Consolidated and Abitibi. The normal value in case of Avenor Maritimes has been, accordingly determined on the basis of normal values of Stone Consolidated and Abitibi.

V. EXPORTERS FROM RUSSIA:

- a) None of the exporters from Russia furnished any factual information with regard to present investigations before the preliminary findings. Balakhana, Kondoponga and Solikams, however, furnished some information after the preliminary findings. The methodology adopted for determination of dumping in respect of these exporters is discussed hereinbelow:
- b) The Authority, immediately upon initiation, requested the exporter to furnish information in the form and manner prescribed. The Authority requested to furnish, Inter-alia, the following information in particular:
- A certificate that the information furnished was true, complete and correct,
 - Willingness of the exporter to offer itself to any verification that the Authority may carry out at their premises;
 - General information about the company, including details about the principal shareholders, etc.;
 - Details of the plants/factories of the exporter;
 - List of incentives given on exports or domestic sales in the form of concessions, exemptions, subsidised inputs, utilities, etc.;
 - Transaction wise details of exports made to India as per the prescribed proforma;
 - Statement with regard to sale of newsprint by the company for three years including investigation period (Proforma 2A);
 - Statement with regard to sale of newsprint by the company month-wise for the investigation period (Proforma 2B);
 - Statement of newsprint exported to India, classified according to the type of the customer i.e. wholesaler/retailers/others(Proforma 2C);
 - Statement of domestic sales, classified according to the type of the customer, i.e., wholesaler/retailers/others(Proforma 2D);
 - Statement of exports to countries other than India, classified according to the type of the customer, i.e. wholesaler/retailers/others(Proforma 2E);

- Statement of sales price structure for exports to India (Proforma 3A), giving therein the list price, price adjustments and net ex-works price;
 - Statement of sales price structure for domestic sales (Proforma 3B), giving therein the list price, price adjustment and net ex-works price;
 - Statement of sales price structure for exports to countries other than India (Proforma 3C), giving therein the list price, price adjustments and net ex-works price;
 - Statement showing licensed capacity, installed capacity, production and sales (Proforma 4A);
 - Statement showing element-wise cost of production for exports made to India, sales made in the home market and exports made to countries other than India (Proforma 4B, C,D);
 - Annual accounts and financial statement for the past three years, including the investigation period
- c) The claims made by Solikams, Balakhana and Kondoponga have been discussed hereinbelow. The methodology adopted by the Authority with regard to determination has also been discussed hereunder.
- VI. BALAKHANA:
- i) Balakhana has argued the following:
- a) The exporter has fully co-operated with the Authority and furnished all information requested by the Authority;
- b) The exporter was willing to offer itself for verification;
- c) The Authority gave a very short time for spot investigations;
- d) The exporter offered a detailed verification, including the manufacturing process, calculation of cost of production for the investigation period as well as for the post and pre-investigation period;
- e) Balance Sheet and Statement of Income and Operations alongwith their schedule were shown to the investigating team, though the copy of the same could not be given for want of Board Approval (which could not be obtained in view of non-availability of the competent authority). The same were, however, submitted after the spot investigations by the investigating team;
- f) The normal value should be calculated based on the selling prices in the home market. The selling prices in the home market were well above the average cost of production

In view of the above and the disclosure statement made by the Authority, Balakhana argued that full co-operation has been extended by the exporter and full verification offered to the investigating team.

Authority's position:

- ii) The above arguments of the exporter are factually incorrect, more so in view of the following:
- a) Balakhana furnished, inter-alia, the following information:
- Statement of sales made in the home market and exports to India during the investigation period,
 - Quantities exported to third countries during the investigation period;
 - Calculation of newsprint cost, month-wise for the investigation period;

- Comparison of average price, ex-mill for sales in the domestic market and exports to India;
 - Details of vessel-wise newsprint exported to India, giving therein the details of vessel, bill of lading date, quantity booked and quantity received;
- b) The Authority, immediately upon initiation, requested the exporter to furnish information in the form and manner prescribed. The exporter was informed of the intentions of the Authority to verify any information deemed necessary. The obligation to furnish full and complete information rests with the exporter. Not only that the exporter did not file complete information, but also the details were not shown to the investigating team, as is evident from the above.
- c) The exporter was requested to furnish supporting information with regard to cost of production, such as raw material consumption norms and reconciliation of the cost statements with the financial statements. These were also not furnished
- d) The investigating team discovered during the course of the verification that the exporter has three paper machines, PM 5, 6, and 8 and the cost of production claimed by the company was for its PM 8 machine only. This fact was not brought out in the response to the questionnaire. The exporter was requested to make available cost sheets for the other two paper machines, which were also not furnished to the investigating team or to the Authority. It was merely clarified that PM 5 and PM 6 are used only after PM 8 is operating at full capacity (and the company needs more production)
- e) The investigating team desired details of production of the company for the past three years, including the investigation period. No details of production were furnished to the investigating team, even though the details of despatches, that too for the investigation period only, were made available. The company claimed that there were no changes in inventory and the production was equal to the sales/ despatches. The company furnished its production during 1996 first time in response to the disclosure statement and the same were neither furnished with the response not provided at the time of verification. It is, however, found that the company has claimed a total production of *****, which is significantly higher than the capacity of PM 8 machine (the capacity of PM 8 has been claimed at *****. It is thus evident that the company produced in significant volumes from the remaining two paper machines, costs of which have not been disclosed. This becomes all the more important in view of the fact that the financial accounts are maintained by the company on consolidated basis for all the three machines and no separate financial records are maintained by the company for individual machines.
- f) The information furnished by the company did not enable the investigating team to verify detailed element-wise costs. It was not clear whether the cost of production included elements of costs such as depreciation on fixed assets, interest, etc. In fact the understanding given to the investigating team was that generally there is no provision for mandatory audit in Russia, nor was it mandatory to provide for depreciation on fixed assets. It is, however, found from the annual accounts for 1996 filed by the exporter after the spot investigations that both the Balance Sheet and Statement of Income and Expenditure are after considering depreciation on fixed assets
- g) Some of the information, such as reconciliation of production, sales and stocks has not been filed by the exporter. The exporter has determined cost of production on the basis of its production and has apparently assumed that sales were equal to the production. Scrutiny of the Statement of Income and Expenditure reveals that the finished goods inventory increased significantly as on 31.12.1996 as compared to 1.1.1996. This apparently implies that the sales volumes were significantly lower than the production

(which would result in higher cost of production than the amounts claimed by the exporter). Similarly, the details of "Other Income (Expenses)" furnished by the exporter reveal that there was significant foreign currency transaction gains, the interest expenses are possibly net of interest income (which could be from non-operational sources). The Long Term Debt, less Current Portion as on 31.12.1996 were ***** cost of which comes to well above US \$ ***** , whereas the company has charged an expenditure of US \$ ***** in its financial statement. It is not known to the Authority whether the company has access to interest free loans or the interest expenses shown in the financial statement are net of any substantial interest income from some sources. None of these details have been furnished by the exporter, which have a critical bearing on the cost of production.

- h) The claim of the exporter that the information to the extent available/ possible was furnished to the investigating team is also not acceptable. The information filed by an interested party(ies) is verified during the course of the spot investigations. The investigating team did not request any information which could be termed as a new requirement. The team merely requested the information which has been prescribed in the questionnaire. Even this request by the investigating team was made as a part of yet another opportunity by the Authority to those exporters who are willing to co-operate with the Authority, who furnished certain minimum information with regard to normal value and export price. There is no obligation on the part of the Authority to request such information at the time of verification.
- i) The claim of the exporter that total average cost of production (derived from the unit cost of production and total production quantities) plus the net profit for the period is more or less equal to total sales revenue earned by the mill is far from Generally Accepted Accounting Principles. In making the claim, the exporter has overlooked the underlined principles of "production and the expenses for the production", for working out cost of production. The apparent fact that there was substantial stock increase in the period (resulting in significantly lower sales volumes compared to production) and the company catered to a number of different markets have been completely overlooked by the exporter
- j) The Authority notes that the exporter filed the details with regard to production during 1996 in response to the disclosure statement, and the same were not filed either in response to the questionnaire or at the time of verification.
- k) With regard to the sales made in the home market, the exporter was requested to furnish details evidencing total sales in the home market. The exporter has not furnished any statement showing details of all sales transaction in the home market, and merely made available a large number of invoices (which were claimed to contain all invoices relating to the sales in the home market). The Authority notes that the exporter has till now not furnished any such details which establishes details of all sales transactions in the home market

VII KONDOPONGA.

- i) Kondoponga has argued the following:
 - a) The entire spot investigations was conducted without sufficient time. The investigating team did not have sufficient time to visit the mill;
 - b) The company furnished whatever information was requested by the investigating team, including audited Balance Sheet and Profit & Loss Account, which shows gross earnings

of ***** It is not clear what information was not filed by the exporter and what information was found incomplete.

- c) With regard to the observation of the Authority that the details of sales made in the home market are on some date, it is clarified that the mill change its prices periodically (and till then the prices remain constant for all purchasers). The company submitted copies of the invoices drawn on each occasion when the price was changed during the investigation period.

Authority's position:

- ii) The above arguments of the exporter are factually incorrect, more so in view of the following:

- a) Kondoponga furnished, inter-alia, the following information

- Details of newsprint exported to India, newsprint sold in the home market, giving therein the selling price;
- Details of cost of production;
- Willingness to offer itself to verification.

- b) The Authority, immediately upon initiation, requested the exporter to furnish information in the form and manner prescribed. The exporter was informed of the intentions of the Authority to verify any information deemed necessary. The obligation to furnish full and complete information rests with the exporter. Not only that the exporter did not file complete information, but also the details were not shown to the investigating team, as is evident from the above.

- c) As observed in case of Balakhana, the request for information was made immediately after the initiation of the investigations, and the claim of the exporter that it has filed complete information or the Authority did not allow sufficient time for filing information or the information was shown to the investigating team are without merit. The Authority finds that the exporter has not furnished its audited Balance Sheet and Profit & Loss Account even after the spot investigations. Further, the claim of the exporter that the annual accounts shown to the investigating team were audited is contradictory to the claim made by Balakhana that there is no provision for statutory audit in Russia. With regard to changes in prices periodically in the home market, the Authority observes that the same is without any supporting evidence. The obligation of the exporter is not to furnish the information in the format suitable to the company, but to furnish the same in the form and manner required by the Authority. The Authority required details of all the sales made in the home market and the average price for sales made in the home market on the basis of all the sales made in the home market. While the claim of the exporter with regard to uniform pricing for a certain period is rejected for want of supporting evidence, the claim made with regard to the selling prices is rejected in view of improper and inconsistent determination of selling prices made by the exporter

VIII. SOLIKAMS:

- i) Solikams has argued the following:

- a) The entire spot investigations was conducted without sufficient time. The investigating team did not have sufficient time to visit the mill;
- b) The company furnished whatever information was requested by the investigating team, including Balance Sheet and Profit & Loss Account, duly certified by a chartered/independent accountant under the Russian Laws which shows huge profit

during 1996. It is not clear what information was not filed by the exporter and what information was incomplete.

ii) Authority's position:

a) Solikams furnished, inter-alia, the following information:

- Details of newsprint exported to India, newsprint sold in the home market, giving therein the selling price;
- Details of cost of production;
- Willingness to offer itself to verification.

b) As observed in case of Balakhana, the request for information was made immediately after the initiation of the investigations, and the claim of the exporter that it has filed complete information or the Authority did not allow sufficient time for filing information or the information was shown to the investigating team are without merit. The Authority finds that the exporter has not furnished any Balance Sheet and Profit & Loss Account even after the spot investigations. Further, the claim of the exporter that the annual accounts shown were certified by a chartered/independent accountant under the Russian Laws is contradictory to the claim made by Balakhana that there is no provision for statutory audit in Russia and claim made by Kondoponga that the financial statements are audited. The Authority has been prevented from ascertaining factual position till date. The Authority further finds that the exporter has furnished a statement, showing its income and expenditure for 1996. No details and supporting statements with this statement whatsoever have been filed by the company.

c) As regards the time allowed, it need to be mentioned that anti-dumping investigations are to be completed within a strict time frame. It is also important to note that it were the exporters from Russia who submitted their response after almost 6 months whereas the statutory time limit is only 40 days. Even though the responses were not received within 40 days, the Authority has considered the information supplied by them to arrive at a fair decision.

15. METHODOLOGY ADOPTED BY THE AUTHORITY WITH REGARD TO SOLIKAMS, BALAKHANA AND KONDOPONGA

a.) As brought out in detail in the foregoing paragraphs, the information furnished by Solikams, Balakhana and Kondoponga is insufficient to determine normal value of these exporters on any of the basis provided in the law. The cost of production details furnished by these exporters is also insufficient to determine normal value, as detailed in the foregoing paragraphs. In view of the above, the Authority has determined normal value based on fair cost of production in case of Balakhana. The cost of production has been reworked out on the basis of the information furnished by Balakhana, after considering fair interest cost of debts shown by the company in the statements furnished. Other expenses shown by the company in the statement furnished has also been included for determination of fair cost of production. Fair return has been allowed on the cost of production to work out normal value. The Authority has determined export price on the basis of claims made by the exporter, which were also verified by the Authority. Since the exporter furnished ex-works export price, the same has been relied upon.

b.) In case of Solikams and Kondoponga, since the information furnished by the exporters is insufficient to determine even fair cost of production, the Authority is prevented from determining normal value on the basis of cost of production. The Authority, however, notes that normal value under the Act *supra* has been defined as the prices in the domestic market of the exporting country. It would, therefore, be appropriate, as

discussed in the paras relating to Avenor Inc. Also, to determine dumping based on the normal value available for Balakhana. Further, as discussed in detail in the para relating to final findings, these two exporters have furnished price undertaking and the same has been accepted by the Authority, no specific duty has been recommended by the Authority against these exporters. The Authority has determined export price on the basis of claims made by these exporters, which were also verified by the Authority. Since the exporters furnished ex-works export price, the same has been relied upon.

16. **PRICE UNDERTAKING:** Solikams and Kondoponga have offered price undertaking to the Authority, through their respective agents. The Authority considers it appropriate to allow the said exporters to clear the goods in terms of said undertaking so long their c&f prices are not below the prices mentioned below:

(Rs. per MT)

a) JSC Solikamskprom	20280
b) Kondoponga Pulp and Paper Mill	20280

17. **OTHER PRODUCERS FROM CANADA/USA/RUSSIA:** The Authority has not determined separate dumping margins in respect of the following exporters for the reasons set out below:

- a) **Alliance Forests Products Inc.:** The company claimed that it had sold in Indian market at fair market prices, maintained high quality standards and cannot be accused of dumping. The company further claimed that it has not exported any newsprint during the investigation period and therefore, has not furnished information requested by the Authority.

Authority's position:

The exporter did not furnish information requested by the Authority in the prescribed form and manner and, therefore, the claim of the exporter with regard to exports at fair price cannot be accepted. In case the exporter has not exported during the investigation period, it may request for review under Rule 22.

- b) **Kamsk Pulp and Paper Mills, Russia:** The company requested for its exclusion on the ground that it did not supply any newsprint in the investigation period.

Authority's position:

The Authority notes that since the exporter has not exported newsprint during the investigation period, it attracts Rule 22. The exporter may accordingly file request under Rule 22.

- c) **The Daishowa Inc.:** The company stated that selling price to Far East, South East Asia, Central and South America and China were at similar or lower than the export price to India. The aggregate export price of Daishowa to India during the investigation period was US \$ 612 21 pmt which compares to Canadian and US pricing. Daishowa's export price to India during the said period were not lower than the domestic prices and were marginally higher than shipments to other world markets.

Authority's position:

The Authority notes that Dalshowa Inc. has not furnished information, in the form and manner requested by the Authority, with regard to normal value. The exporter has merely furnished information with regard to the prices in North America.

- d) Finlay Forest Industries Inc.: Trans World Exports, New Delhi argued that Finlay Forest Industries Inc., Vancouver, Canada manufactures high bright newsprint and had not exported any newsprint to India. The exporter has not, therefore, dumped any material in India.

Authority's position:

The Authority notes that since the exporter has not exported newsprint during the investigation period, it attracts Rule 22.

- e) Price & Pierce: With regard to imports through Price & Pierce, some interested party(ies) have argued that the Authority has erroneously taken the normal value prevailing at the time of initiation i.e. December, 1996. The Authority has compared the normal value of Indian producers prevailing in December 1996 and compared it with the export price during the investigation period.

Authority's position:

The above argument is factually incorrect, as the Authority has not taken normal value prevailing at the time of initiation in the preliminary findings for any exporter, including Price & Pierce. The Authority has not determined separate dumping margin in case of Universal Paper Export Company, Canada, Price & Piece, USA and Price & Piece, Singapore, as they are not manufacturers of newsprint and have exported newsprint produced by other producers.

- f) Corner Brook: The company claimed that it has not directly exported newsprint to India, nor the company has furnished any response directly to the Authority.

Authority's position:

Price & Piece furnished information with regard to normal value and export price, which relates to Corner Brook. The Authority, however, found that the company has not furnished essential and sufficient information with regard to its normal value and, therefore, separate dumping margin cannot be determined.

- g) Abitibi-Consolidated Inc.: The company claimed that with effect from 30.5.1997, Stone Consolidated and Abitibi have merged and a new company called Abitibi-Consolidated Inc. has been formed. The new company has not exported any newsprint to India during the investigation period. Therefore, exports from the new company should not be subject to any anti-dumping duty. The exporter comes under the category of new shipper and, therefore, should be reviewed under Rule 22.

The exporter, however, after disclosure of essential facts argued that even though the company came into existence on 30.5.1997, it should be treated as an exporter of newsprint to India during the investigation period, since the new company is composed of two erstwhile companies which had furnished information to the Authority. The exporter requested that the Authority should recommend a single anti-dumping duty on this company by combining the details contained in the individual responses.

Authority's position:

With regard to the claim made by Abitibi Consolidated Inc. for separate duty to be made applicable to them, the Authority notes that initially request was made by the company

average basis". However, the weighted average normal values and export prices have been worked for each of the month in the investigation period. The Authority has done comparison on this basis in view of significant decline in both the normal value and export price during the investigation period. It was noted by the Authority that there were very high sales volumes in some month whereas there were no exports to India in some other month. For instance, Stone Consolidated has not exported to India during the months of April and Oct., 1996. Determination of normal value on the basis of weighted average of normal values for the whole of the investigation period in this case and comparison of the same with export price (which represents export price for the sales made in only five out of seven months) would be inappropriate, unfair and could even be misleading. In a situation where there are exports to India only in one month in the investigation period, say Oct., 1996, and the prices declined in the investigation period, as in the present case, the results drawn using weighted average basis for comparison may be quite misleading and may show dumping whereas there may not be any dumping. Converse is also true. Since there are no exports to India in case of Stone Consolidated and Avenor in some of the months in the investigation period, the comparison on the basis of month-wise averages is more appropriate than a single average for the entire investigation period. It would also be inappropriate to adopt different comparison methods for different exporters. Moreover, it has not been demonstrated by any interested party(ies) how the comparison of normal value with export price on month-to-month basis has resulted in distortions, if any, in the comparison.

19. The dumping margin in respect of individual exporters are as under:

S No	Name of exporter	Dumping margin (% of export price)
A.	<u>Exports from Canada</u>	
	a) Stone Consolidated	23.85
	b) Abitibi-Price Inc.,	6.45
	c) Abitibi Consolidated Inc.	23.85
	d) Avenor Maritimes Inc.	20.44
B.	<u>Exports from USA</u>	
	a) Abitibi-Price Inc.,	36.34
C.	<u>In case of Russia</u>	
	a) JSC "Volga" (Balakhana Paper Mills)	15.88

F. INJURY

20. The views expressed by various interested parties on injury to the domestic industry and the observations of the Authority are as under:

Arguments raised:

- a) The prices of newsprint in India of the Indian industry were higher than the import prices from the subject countries during the investigation period. In such circumstances, there can be no question of injury.

Authority's position:

The argument is conceptually and legally untenable, as the very contention advanced by the importers substantiates the argument of the domestic industry that it was forced to reduce its prices because of cheaper imports available from the subject countries, thus resulting into a situation of price undercutting in the Indian market. This also establishes that the injury to the domestic industry was caused due to dumping.

Arguments raised:

- b) There will be no material injury to the domestic industry if it has made profits and if it does not produce newsprint equal to the demand of newsprint in the country.

Authority's position:

The above arguments are not supported by law. Para (iv) of annexure II clearly states that decline in profits is also an indicator of injury. Therefore, there may be injury to the domestic industry even in a situation when the domestic industry has made profits. In the instant case, however, the domestic industry has incurred losses in the investigation period from a situation of profits before the investigation period, as brought out by the Authority in the preliminary findings. Further, there is no provision to suggest that the domestic industry should be in a position to meet the demand of the country before it can seek any relief under the law. The conditions with regard to standing of a petitioner to file a petition are well laid down in the rules. In so far as the demand-supply situation is concerned, the domestic producer could have capacity excess or short of the demand. The argument that no duty can be imposed for the quantity imported, which is in excess of the newsprint produced in the country is unsupported by law, as the purpose of anti dumping is not to impose any quantitative restrictions but to ensure a situation of fair competition with regard to prices alone.

Arguments raised:

- c) Express Publications argued that Indian producers increased the prices in line with import prices and did not reduce the prices when the international prices came down. The company furnished a comparison of imported newsprint prices C&F Indian ports and ex-Indian mill prices, which shows as under to establish its argument:-

Period	Canadian Prices C&F	(Rs. Per MT)		
		Price charged by the Indian producers		
		HNL	TNPL	MPM
Apr-June, 1995	27606	27000	27925	27875
Jul.-Sep., 1995	31496	27000	27925	27875
Oct.-Dec., 1995	34342	27000	27925	27925
Jan.-Mar., 1996	30915	27000	27925	27875
Apr.-Jun., 1996	24535	27000	27925	27875
Jul.-Sep., 1996	20735	23000	24210	23000
Oct.-Dec., 1996	17208	21000	21820	21800

Authority's position:

The Authority observes from the above that the contention of the interested parties that Indian producers increased the prices in line with import prices and did not reduce the prices is not established. It rather establishes that the domestic industry was forced to reduce its prices far lower than its fair selling price in view of declining import prices, thus resulting in a situation of price undercutting in the Indian market. The table also indicates that the Canadian prices were coming down even though the Indian prices were constant during the period Apr, 1995-June, 1996.

Arguments raised:

- d) Production of newsprint requires bamboo, eucalyptus wood and salai wood. Except bamboo there is prohibition on felling of wood of any type in India w.e.f. 12.12.96. In view of this, the Authority should investigate how the domestic industry would cater to its requirement of raw materials.

Authority's position:

Anti dumping provisions under the Indian requires that the duty shall be restricted to the amount which is found sufficient to remove the injury to the domestic industry. Injury on account of factors other than dumping (including the increase in the cost of production due to non-availability of raw-material), are not considered for determination of the quantum of anti dumping duties. Moreover, an interested party can approach the Authority for a review in case it is shown that the circumstances have changed substantially after the period of investigation.

Arguments raised:

- e) The Authority took into account the fall in profits or losses by Indian mills without going into a justifiability of the prices charged by the domestic industry before the dumping period. The Authority has not compared the price quoted by the exporters to India and other world market. Without such comparison the conclusion that the exporters price has injured the Indian newsprint industry is not fair.

Authority's position:

It is not within the legislative framework of anti-dumping laws nor is it the purpose of present investigations to investigate the justifiability of prices charged by the domestic industry, prior to the investigation period

Arguments raised:

- f) The preliminary findings does not address whether the Indian newsprint market is increasing, decreasing or remaining constant. An increased demand for imports in a growing market cannot be considered an indicative of injury being suffered by domestic industry from imports.

The fall in the selling prices of the domestic industry is from the peak prices not from the normal prices

The petitioner makes an unsupported statement that some mills in India have suspended production because of dumping. Without further information and analysis, it is not possible to link the same with dumping.

The purchasers did not depend on Indian mills for their source of supply and chose to import from a foreign reliable supplier, in view of reliability of the exporters.

Authority's position:

The purpose of anti dumping duties is not to restrict the imports from any particular source. The consumers are still free to chose their source for supplies. The argument with regard to increased demand of newsprint is also without merit as the Authority has given its finding with regard to the changes in the market share.

- g) In view of petitioners' view that despite a reduction in selling prices by domestic industry, sales were still being lost to imports, the possibility that the injury was being caused by factors other than dumping cannot be ruled out. Examples of such factors include quality, differences, reliability, timeliness and dependability of supply.

Authority's position:

The argument is presumptive. As brought out later in these findings, there is enough evidence to indicate that the preference to the newsprint imported from the subject countries was because of the price and not other factors

FINDING OF AUTHORITY ON INJURY TO THE DOMESTIC INDUSTRY:

21. The factual information mentioned by the Authority in the preliminary findings with regard to the injury to the domestic industry and various economic indicators affecting the domestic industry has not been disputed by any party. A number of interested parties have advanced arguments justifying the changes in the parameters relating to imports, market share, and factors affecting the domestic industry. The Authority observes that the analysis has to be done within the framework of anti-dumping provisions. Annexure II to the Rules states as under:

"a determination of injury shall involve an objective examination of both (a) the volume of the dumped imports and the effect of the dumped imports on the prices in the domestic market for like article and (b) the consequent impact of these imports on the domestic producers of such products."

The Rules further provides that

"The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including"

It is evident from the above that the reasons for the behaviour have to be looked into to establish whether the injury to the domestic industry has been caused by the dumped imports. The Authority further notes that the Authority is required to examine all factors, which are considered relevant, and, therefore, any factor which is not considered as relevant may be ignored.

22. In view of the above, the Authority analysed the injury to the domestic industry for these final findings. In addition to the details brought out in the preliminary findings, the following details are being relied upon to hold that material injury has been caused to the domestic industry:

Market share of imports from the subject countries in the total imports and compared to consumption in India were as follows:

- i) Market share in total imports: Market share of imports of newsprint from the subject countries in comparison to total imports of newsprint in India has been as follows:

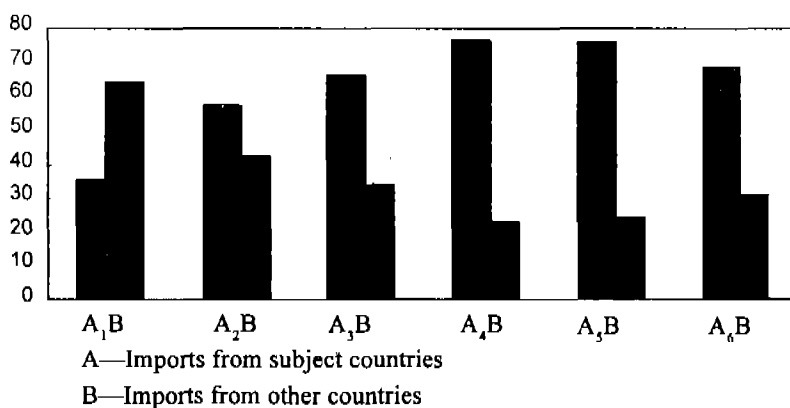
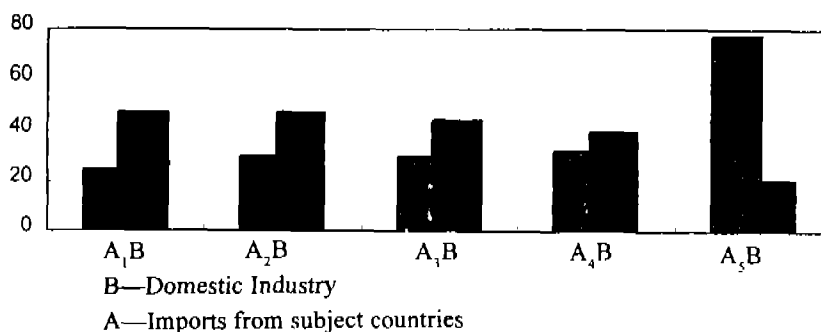


Figure 1 : Trend of share of subject countries in total imports

The Authority notes that market share of imports from the subject countries in total imports of newsprint in India increased significantly. There is distinct evidence to suggest that importers switched to these countries.

- ii) Market share in total demand: Market share of imports of newsprint from the subject countries in comparison to consumption of newsprint in India has been as follows:



1 - 1992-93, 2 - 93-94, 3 - 94-95, 4 - 95-96, 5 - POI

Figure 2 - Trend of market share of domestic industry and subject countries

The Authority notes that the market share of subject countries in the total imports and total consumption in India has increased significantly in case of imports from Russia

- 23 The argument of the interested parties that the demand of newsprint has increased and the same is the reason for increase in the imports in India is irrelevant, as the Authority has analysed imports from the subject countries, both in absolute terms and in relation to production/consumption of newsprint in India. It may be appreciated that all parameters relating to imports and domestic industry need not reflect injury to the domestic industry and even a single parameter, such as price effects, may be sufficient to establish injury to the domestic industry.
24. While analysing the injury to the domestic industry, the Authority is not required to assess the reasons for the changes in the indices. The reasons for the changes have to be looked into while establishing causal link between dumping and injury. Arguments raised by the interested parties with regard to the production, capacity utilisation and sales in absolute terms relate to the reasons for the increase or decrease in the indices. None of the interested parties has, however, disputed the preliminary findings in so far as the observation of the Authority on these indices are concerned. The preliminary findings with regard to production, capacity utilisation and sales in absolute terms are, therefore, confirmed.
- 25 Price undercutting and price suppression.
A comparison of average export prices from the three countries and the net sales realisation of the domestic industry (excluding Nepa) shows as follows:

Period	Average landed price (Rs. pmt) (a)	Net Sales** Realisation (Rs. pmt) (b)	Difference (Rs. pmt) (b - a)
1994-95	15615	20119	4504
1995-96	28709	27556	-1153
<u>1996-97</u>			
April, '96	28740	27906	- 803
May, '96	26207	27722	1515
June, '96	23984	27559	3575
July, '96	24629	25817	1188
Aug., '96	21945	22192	247
Sept., '96	21758	21955	197
Oct., '96	21458	21137	- 321
Average	23685	25132	1447

** without considering Nepa, i.e., sales realisations of TNPL, HNL and MPM only.

26. The above comparison of average landed prices from the three countries and the net sales realisation of the domestic industry (excluding Nepa) shown above establish that the exports from the subject countries were undercutting the prices of the domestic industry to the extent of 6.11% and further suppressed the selling prices of the domestic industry in the Indian market.
27. In view of the above, the Authority notes that the exports from the subject countries resulted in price undercutting and price suppression towards the end of the investigation period to such an extent that the exporters started exporting newsprint to India at prices below their own cost of production, resulting in losses to them. Further, the price depression for the domestic industry was to such an extent that it was forced to sell newsprint at prices significantly lower than its cost of production, resulting in financial losses. The Authority further notes that the imports from the subject countries resulted in price undercutting and price depression to such an extent that some of the exporters in Canada started exporting to India at prices below cost of production resulting in financial losses to them in the quarter 4, 1996.
28. Arguments have been advanced about the quality of newsprint produced by Nepa. None of the interested parties has, however, demonstrated the impact of quality of newsprint produced by Nepa and no price adjustment, whatsoever, has been claimed by any interested parties. It is however, found that the sales realisations of Nepa are significantly lower than the sales realisations of the remaining three companies comprising domestic industry. It may be concluded that there are other factors also affecting the sales realisations of Nepa. The Authority has therefore, ignored the cost of production of Nepa while arriving at the fair selling price for the domestic industry.

29. An analysis of circulation figures of Express Publications between 1990-96 shows the following:

Year	Newsprint Price	Copies (Nos.)	Price Rs.	Net price after commission (Rs)
Apr-June, 95	27606	267137	2.25	1.74
Jul-Sep., 95	31496	263054	2.25	1.74
Oct-Dec, 95	34342	263054	2.25	1.74
Apr-June, 96	24535	274011	2.25	1.74
Jul-Sept, 96	20735	274011	2.25	1.74
Oct-Dec., 96	17208	284112	2.25	1.74
		(1 50 Bangalore)		1 16

The Authority notes that the newspaper prices are inelastic to the cost of newsprint, as the same remained at Rs. 2.25 per copy even when the price of the imported newsprint ranged from Rs. 34342 pmt to Rs. 17208 pmt. The Authority concludes that imposition of anti-dumping duties, which is necessary to prevent injury to the domestic industry, on exports from the subject countries will not result in serious implications on the newspapers, particularly when imports from other countries, supplies from Indian producers and imports from the subject countries at fair prices are not proposed to be restricted by these measures.

G. CAUSAL LINK.

30. The views expressed by various interested parties and the observations of the Authority are as under:

Arguments raised:

- a) The Authority has not separated the injury, if any, to the domestic industry arising as a result of the withdrawal of the quota restriction of 2:1, and therefore, the causal link between dumping and injury has been perfunctory

Authority's position:

The Authority appreciates that withdrawal of the quota restriction of 2:1 might have resulted in increase in imports in absolute terms. However, the findings of the Authority on injury to the domestic industry and causal link thereof with dumping is not based on increase in the imports in absolute terms. As discussed in detail in the para relating to injury, market share of imports from the subject countries increased in relation to total imports of newsprint in India. Further, the findings of causal link are based on the effect of these imports on the prices of newsprint in the Indian market. The findings of the Authority with regard to price realisation, price undercutting are relied upon while holding that injury to the domestic industry has been caused by the dumped imports

Arguments raised:

- b) Rule 5(2) with regard to initiation of investigation states that the application shall comprise of evidence with regard to dumping, injury, a causal link. The Rule further states that the application shall contain evidence with regard to injury and causal link "where applicable".

Authority's position:

The Authority is required to give a finding with regard to the injury to the domestic industry and causal link between dumping and injury in case of imports of specified country, and accordingly the Authority has given its findings on injury to the domestic industry and causal link between dumping and injury.

- c) The case of petitioners themselves is that "dumping of newsprint, coupled with the fall in the international prices, has injured the Indian industry". It is thus evident that dumping alone has not caused injury to the industry. It is the fall in the international prices which has caused the injury. Levy of anti-dumping duty will make foreign supplier wary of selling in Indian market. They will artificially increase their prices. The imposition will not be in the public interest.

There is no evidence in the preliminary findings which links the lost sales directly to imports from the subject countries. With regard to the volume of dumped imports, the Notification does not identify individual import levels from each of the named countries. In view of the criteria with regard to de-minimis volume of dumped imports, the Authority should determine the level of imports from Canada and in case the same is found lower than 3%, the Authority has a WTO obligation to terminate investigation against Canada.

Authority's position:

With regard to the volume of dumped imports, the same are above de-minimis limits, as brought out in the para relating to injury. With regard to the factors other than dumping causing injury to the domestic industry, the Authority holds that the injury to the domestic industry has been restricted by considering optimum cost of production and allowing fair return thereon. The Authority notes that the lesser duty provision in Indian legislation (by virtue of which it is obligatory on the part of the Authority to recommend a duty lower than the dumping margin, if found sufficient to remove injury to the domestic industry and which is not an obligation either in GATT agreement or in the anti-dumping legislation in some countries) takes care of the other problems being faced by the domestic industry. In so far as the injury to Nepa because of its inability to fetch the price which the other constituents of domestic industry are fetching, the Authority has not included the cost of production of Nepa while arriving at the cost of production and fair selling price. The injury to Nepa because of other factors is, therefore, not considered.

I. FINAL FINDINGS

31. The Authority, after considering the foregoing, concludes:

- a) Newsprint originating in or exported from USA, Canada and Russia has been exported to India below its normal value;
- b) the domestic industry has suffered material injury;
- c) the injury has been caused to the domestic industry by the exports originating in or exported from USA, Canada and Russia.

32. The Authority confirms the preliminary findings with regard to imposition of Anti-dumping duty and recommends imposition of definitive anti-dumping duties on all imports of newsprint originating in or exported from the subject countries. The duty shall be the difference between the reference prices mentioned in column 2 and the landed value of imports, except in case of M/s JSC Solikamskprom and Kondoponga Pulp and Paper Mill.

33. In case of M/s JSC Solikamskprom and Kondoponga Pulp and Paper Mill, no anti-dumping duty shall be collected, as the Authority has accepted price undertaking from these exporters in accordance with Rule 14. However, in case any exports are made by the said exporters below the prices mentioned in para no. 16 relating to dumping above, anti-dumping duty as applicable to any other exporter from Russia, shall be chargeable on such exports.

- 34 Landed value of imports for the purpose shall be the assessable value as determined by the customs under the Customs Act, 1962 and the prevailing level of Basic Customs Duty at the time of clearance.

Sl. No.	Name of the Exporter (1)	Reference Price for calculation of applicable duties (Rs. per MT) (2)
A.	<u>Exports from Canada</u> 1. Stone Consolidated Corpn. 2. Abitibi-Price Inc., 3. Abitibi Consolidated Inc. 4. Avenor Maritimes Inc. 5. Any other exporter	26696 25786 26696 26642 26696
B.	<u>Exports from USA</u> 1. Abitibi-Price Inc., 2. Any other exporter	26696 26696
C.	<u>Exports from Russia</u> 1. JSC "Volga" (Balakhana Paper Mills) 2. Any other exporter	22958 22958

- 35 Subject to above, the Authority confirms the preliminary findings dated 11.6.1997.
36. An appeal against this order shall lie to the Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal in accordance with the Act supra.

RATHI VINAY JHA, Designated Authority

